Page No.1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २०वां दिवस [संख्या १४



**शनिवार, दिनांक १६ मार्च, १९६३**

विधान सभा की बैठक म.पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

**भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री जयनारायण व्यास के निधन पर श्रद्धांजलियां**

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री):** माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि सदन में माननीय सदस्यों को मालूम है परसों शाम को राजस्थान के वयोवृद्ध, राजस्थान में जन-जागृति पैदा करने के स्तम्भ, जिनका जीवन राजस्थान को आगे बढाने, अंग्रेजी सरकार और एकतंत्री शासन के विरुद्ध सदैव संघर्ष करने से भरा हुआ था, उनका देहावसान हो गया। श्री जयनारायणजी व्यास से मेरा करीब सन् १९४४ से निकट का सम्पर्क रहा है और जब कभी उनसे बात करने का, जब हम आजाद नहीं हुए थे तब और उसके बाद भी, अवसर प्राप्त हुआ तो उनके दिल में हमेशा देश-प्रेम की भावना प्रज्ज्वलित रहती थी। श्री व्यासजी अखिल भारतीय स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेन्स के जनरल सेक्रेटरी रहे। न सिर्फ जोधपुर में या राजस्थान में, बल्कि सारे भारतवर्ष में उन्होंने रियासती जनता की जन-जागृति में विशेष तौर से अपना हिस्सा दिया। राजस्थान बनने के पूर्व जोधपुर में वे प्रधान मंत्री के पद पर थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री के पद पर रह कर उन्होंने राजस्थान की सेवा की और उसके बाद राज्य सभा के अन्दर वे लगातार भारतवर्ष की सेवा में लगे हुए थे। व्यासजी की सबसे बडी विशेषता यह थी कि वे चाहे कैसी परिस्थिति हो, ब्लड प्रेशर से काफी अर्से से पीडित थे लेकिन हर परिस्थिति के अन्दर वे हंस-मुख रहने का, विनोद करने का बराबर प्रयत्न करते थे। यहां तक अभी जो उनकी आखिरी बीमारी थी उस बीमारी में भी होली के दिनों में जब वे जहां बीमार थे, बोलना भी मुश्किल था, तो हाथ से लिख कर भी बराबर लोगों से विनोद किया करते थे। वे कहा करते थे कि हमेशा रंग से होली खेलता रहा इस बार दवाइयों से होली खेल रहा हूं और इस हॉस्पिटल में होली की मेरी रातें बीत रही हैं। इससे अन्दाज होता है कि इस संघर्ष में भी अपने आपको एडजस्ट करने की कोशिश किया करते थे। हमेशा यह देखने में आया है कि उनके जीवन में जिस बात को वे उचित समझते थे उस बात को निर्भीकतापूर्वक, उस बात पर

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

हमेशा कायम रह कर उस बात पर ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाया करते थे। राजस्थान में आज यह दुर्भाग्य की बात है कि वे नहीं रहे और उनके द्वारा जो राजस्थान को और देश को प्रेरणा मिल सकती थी, सेवा हो सकती थी उससे राजस्थान को आज एक जबर्दस्त घाटा हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। पुराने व्यक्तियों का अनुभव, उनका जीवन, उनका त्याग–वह सब दूसरों के लिये एक प्रेरणा की वस्तु है। उनका व्यक्तिगत जीवन खुद का न होकर देश के लिये उन्होंने अपना जीवन बना लिया था।

व्यासजी लेखक थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में रुचि लेने वाले थे। उनका एक व्यापक जीवन था। हर क्षेत्र के अन्दर वे अपने विचारों से और अनुभवों से हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया करते थे। आज राजस्थान में उनका अभाव खटकने वाला अभाव है। मैं अपनी तरफ से उन दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले, उनके परिवार को शान्ति मिले उसके लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जयनारायण व्यास राजस्थान कांग्रेस के पुराने कर्णधारों में एक अग्रगण्य थे। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की उस समय स्थापना की जब देश का विभाजन तथा भारत की आजादी की कल्पना मात्र बहुत कम लोग कर सकते थे। वे उदात्त सिद्धान्त-वादी और परम निष्ठावान सुप्रसिद्ध कांग्रेस-जन थे। कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार को देख कर वे दुःखी थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी आवाज निर्भीकता से उठायी। वे कांग्रेस की ओर से राजस्थान के सफल मुख्य मंत्री रह चुके और उनके निधन के समय वे राज्य सभा के सदस्य थे। उनकी मृत्यु पर मैं अपने दल की ओर से तथा मेरी ओर से दुख प्रकट करता हूं और दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जयनारायणजी व्यास का निधन हम सब के लिए बहुत ही दुःख की बात है। विशेष तौर पर राजनैतिक क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उन सब के लिये व्यासजी का जीवन एक प्रेरणादायक जीवन है। जब से उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में काम किया उस समय से लेकर अब तक जितने संघर्ष उन्होंने राजनीति से लिये होंगे उतने संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति ने राजनीति में लिये हों, ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। वे एक इस प्रकार के व्यक्ति थे जिन्होंने साधनों की चिन्ता किये बिना संघर्ष करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोडी। राजनीतिज्ञों के समक्ष उनका जीवन का हर पहलू जिसमें सच्चाई, निर्भीकता और सिद्धान्तवादिता हर स्थान के ऊपर हर कार्य से जो मिलती है वह हम सब के लिए एक प्रकार से मार्ग-दर्शन है। किसी भी सही बात को कहने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। वे सिद्धान्तवादी थे और उस सिद्धान्त को अच्छी तरह से लागू करने में उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित हो, उन बाधाओं को अपने काबू में करने के लिए वह हर समय संघर्ष के लिए तैयार थे। मैं ऐसा समझता हूं कि हम आज के दिन उनके जीवन से स्फूर्ति लें तो हम किसी भी राज-नैतिक क्षेत्र में कार्य करते हों, निश्चित रूप से उस राजनीति के क्षेत्र में हम ईमानदारी से कार्य करने में आगे बढ सकेंगे।

(श्री भैरोंसिंह)
हम सब के लिये यह बहुत दुःख की बात है कि हम उनके जीवन-काल का और भी रसास्वादन करके भविष्य के अन्दर भी उस जीवित मूर्ति से प्रेरणा लेते किन्तु व्यासजी की जीवित मूर्ति आज चाहे हमारे बीच नहीं फिर भी उनकी कार्यवाहियां किसी भी रूप में जीवित मूर्ति से कम नहीं। मैं अपने दल की ओर से उनकी आत्मा को श्रद्धान्जली अर्पित करता हूं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को चिर शान्ति प्रदान करें।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज वह आत्मा जिसने राजस्थान की अनवरत रूप से सेवा की वे आज हमारे बीच नहीं रहे। इससे निःसन्देह राजस्थान को एक बहुत बडा अभाव हमेशा के लिये महसूस होता रहेगा। जहां तक व्यासजी के व्यक्तित्व का संबन्ध है उनका बहुत व्यापक व्यक्तित्व था। कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति के लिये वे बचपन से मेरे प्रेरणा-श्रोत रहे हैं। सन् १९४४-४५ में आजादी से पहले जब आजादी के लिये संघर्ष लडा जा रहा था, देशी रियासतों में जब दोहरी गुलामी में जनता पिस रही थी उस समय जब जनता संघर्ष में लगी हुई थी उस वक्त भरतपुर या दूसरे स्थानों पर जब जब भी उनसे मिलना हुआ हमने उनसे प्रेरणा प्राप्त की। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद् के वे अध्यक्ष थे। उन्होंने उस समय देशी रियासतों में संघर्ष लिया। यही नहीं उनके जीवन का राजनैतिक पहलू के अलावा सांस्कृतिक पहलू भी था। उनके द्वारा भागरा डान्स, तांडव नृत्य प्रस्तुत करते हुए मैंने खुद ने आखों से देखा है। जिस वक्त जयपुर में कांग्रेस का सेशन चल रहा था एक वॉलिन्टियर की हैसियत से उनके कमान्ड के नीचे काम करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। जब जब स्वयं सेवकों के समक्ष कोई मसला पैदा होता हम भाग कर उनके पास जाते। जिस सहृदयता व सरलता से उनका समाधान किया जाता वह आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। आज वह अमर आत्मा हमारे बीच में नहीं रही। उनका जीवन फक्कड जीवन था जिसने सब कुछ दुनिया के लिये चाहा, अपने लिये कुछ भी संचय नहीं किया। आज ऐसे अवसर पर जब कि वह अमर आत्मा हमारे बीच में नहीं है मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं, साथ ही साथ संतप्त परिवार के लिये ईश्वर धैर्य प्रदान करे, उसके लिये प्रार्थना करता हूं।

**श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभावों से पीडित राजस्थान के अन्दर से श्री व्यासजी का ऐसे समय चले जाना एक बहुत बडा अभाव पैदा हो गया जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभव दिखाई नहीं देती। जहां तक उनके राजनैतिक जीवन का बीकानेर के राजनैतिक कार्यकर्ताओं से संबन्ध था, उनका मुझसे जो संबन्ध था सन् ४५ से लेकर राजस्थान के मर्जर होने के वक्त तक राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जो प्रेरणा उनसे मिलती थी, जो हिदायतें उनसे मिलती थी और जो सफलता प्राप्त हुई—उस सब का श्रेय श्री जयनारायण व्यास को ही प्राप्त था।

आज भी राजस्थान के जो चोटी के राजनैतिक कार्यकर्ता हैं उनमें से अधिकांश को उनका सहयोग और उनका सहारा मिला है। आज भी वे अपने पीछे एक बडा शिष्य समूह छोड गये हैं। मैं आशा करता हूं कि वे भी उनके बताये हुए रास्ते पर चल कर राजस्थान का उत्थान कर सकेंगे। उनमें जो

# Page No.4



(श्री हरदत्तसिंह)

सबसे बड़ी चीज थी वह यह थी कि राजस्थान के वर्षों तक सर्वेसर्वा रहते हुए भी एक समय तो उनके लिये ऐसा निकला है जिसमें इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व होते हुए भी अपने पीछे रहने तक का मकान भी नहीं रख पाये। उनकी निस्पृहता, उनकी निस्वार्थ वृत्ति राजस्थान के राजनीतिज्ञों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। मैं आशा करता हूं कि उनके अनुरूप उनकी यादगार बनाने के लिये हमारे शासक वर्ग प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को वह शान्ति प्रदान करे और संतप्त परिवार को शान्ति प्रदान करे। मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री जयनारायण जी व्यास के निधन का समाचार जब हमने सुना तो बहुत ही अचानक इस प्रकार की घटना लगी जिसकी कल्पना दिमाग में कभी थी ही नहीं। अभी थोड़े दिन हुए उनसे मुलाकात का मौका मिला था। वे अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और विभिन्न लोगों से विचार-विनिमय कर रहे थे। उससे यह जाहिर होता था कि अभी भी उनकी लाइफ संघर्षमय कार्यक्रम साथ में लेकर चल रही है। जब एकाएक सूचना मिली तो बहुत ही बड़ा दुख: हमें इससे महसूस हुआ और वह इसलिये कि राजस्थान की समस्त राजनैतिक कार्यकर्ताओं को चाहे वह किसी भी दल में क्यों न हो व्यक्तिगत रूप से श्री जयनारायण व्यास के सम्पर्क में आने का मौका मिला है। मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्री जयनारायण व्यास को राजस्थान के राजनैतिक मंच पर वही स्थान प्राप्त है जो कि श्री सरदार बल्लभ भाई पटेल को भारतीय स्तर पर था। जिस कार्य का सम्पादन अखिल भारतीय स्तर पर श्री पटेल ने देशी राज्यों को समाप्त करके सारे भारतवर्ष का एकीकरण किया उसी प्रकार श्री जयनारायण व्यास का स्थान राजस्थान के इतिहास में है। दरअसल में श्री जयनारायण व्यास का जीवन राजस्थान के राजनैतिक संघर्षमय जीवन का अपने आप में एक इतिहास है और जिस प्रकार से उन्होंने एक संघर्षमय जीवन अपनी बाल्यावस्था से लेकर अन्तिम क्षण तक गुजारा है वह सब लोगों के लिये एक प्रेरणा का स्त्रोत रहा है और हमेशा रहेगा। चाहे उनके किन्हीं विचारों से हम सहमत न भी हों लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता जो उन्होंने अपने कन्विक्शन्स के बारे में, अपने विचारों के बारे में जो भी उनके थे, उन पर दृढ़ता से चलना और उसके साथ साथ दृढ़ता से चलते हुए अन्तिम मंजिल तक पहुंचने की जितनी शक्ति थी वैसी आम तौर पर कम में देखी जाती है। वे चाहें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल रहे हों या नहीं रहे हों, इसका तो आगे आने वाले इतिहासकार अन्दाज लगायेंगे; परन्तु यह हम सब के देखने की बात है कि जिस राजस्थान के अन्दर उन्होंने पुरानी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया, आम जनता को आन्दोलित किया, एकत्रित किया, उस राजस्थान को वे एक फलता-फूलता, एक बहुत प्रगतिशील, एक बहुत विकासोन्मुख राजस्थान के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिये वे अपने साथियों तक से लड़े भी, झगड़े भी, सब कुछ हुआ लेकिन व्यक्तिगत बातों में जो देखने को मिला, उसमें उनके सामने एक मात्र यह लक्ष्य रहा कि जिस कार्य के लिये हमने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पुरानी व्यवस्था से संघर्ष किया, वह हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिये और उनके मतानुसार जो भी उनके कोई सहयोगी रहे हों, चाहे उनसे भिन्न विचारों को रखने वाला रहा हो, वे इसके लिये उनसे भी कठोर संघर्ष करने में नहीं चूके। उनका एक मात्र लक्ष्य राजस्थान की जनता का हित था। वही उनका सर्वोपरि स्वार्थ था।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री जयनारायण व्यास नवयुवकों के लिये एक विशेष प्रेरणा के श्रोत रहे और हर तरह से उन्होंने राजस्थान के नव युवकों को संगठित करने का प्रयत्न किया, उनको प्रेरणा दी। राजस्थान के सभी नौजवान उनकी प्रेरणाओं से आन्दोलित रहे।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उस दिवंगत आत्मा के लिये शान्ति की कामना करता हुआ, अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और जो प्रस्ताव इस सम्बन्ध में मूव किया गया है उसका अनुमोदन करता हूं।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय व्यासजी की मृत्यु पर दुःख होना एक स्वाभाविक सी बात है। मैं समझता हूं कि पिछले ३० सालों में जिन पर्सेनेलिटीज ने, जिन सोशल फोर्सेज ने, जिन शक्तियों ने हमारे राजस्थान की हिस्ट्री को और हमारी जिन्दगी को शेप किया उनमें श्रद्धेय व्यासजी का नाम सबसे पहला है।

उनको मास्टरजी कहें, शेरे राजस्थान कहें या लोकनायक कहें, मैं समझता हूं हरेक व्यक्ति का, हरेक पार्टी का उनके साथ सम्बन्ध रहा। जिन लोगों को अपने जीवन में राजस्थान जन-आन्दोलन में हिस्सा लेने का मौका मिला उनको मालूम है कि श्रद्धेय व्यासजी की हृदय की विशालता, बुद्धिमत्ता, विजिलेन्स, हिम्मत, दिलेरी और सादगी की क्या कीमत रही। दिल्ली और वर्धा हमारे लिये, राजस्थान में राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों के लिये, दूर थी, पर श्रद्धेय व्यासजी हमारे लिये बहुत नजदीक थे। मैं समझता हूं कि उनके उज्ज्वल चरित्र और कर्त्तव्यनिष्ठा और हिम्मत की झलक हमें एक लैटर से मिलती है। अगर मैं उस लैटर के बारे में कहूं कि जो रेस्पोन्सिबल गवर्नमेन्ट बनी बीकानेर में तब स्वर्गीय महाराजा श्री गंगासिंहजी ने उनको लिखा था और वह लैटर और उसका उत्तर हिस्ट्री के महत्वपूर्ण डॉक्युमेन्ट के रूप में अमर रहेगा। जब व्यासजी का अखबार बन्द हो गया था पैसे की कमी के कारण, तब स्वर्गीय महाराजा श्री गंगासिहजी ने उनको एक पत्र लिखा कि चूंकि मैं एक राजपूत हूं, मैंने अपने प्रिडीसैसर्स से जो साहस और शान इनहेरिट की है, मैं नहीं चाहता कि जिस अपने शत्रु के हाथ में हथियार नहीं हों, उस पर वार करूं। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में हथियार रहे। इसके लिये मैं एक तीस हजार का चैक आपको भेज रहा हूं, आप अपना अखबार चलावें। उस वक्त व्यासजी ने उसका जवाब दिया जो मैं समझता हूं राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में एक अनुपम मिसाल के रूप में एक महत्वपूर्ण डॉक्युमेन्ट के रूप में रहेगा। उनके पत्र के शब्द ये थे कि अगर एक सत्याग्रही के पास सिन्सियर डिवोशन है, सिन्सियर डेडीकेशन और डिर्टमिनेशन है तो पैसे की उसे चिन्ता नहीं और किसी बात की परवाह नहीं।

आज वे हमारे बीच में नहीं हैं but it is for us to keep his spirit alive. His long and chequered life,

# Page No.6



(श्री केदार नाथ)

full of dedication and determination, is an inspiring history in itself not for us only but for generations to come.

**श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवा महल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दो पंक्तियां मैं भी कहना चाहता हूं।

श्रद्धेय व्यास जी हमारे राजस्थान की एक अनुपम हस्ती रहे हैं और कोई विशेष तो नहीं, लेकिन मेरा अपना भी कुछ उनसे संबंध रहा है। उनके विषय में श्रद्धांजलि अर्पित करना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे हृदय में तो दो पंक्तियां उत्पन्न हो रही हैं और उनके माध्यम से मैं अपनी भावना मात्र प्रकट करता हूं कि:

"समय ठहर, हम कैसे कर लें, यों जल्दी विश्वास,
जो जन मन में बसा
हुआ, वह नहीं रहा व्यास!"

केवल श्रद्धान्जलि की ये दो पंक्तियां व्यक्त करते हुए मैं उस दिवंगत आत्मा के लिये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उसे शान्ति दे और उनके शोक सन्तप्त परिवार को भी शान्ति दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, आज वास्तव में हम बड़े ही एक दु:खपूर्ण समय में यहां एकत्रित हुए हैं जब कि इस राजस्थान के एक लोकनायक, जो कि कल परसों ही तो थे और आज नहीं हैं। जब इस बात पर हम विचार करते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि यह शरीर आता है और कुछ कर जाता है? कहां से वह आता है? और कहां चला जाता है?

हमारा बेदान्त वाक्य भी कुछ इसी तरह से कहता है:

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

विज्ञान भी इसी प्रकार की कुछ बात कहता है और गणित भाषा में भी "under root minus one" वाली बात कही जाती है।

कुछ भी हो, यह शरीर आता है, यहां पनपता है और कुछ कार्य के लिये तत्पर होता है। यदि वह किसी विशाल ऊंचे कार्य को लक्ष्य करके चलता है, उदारतापूर्वक और हिम्मत से चलता है तो उसकी आत्मा सन्तुष्ट होती है और उस सन्तुष्टि के साथ ही वह चली जाती है।

मैं जब कल श्मशान में श्रद्धेय व्यासजी की देह को जलता हुआ देख रहा था तो यही बात विचार रहा था। आखिर सबको उसी स्थान पर एक न एक दिन पहुंचना पड़ता है। लेकिन किस तसल्ली के साथ वह व्यक्ति पहुंचता है वहां, केवल यही बात है देखने की और उसी से सारी बातों का अंकन किया जा सकता है। जिस समय उनकी शव-यात्रा कल जोधपुर में हो रही थी, ढोल बज रहे थे और गाड़ आगे चल रही थी, तो मुझे एक पंक्ति राजस्थानी कवियों की कविता की याद आती थी। पूरी पंक्ति तो याद नहीं है, लेकिन उसका आशय इस प्रकार है कि:

"ढोल बजते ही मैं, सखि आई थी और ढोल बजते ही मैं जाना चाहती हूं।"

अपने पति के विषय में एक नव विवाहिता कहती है एक कवि की भाषा में। तो यही बात आत्मा के विषय में है। और यहां व्यासजी के जीवन की एक मिसाल, उनका यह स्वरूप देखने में मिला कि जब वह आत्मा

(श्री उपाध्यक्ष)

भी ढोल बजते ही आयी एक दिन इस दुनियां में और अच्छे ऊंचे कार्य में तन्मय हो गई, एक क्रान्ति को देश में उत्पन्न करने को उठ खडी हुई और अन्त में सब प्रकार के संघर्ष, त्याग और बलिदान का पाठ आत्मा उदाहरण द्वारा पढाती हुई ढोल बाजते ही चली गई। संसार को आज यह महसूस हो रहा है कि जब व्यासजी आये होंगे संसार में तब भी घर में ढोल बजे होंगे और जब गये तब भी ढोल बजे, तो इससे बडा आदर उस दिव्य आत्मा के लिये और कुछ नहीं हो सकता, इससे बडी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से जब हम एक पुरानी गाथा सुनते हैं कि राजा हरिश्चन्द्र अतीतकाल में कहीं डोम के यहां भी भिक्षा मांगने की स्थिति में उतरे थे और सत्य के लिये सब प्रकार के संकट झेले और अंततोगत्वा ऊपर से विमान उतरा और स्वर्ग में बडे ही ठाठ से चले गये। कुछ ऐसे ही होते हैं ऐसे सत्य पर अडे रहने वाले लोग। व्यासजी के बारे में भी कुछ ऐसा ही लगा। जब व्यासजी उन फूलमालाओं में लदे हुए ढोलों की धमक के साथ चले तो उनकी आत्मा भी उसी तरह जैसे पुष्पित विमान द्वारा स्वर्गारोहण कर रही थी।

व्यासजी का संघर्षमय जीवन सबको विदित है। किस प्रकार के निधडक स्वतंत्रता के सेनानी थे वे और किस प्रकार के वे राजस्थानी प्रजातन्त्र के एक प्रकार से अग्रदूत थे। उनकी विगत आत्मा ने जैसे इस राजस्थान की सदियों से सोई हुई आत्मा ही को जगाया और उसे आगे बढने का नारा दिया। उनके शुद्ध चरित्र के विषय में तो कोई कुछ बात कही ही नहीं जा सकती कि कितना परम पवित्र उनका चरित्र था। कितनी उनकी निष्ठा उनके लक्ष्य में समाविष्ट थी। उनके विषय में अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि महाराजा गंगासिंह जी ने व्यासजी को जब उनकी माली हालत गिरी हुई थी, उनका पत्र नहीं चल रहा था, कुछ सहायता देने के लिये कहा, लेकिन उससे उन्होंने इन्कार कर दिया।

मेरी जानकारी में एक बात है इसी प्रकार की कि उन्हीं महाराजा गंगासिंह जी ने कर्नल डोनाल्ड फील्ड को एक पत्र व्यास जी के विषय में लिखा था, इसी प्रकार की माली हालत उनकी थी और शायद वे यहां से छोडकर बम्बई चले जाना चाहते थे, वे कलाकार तो थे ही, कला के मार्ग में प्रवृत्त हो जाना चाहते थे। तब गंगासिंहजी ने कर्नल डोनाल्ड फील्ड को लिखा कि इस प्रकार का चरित्रवान आदमी का राजनीतिज्ञ जीवन जीवित रखना हमारा धर्म है क्योंकि ऐसे ही लोग अन्ततोगत्वा राजाओं की राजाशाही जब समाप्त होने का समय आयेगा, इसी प्रकार के चरित्रवान और मनोबल वाले व्यक्ति आगे आयेंगे और उनके कन्धों पर राजाशाही का भार प्रजातन्त्र के रूप में जा सकेगा। यही बातें स्वयं भी एक व्यासजी का क्या व्यक्तित्व था इसका ज्वलंत प्रमाण है। इतना ही नहीं, कल ही देखा व्यास जी का शव उनके किराये के मकान से निकला, उनके खुद का मकान भी बनाने की उनको फुरसत नहीं मिली–यह हमारे लिए उदाहरण की बात है। सारे जीवन ही उन्होंने जिस बात की लौ ली उसी में खपा दिया। मुझे, और उनके जीवन के बारे में थोडा सा संकेत करके ही रह जाना है। बाकी तो उनका जो कुछ कार्य है वही हमारे सामने रह जाता है, वही प्रेरणा दायक है और उसी से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ सकते हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

१८ फरवरी, १८६६ में उनका जन्म हुआ। सन् १९२१ में मारवाडी हितकारी सभा के वे मंत्री चुने गये और सन् १९२७ में वे कांग्रेस में शामिल हुए और उसके पश्चात् देशी राज्य लोक परिषद् के प्रमुख नेता बने और सन् १९३६ से ४७ तक उसके महामंत्री भी रहे और सन् १९४८ में वे जोधपुर के प्रधान मंत्री बने थे। सन् १९५७ में वे कौंसिल आफ स्टेट्स में गये और सन् ६० में उन्हें दुबारा राज्य सभा में भेजा गया। इस प्रकार उन्होंने आज तक विभिन्न प्रकार से अपना जीवनयापन किया। यह जो उनका इतिहास है यह तो इतिहासज्ञों को तारीखवार लिखना है, लेकिन हमें जो सोचना है वह तो यही है कि किस प्रकार से लडते हुए स्वतंत्रता-संग्राम का वह सिपाही आखीर तक डटा रहा और सम्मानपूर्वक चला गया–हम भी सब यही आकांक्षा करें कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर इसी प्रकार अपनी अपनी लौ में मस्त कार्य करते हुए उसी सम्मान के साथ जा सकें। हम कभी कभी किसी सिद्धान्त पर अड जाते हैं, कहते हैं कि यह हमारा सिद्धान्त है। लेकिन सिद्धान्त विचार और व्यवहार से ही सिद्ध होता है। वह तो स्वयंसिद्ध अंत है। वह तो अपने ही सारे कार्य से, अपने ही सारे जीवन के अनुभव से सिद्ध होता है। जिस प्रकार से व्यास जी ने सिद्ध किया होगा। जिस प्रकार से अन्य और कई महापुरुषों ने सिद्ध किया होगा। तो सिद्धान्त की हठधर्मी के साथ हम न बहें बल्कि सिद्धान्त को टोहने की कोशिश करें। जिस तरह व्यास जी ने सारे जीवन पर अपने सारे अनुभवों के साथ उस सिद्धान्त को तोलने की कोशिश की होगी; उसको टोहने की कोशिश की होगी। कहने के लिये वे यहां नहीं हैं लेकिन वास्तव में उनकी त्यागमय जीवन की प्रेरणा स्रोत वन अविरल बह रही है जहां से हम हमेशा प्ररणा ले सकते हैं। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि के स्वरूप २ मिनट तक मौन खडे होने के लिए निवेदन करूंगा।

(माननीय सदस्य २ मिनट के लिये खडे रहे)

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि संवेदना का संदेश उनके परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाये और यह सदन उनके सम्मान में आधा घन्टे के लिए स्थगित कर दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष**: व्यासजी के संतप्त परिवार के सभी सदस्यों को इस सदन की हार्दिक संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अतः आज की कार्यवाही आधा घन्टे के लिये स्वर्गीय व्यासजी के सम्मान में स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ११ बज कर ३६ मिनट पर आधा घन्टे के लिए स्थगित की गयी)

(सदन की कार्यवाही पुनः १२.५ बजे प्रारम्भ हुई)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**आय-व्ययक, १९६३-६४ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद**

**श्री उपाध्यक्ष**: बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

(विराम)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा ।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने तीन बातों पर जोर दिया था। इस बजट के समर्थन में, पहले हमको यहां पर पालियामेन्टरी प्रोप्राइटी और हकों की रक्षा करनी चाहिए । दूसरे, मैंने, अनजान और भोलेपन की, आपके वित्त मंत्री की तारीफ कल इस बजट के सिलसिले में की थी और मैंने कहा था कि जब मैं तथ्यों को रखूंगा तो इन सब चीजों को, इन टैक्सेज को सपोर्ट करना पड़ेगा, और तीसरी बात पर मैंने जोर दिया था कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह उसके निमित्त मात्र हैं । और अब मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं ।

श्रीमन् , मैंने पहली बात पर जोर दिया था कल भी और आज भी जोर देता हूं कि इस मुल्क के इतिहास के अन्दर आज तक आप आजादी की लडाई को ले लें, गरीबी की लडाई को ले लें, इनके खिलाफ अगर किसी ने मोर्चा बांधा है तो वह कांग्रेस सरकार ने बांधा है । कांग्रेस सरकार आज भी किसी की महरबानी से इस देश में नहीं रहती, बल्कि जनता से वोट प्राप्त कर, अपने मेनीफेस्टो के जरिये रहती है और उस पर आज भी कृतसंकल्प है । इस देश में एक हमारी दुश्मन गरीबी थी, और दूसरे दुश्मन चीन ने पिछले साल हमारे देश पर हमला किया । ये दो दुश्मन हैं और इनके लिए कहा जा सकता है कि इन दोनों दुश्मनों का एक दूसरे से आपसी ताल्लुक है, एक दुश्मन का दूसरे दुश्मन से ताल्लुक है । तो एक हमारा दुश्मन गरीबी है और दूसरा दुश्मन वह है जो हमारी आजादी से खेलना चाहता है, हमारे देश पर जबरदस्ती आक्रमण करना चाहता है और हमारी इज्जत को लेना चाहता है । उससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम गरीबी के खिलाफ लडाई जारी रखें । इस भूमिका के अन्दर, इस सन्दर्भ के अन्दर मैंने कहा था कि पुरफरेब तखयुल इस बजट को रखने में काम लिया गया । मतलब यह कि चक्करदार ढंग से इसको घुमा फिरा कर कहा गया । अब मैं सीधी भाषा में इसको सपोर्ट करता हूं ।

श्रीमन्, इस ओवर ड्राफ्ट का पिछली मर्तबा कुछ वित्त मंत्री ने इशारा किया था : और क्योंकि ओहदानशीनी को कम दिन हुए थे, उस वक्त पूरी तरह से वे देख नहीं सके थे, इसलिए उन्होंने इशारा किया था । और हमारे वित्त मंत्री ने, उस ओवर ड्राफ्ट को लेकर जो पिछली हुकूमतें चल रही थीं उनकी तरफ सुखाडिया साहब का ध्यान दिलाया । यह ओवर ड्राफ्ट जो उस समय निकलता था, वह धीरे धीरे ग्यारह करोड का ओवर ड्राफ्ट हो गया । इतना ओवर ड्राफ्ट हुआ तो चिन्ता हुई । मैं आपको इसके विषय में एक अखबार में खबर १५-१-६२ को जो निकली है, वह पढ़ कर सुना देता हूं ...

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री) : १५-१-६२ ?

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** : जी हां, लिख लीजिये, १५-१-६२ । जल्दी जल्दी लिखिये :—

"At the same time the State Government failed to repay loan to the Centre to the extent of six crores 38 lacs. This caused a serious concern to the Centre which convened a meeting of the officials of the Finance Ministry and the Rajasthan Government and the Planning Commission."

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह राजस्थान गवर्नमेंट के लिए है,

"The meeting came to the conclusion that the recurring expenses of the Rajasthan Government were the resources of the old deficits run by the State Government which in turn were attributed to the inability to raise adequate resources within the State......"

प्रश्न यह है कि उन सब को बुलाया गया। इनको ही नहीं बल्कि ५ स्टेटें और थीं जिनको भी सेन्टर ने बुलाया था। उन पर भी ओवर ड्राफ्ट् थे, मगर उन पर इतने ऊंचे ओवर ड्राफ्ट नहीं थे। आपको यहां पर क्यों टैक्स लगाने पडते हैं, यह बात मैं आपको समझा रहा हूं। जब यह आपके सामने आया तो आपको चिन्ता हुई और आपने इसको इस तरह से तय किया कि १५ करोड का तो लोंग टर्म लोन लिया जाय और २० करोड का शार्ट टर्म लोन लिया जाय जिससे कि रिजर्व बैंक का ओवर ड्राफ्ट है उसका पेमेन्ट किया जावे और वह आपने लिया वह इस शर्त पर लिया; अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो माननीय मंत्रीजी मुझे ठीक सुधार दें क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी है उनको भी है। मेरे पास तो मेरी ही जानकारी है और वह मैं आपके सामने बता रहा हूं।

अब मैं यह बता रहा हूं कि यह टैक्स क्यों लगाये जा रहे हैं?

यह ३५ करोड रुपये का ऋण, १५ करोड लोंग टर्म और २० करोड शार्ट टर्म तीसरी पंच वर्षीय योजना में देने के वायदे पर मिला है। आपने यह तय किया कि ये रुपये तीसरी पंच वर्षीय योजना समाप्त होने पर दे दिये जावेंगे। आपने लोंग टर्म लोन जो १५ करोड के हैं उनको तो १० साल में देने का और २० करोड के लोन हैं उनको वापिस देने का वायदा सेन्ट्रल सरकार से जो किया उसमें अब सरकार के सामने यह समस्या है कि दो साल तो निकल गये और अब तीन साल बाकी रहे हैं। दो सालों में तो कुछ चुकाया नहीं गया, इसलिये अब २० करोड को ३ से डिवाइड करें तो मालूम होगा कि वह ६।। करोड के लगभग आते हैं। यह कर्जा एक साल में सरकार को देना है। अगर यह सब बात सरकार विधान सभा के सदस्यों को विश्वास में लेकर करें तो यह ३५ करोड के कर्जे की बात है इसमें जाया जा सकता है कि यह कर्ज किस तरह से हुआ। मगर आपने कर्ज किया है और अब आप टैक्स से इसको वसूल करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह ६० परसेन्ट रुपया जनता से लोन के रूप में वसूल किया जा रहा है। आज आप ३५ करोड के कर्जदार हैं और वह कर्जा इसी शर्त पर लिया गया है कि २० करोड आने वाले तीन वर्षों में अदा कर दिया जायगा और १५ करोड १० साल में। ये सब बातें जब मैंने अखबार में पढीं कि ६।। करोड हर साल राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल सरकार को देना है तो मेरे समझ में नहीं आया। ये बातें जो मैं यहां कह रहा हूं कोई इधर उधर की बातें नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी आंकडों में गलती हो तो माननीय मंत्री को मुझे सुधारने का अधिकार है ताकि सही बात का पता चले। यह जनता पर ६।। करोड का टैक्स साल दर साल लगेगा जो ३।। वर्षों तक चलता रहेगा।

(१२.०० म. प.)

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इस प्रकार का आपने सेन्ट्रल सरकार से वायदा किया है। यहां तक मेरी जानकारी है और मेरी जानकारी सही है। आपको ६।। करोड हर साल तीन सालों तक देना है।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री): अभी माननीय सदस्य ने जो फरमाया कि मैं उनका जवाब दूं और नहीं देता हूं तो इसके मायने यह होंगे कि जो बातें वे कह रहे हैं सोलह आने सच्च हैं। मैं इस वक्त उस बहस में नहीं पडना चाहता, लेकिन जब मेरा जवाब देने का समय आयेगा उस समय मैं पूरी व्याख्या करूंगा।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा**: मैं आपको कहूंगा कि आपको मेरी बात याद नहीं रही होगी। श्रीमन् मैंने यह नहीं कहा कि आप बहस में पड़ें। मैं यह चाहता हूं कि आप इसमें 'हां' या 'ना' कह दें। मैंने जो आंकडे रखे हैं, ये सही हैं या गलत? आखिर देश की उन्नति और अवनति के संबंध में तो हम भी समझते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): प्रश्न यह है कि वायदा सरकार पूरा करेगी अब न?

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा**: वायदे की पूर्ति पर तो जिन्दगी कायम है। चला जाय या नहीं, यह अलग बात है। कोई भी सरकार झूठा वायदा करके चल नहीं सकती और सेन्टर को धोखा देकर झूठा वायदा करके रुपया नहीं ले सकती।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: यह तो इन्टर्नल एडजस्टमेंट का सवाल है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा**: यह एडजस्टमेंट का तरीका भी आप बता दें और जब आप हिमायती पर आते हैं तो कई बातें सामने आ जाती हैं। मैं आपको इसके लिये आगाह कर देता हूं कि वे अपनी सफाई के लिये कितनी ही ताकत से सरकार की तरफ से जवाब दे दें, मगर यह सत्य है कि ३५ करोड के कर्ज के भार से राजस्थान दबा हुआ है और यह लोन इसी वायदे पर लिये गये हैं कि आने वाले तीन वर्षों में २० करोड रुपयों को देना होगा।

श्रीमन् ६।। करोड तीन साल तक बराबर खाली कर्जे में चुकाने हैं और इनको आपको टैक्सों के रूप में देना है, यह आपको सोच लेना चाहिये। इसमें ५ करोड वाली बात आपके सामने नहीं आई। कुछ लोगों का अन्दाजा है कि ५ करोड सरकार के लिये और १ करोड अपने लिये। आप बतावेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। आपने विधान सभा के सदस्यों को एक ऐसी स्थिति में लाकर खडा कर दिया है, हमें इसके लिये कुछ मालूम नहीं। आज विधान सभा के सदस्यों को मालूम भी न पडे, इस प्रकार का हाल डेमोक्रेसी में है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि २० करोड का कमिटमेंट करके हमारी सरकार चली आवे और इस संबंध में दूसरी सब जगह बडी बडी तकरीरें होती रहें और विधान सभा के सदस्यों को विधान सभा के चलाने वाले जानकारी तक न दें और हमें बगैर कान्फीडेन्स में लिये इस तरह के कार्य करके हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खडा कर दिया जाता है जिससे हम इधर उधर हिल नहीं सकते। इसमें हमारी सरकार का कोई दोष नहीं है। यह बजट बनाने वालों का दोष है और बजट बनाने वाले दूसरे हैं।

# Page No.12



(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री जी यह स्पष्ट शब्दों में कह तो दिया करते थे कि मैं तो बजट बनाता नहीं हूं मैं तो केवल हस्ताक्षर करता हूं बजट तो वे ही सरकारी अधिकारी बनाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो यहीं हैं, क्या कहना चाहिये आप तो कहने की इसमी भी हिम्मत नहीं करते कि मैं केवल हस्ताक्षर ही करता हूं। आप यह दिखाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। मैं और भी बातें कहूं। एक राजा था, उसको मंत्रियों की जरूरत थी। पुराने जमाने की बात है। उसने एडवर्टाइजमेंन्ट निकाला कि इन इन क्वालिफिकेशन्स के आदमियों की आवश्यकता है, वे आवें। एक आदमी ने कहा मुझे में इन क्वालिफिकेशन्स से दो क्वालिफिकेशन्स ज्यादा ही हैं। जिस समय राजा इंटरव्यू के लिये बैठा तो उसने यह सोचा कि इस व्यक्ति में दो क्वालिफिकेशन्स ज्यादा हैं, इसलिये इस व्यक्ति को बुलाया जाय और ले लिया जाए तो काम जल्दी खत्म हो जावेगा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपमें कौन से दो गुण अधिक हैं। तो उसने बताया कि एक तो मुझे अपनी कोई बात सूझती नहीं और दूसरा गुण यह है कि मैं किसी दूसरे की बात मानता नहीं।

यह डूंगरपुर की बात नहीं है किसी दूसरी जगह की है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : यह मेवाड़ की बात नहीं है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : राजा ने देखा कि ये दो गुण बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, इसलिये उसको मंत्रि-मण्डल में ले लिया। इस प्रकार की बात है कि आप सोचते नहीं और दूसरा कोई कहे तो उसकी मानते नहीं।

आप जिस समय इस पर बहस करें तो मैंने जो बातें सदन के सामने रखी हैं कि ३५ करोड रुपये आपने कर्जा चुकाने के लिये लिये हैं, २० करोड शार्ट टर्म लोन और १० करोड लोंग टर्म लोन, वह सही है या नहीं। आपने २० करोड रुपये शार्ट टर्म लोन के लिये हैं वह आपको तीन सालों में चुकाना है या नहीं, यह आप बतावें। इसका मतलब यह होगा कि ६।। करोड सालों साल आपको इस कर्जे को अदा करना होगा। यह मैंने अखबार में पढा, उस समय मैं नहीं समझ पाया। उसके बाद १५-१-६२ को मुझको न्यूज पढने को मिली, उसका हैडिंग था, "Stricter check on plan......" यह हैडिंग मैंने पढा १५-१-६२ में। तो श्रीमान्, इस तरह से हम चाहते हैं, पहला कर्तव्य हमारा इस खतरे के वक्त यह होना चाहिये कि इस वक्त इस पर चैक लगायें। मैं बडे अदब से आपके वित्त मंत्री से कहूंगा कि यह काम ऐसा नहीं है। जब सेंटर को वित्त मंत्री की जरूरत पडी तो वित्त मंत्री षण्मुखम् चेट्टी को लाना पडा जो कांग्रेसी नहीं थे, देशमुख को लाना पडा जो कांग्रेसी नहीं, जब जब क्राइसेज आई, जब तक काम दिया रखा, जब क्राइसेज आई आवश्यकता हुई तो मुरारजी देसाई को रखा जो चीफ मिनिस्टर थे, बोम्बे जैसी चीफ मिनिस्ट्री को सेक्रीफाइस कराके लाना पडा। मैं समझता हूं कि आपके वित्त मंत्री का काम बडा इम्पोर्टेन्ट है। आज राजस्थान का बच्चा बच्चा, छोटा बडा, खडा पडा चिल्ला रहा है, स्ट्रीट स्ट्रीट से आवाज आ रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, इसे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ठीक करो, हमको सामाजिक न्याय दिलाओ या नहीं दिलाओ, पर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक करो। हम सबको इसके लिये लोगों ने यहां भेजा है, मैं उनकी आवाज को यहां रखता हूं। हमारे राजनैतिक पहलू से, हर पहलू से इसका वास्ता है। इसके लिये जो स्पष्ट-वादिता सदन की है वह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखूंगा। हमें टैक्सेज लगाने हैं, पर सदन को विश्वास में लेना चाहिये कि साढे छः करोड देना है, किस पर करेंगे। एक ही बात बतला दीजिये, शोर्ट टर्म लोन की। इसको कैसे देंगे? टैक्सेज कैसे लेंगे? इन टैक्सेज में उन टैक्सेज का क्या, गरीब टैक्सेज की चोरी नहीं करते, सदन को भी मान लेना चाहिये, यह मुख्य सिद्धांत है जो हमारी डेमोक्रेसी का है:

"no representation without taxation."

जिनको आप रिप्रेजेन्ट करते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, यह सही है। इस मान्यता को मानते हुए यह कहता हूं कि जिनको रिप्रेजेन्ट करते हैं वे टैक्स देते हैं। पर इस गरीबी की लड़ाई में, इस लड़ाई से फायदा उठाकर एक टैक्स लगाने वाले दूसरे टैक्सेज के जरिये गरीबी में और कर्जदारी में स्टेट को फंसाकर ३५ करोड जैसी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की कर्जदारी में हमें फंसा कर कहना चाहते हैं कि गरीबों की जमीन पर भी टैक्स लगा दिया जाय, हरएक पर टैक्स लगा दिया जाये। इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि सेंटर के बजट की तारीफ करूंगा कि ५० प्रतिशत किसान से लेने का फैसला है, पर मलहम भी लगाया है। ५ साल बाद किसान की कैपीटल फॉर्मेशन कर देंगे। तेरे घर में रुपया होगा। पर यहां मलहम नहीं कटाई ही कटाई है और उस पर नमक लगाने की और कमी है। मेरे पास मशीन नहीं, पर मैंने प्रोफेसर से समझने की मेहनत की है, आप इसे मान लें कि साढे तीन करोड के टैक्सेज हैं जिन्हें कि सवा दो करोड कहते हैं।

इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि अनाज पर टैक्स लगाया है, चेम्बर्स वगैरह का निकला है कि हमारे चारों तरफ टैक्सेज ऐसे नहीं हैं, इससे व्यापार में हानि होगी, मैं व्यापार की हानि की बात नहीं मानता। मैं यह जरूर मानता हूं कि टैक्सेज लगें, यह हमें देखना होगा; पर जवार बाजरा पर टैक्स लगाया है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि बोलने पर टैक्स लगादें अगर ज्यादा जलन है तो, पर खाने पर इस तरह टैक्स लगाना गलत है। यह टैक्स ज्वार, बाजरा पर टैक्स ज्यादा इसी तरफ ले जायगा। टैक्स तो कम आयेगा क्योंकि ये व्यापारी ऐसे लोग होते हैं जो आज तक आपको चकमा देते रहते हैं। मैं कल नत्थीसिंहजी की तकरीर बड़े गौर से सुन रहा था, फरमाया बाहर पशु ले जाते हैं उन पर टैक्स लगाते हैं, आदमी उन पर आ जाते हैं उन पर टैक्स नहीं लगाते। आदमी तो रोज आते हैं, देहली में आते हैं, मैं समझा नहीं कि किस तरह के टैक्स की बात करते थे। तो इस तरह वक्त हमारा नहीं लेना चाहिये। यहां हों तो उनसे गुजारिश करूं।

तीसरी बात यह है कि पशुओं पर टैक्स लगाया है पर गोश्त के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। चमड़े पर टैक्स है, दूध पर टैक्स है, हड्डी पर टैक्स है किसान के हर लमेह पर टैक्स है पर गोश्त के दुकानदार हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया है। तो इन तीनों टैक्सेज की आमदनी में साढे सात करोड कूंतता हूं।

Page No.14



(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। श्रीमन् मैं टैक्सेज का तो सुझाव नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं, पर मैं एक चीज रखना चाहता हूं। हमारे पास पैसा आता है, उसको किसानों पर, इन्डस्ट्रीज पर, इतनी प्रोफिसेन्सीज खोल रखी है, उनको देते हैं और लोक कल्याण की बातें खोल रखी हैं वह करते हैं, इन्ट्रेस्ट के ऊपर, ब्याज के ऊपर रुपया देते हैं, वहां देश को ऊंचा उठाने के लिये, मकान बनाने के लिये, तकाबी के रुपया देते हैं, उसका हमारा ब्याज बहुत कम आता है। हम सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट से जो कर्ज लेते हैं उसका ज्यादा ब्याज देते हैं। इसके साथ ही वसूली का ढंग भी बड़ा अजीब है। मोटर वाले मोटर के लिये उधार लेते हैं उनको कहते हैं मूल पहले दे दें फिर ब्याज वसूल किया जाता है। मकान बनाने के लिये लोन दिया तो लोन में कहते हैं कि पहल हमारा मूल आ जाए फिर ब्याज लेंगे, यह गलत है। इस तरह का कायदा नही होना चाहिये। राजस्थान की जनता से टैक्सेज के रूप में पैसा वसूल करें और इन्डस्ट्रीज और दूसरी फायदे की बातें हैं उनमें कर्ज देकर वसूलियां पीछे डालकर राजस्थान को कर्ज में फंसाते हैं, यह गलत है। वसूली की इतनी बड़ी मशीन दी है, फिर भी वसूली नहीं होती और आप हमारे राजस्थान को बराबर कर्ज में फंसाते जा रहे हैं। यह ब्याज का तरीका बदलें, दुगुना ब्याज हो, इसके साथ साथ या पहले ब्याज वसूल करना शुरू करें। इसके बाद महरबानी करके इस ब्याज से मैनेजमैन्ट कीजिए। सरकार की आमदनी है, उससे हमारा राजकाज चलना चाहिये और हमको टैक्सेज से बचाना चाहिये। जितने आपके प्राजेक्ट्स हैं; चम्बल है, पोंग है, राजस्थान केनाल है, आज क्या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट नहीं जानती कि इसका रिटर्न टेक अप पीरियड के बाद होगा तो ब्याज समेत इसका कर्जा आज ही हमारे सिर पर लादते हैं, यह ठीक नहीं। जैसे ५ स्टेट्स ने नहीं दिया है, मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि रहम करिये राजस्थान पर, आप राजस्थान को ३५ करोड के कर्ज में कैसे फंसा आये। जब ५ स्टेट्स ने कोई कर्ज नहीं दिया। आपने कैसे राजस्थान को फंसा दिया हमें। आप सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को नहीं कह सकते कि इनसे हमें रिटर्न आने लगेंगे तब ब्याज और कर्जा दोनों ही दे देंगे। अभी हमारी मजबूरी है। हम नहीं दे सकते हैं इस चीज को। हमारी मजबूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्‌जी, मैं यह कहूंगा कि मेरी पार्टी का टाइम रहता है। मेरी मेम्बरान से बातचीत हो गई है और मैं उनके भी विचार रख रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पैसा कैसे हम दें? पांच स्टेट्स ने इन्कार कर दिया कि हम नहीं देते। अखबार मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने सैन्टर से कोई कमिटमैन्ट नहीं किया। एक साहब से बात हो रही थी। कहने लगे कि और सजेस्ट करो। सजेस्ट यह करो कि ३५ करोड एक दफा दे दो। छूट रख कर मत दो। एक साल टैक्सेज दे देंगे। मैंने कहा पागलपन की बात है। कहने लगे कि दो फायदे होंगे। एक तो लोग मर जावगे, पोपुलेशन कम हो जावेगी और कर्जा भी चुक जावेगा। मैं इस बात का हामी नहीं हूं; मैं इसको सख्ती से रखता हूं कि सदन को विश्वास में लेना चाहिये। ३५ करोड लेना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हो तो इसके लिये स्पेशल सेशन बुलाना चाहिये। ४।। करोड के टैक्स रखे हैं। सेन्टर से पूछना होगा कि राजस्थान से जो कुछ लेना हो वह बता दो, उससे भी राजस्थान डेढ गुना देने के लिये तैयार है और यह बात निश्चित है। लेकिन हमको मालूम होना चाहिये कि हमें क्या करना है।

७४ लाख रुपया बोर्डर पर आर. ए. सी. के लिये खर्च करते हैं। उसकी जगह आप एक करोड रख दीजीये, लेकिन बहिनों और बेटियों को उठा कर ले जाते हैं वह बन्द होना चाहिये। चार बटालियन रख दीजिये, एक करोड नही, चार करोड रख दीजिये। लेकिन हमारी मां-बहिनों की इज्जत पर आयें दिन जो हमला होता है वह बन्द होना चाहिये। हर गांव के अन्दर सुरक्षा की पोस्ट होनी चाहिये। मैं भी अभी उधर जाकर आया हूं। इस प्रकार की सुरक्षा की गांव गांव के अन्दर पोस्टें होनी चाहियें कि जिससे बराबर देखती रहे। हर गांव की पूर्ण रूप से सुरक्षा होनी चाहिये। चौबीसों घंटे गांव की रक्षा होनी चाहिये। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। हम यहां बैठे आराम से रहते हैं, लेकिन हमें हमारे भाई-बहिनों और मां-बेटियों की हालत को देखते हुए चैन नहीं होता है। सैन्टर से चार बटालियन हम रखेंगे और उसका उत्तर-दायित्व हम उठावेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम से कुछ भी लें लेकिन डीफेन्स की जिम्मेदारी उनकी है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि चार बटालियन का खर्चा देते हैं लेकिन डीफेन्स की जिम्मेदारी सैन्टर की है, इसका ताल्लुक उनसे है। बुढिया भुनाने चली, टका है नहीं और यह दान और उनको दे दिया। चार बटालियन और रखें। हमें फक्र है। होम मिनिस्टर को मैं बधाई देता हूं। हमारे जवान लद्दाख में लडे और दुश्मन का बडा मुकाबला किया। हमें उन आदमियों का गर्व है। लेकिन यह जो तरीका है, महरबानी करिये, उनके नाम पर राजस्थान के वित्त मंत्री की मार्फत कहूंगा कि हमें इस तरह न फंसाते चलें कि हमारा दिवाला आउट हो जाय।

दो बातें मैंने आपके सामने रखीं। बचत की बात नहीं कहता। यह जो हकूमत का घोडा है, सर्विसेज का घोडा है इस पर चढने के लिये जिस दिन टांगों में ताकत होगी उस दिन बात होगी। मैं आप से कहता हूं कि दो चीजों से बचाइये।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : ये तो बूढे हो गये, इनकी टांगों में कहां दम है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : टांगों में दम है अभी तो।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** : आपका भूं भूं ठीक नहीं लगता है।

इसलिये मैं अर्ज करूं कि रुपयों की कटौती की बात नहीं की मैंने। मैंने तो आपसे वसूली की बात कही है। कर्ज दिया, पर वसूल करना है। आप इस बात का जवाब दें। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिन जिन शर्तों पर कर्जा दिया गया है, कोई कहे कि वहां का कर्जा छोड दें अभी व वसूली मत करो, लेकिन आप मत मानिये, हमारे कहने से भी मत मानिये, आप हमारे कहने से गलत बात मत करिये। यदि हमारी वसूली पूरी करते, इस पर ब्याज नहीं लगने देते तो आज इस हीन अवस्था के अन्दर राजस्थान खडा नहीं रहता। राजस्थान का इतिहास, कभी लिखा जावेगा तो इन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

३५ करोड रुपयों की चर्चा आवेगी। आपने दब्बू बन कर सेन्टर के अन्दर हमारा केस प्रोपरली नहीं रखा और न रखने से दिवाले को अन्दर भीतर खोंसते रहे। टैक्स आप लगाइये ४॥ करोड के, कोई एतराज नहीं, गरीबी से भी लडना चाहते हैं। लेकिन साथ में कहना चाहता हूं तीन टैक्सों के बारे में। वित्त मंत्रीजी आपने देख लिया होगा और सदन की इच्छा है। डेमोक्रेसी की प्रोप्राइटी के नाम पर अन्दर की सदन की एक आवाज लगी और लग रही है उस आवाज का पूरा असर पडना चाहिये। हम डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स हैं, इससे इन्कार नहीं करते हैं। यह भी कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के रूल का उन्हें एलर्जिक होना चाहिये पब्लिक ओपीनियन से और उसके माने यह हैं कि चार दिन से बहस हो रही है टैक्सेज को लेकर। यह कम्यूनिस्ट और स्वतंत्र पार्टी वाले एक रुपये के दो हिस्से हैं। एक ही पहलू हैं एक रुपये का। वे फरमाते हैं . . . . .

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): आपके कितने पहलू हैं वह तो बताइये ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा**: वह तो आपको वक्त मिलता रहता है, आप सब बताते रहते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: आपका पहलू तो कोई, मेरे खयाल से, रंग लाने वाला है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): जब जलता है यह पहलू तो वह पहलू भी जलने लगता है।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा**: आप सोकप्रूफ हो जाइये। दो मिनट में देता हूं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि श्रीमन्, इस सिलसिले में अजीब तरीका है। अपोजीशन के लीडर महोदय को मैं बधाई देता हूं कि वे अपनी बात साफ साफ कहते हैं, साफ साफ बात करते हैं। बढता हुआ जा रहा है, टांगे में बैठकर लगाम खींचना चाहते हैं घोडे की। घोडा आगे बढना चाहता है लेकिन लगाम खींचते ही वह पीछे पीछे हो जाये खुट खुट करके। इस तरह सारे देश को पीछे खींचना चाहते हैं। ये साफ बात करते हैं, उनसे कोई डर नहीं है। फ्यूडल, रिएक्शनरी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। हमने जनतन्त्र को इस तरह बांधा है कि एक गुलदस्ता है। सब तरह के फूल खिल सकते हैं इस गुलदस्ते में।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह**: यह गुलदस्ता जम्हूरियत का है। इस गुलदस्ते को बनाने में हमारा भी उतना ही हाथ है जितना आपका।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा**: इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें लगने का हक है। एक अर्से पहले इसने आपको लगाया था यह भी सही है।

एक और पार्टी है। ये कहते हैं कि प्लान और बढा दो। लडाई को जोरों से बढा दो यह है कम्यूनिस्ट पार्टी। आपका नक्शा मालूम हो गया जब चीन का आक्रमण हुआ। आपका नक्शा साफ हो गया। जनता ने एक दिमाग बनाकर चीनी हमले के खिलाफ एक रिजोलूशन पास किया। जनता में इसके लिये क्या स्थिति हुई, यह सब जानते हैं; लेकिन आपके (कम्यूनिस्ट पार्टी के) कारनामों को जनता अब अच्छी तरह से समझने लग गई है। जनता अच्छी

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)
तरह से समझती है। पहल जनता ने आपके आन्दोलनों को नहीं समझा, लेकिन चीनी आक्रमण से आपके बारे में उनको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया। चीनी आक्रमणकारी हैं, आपने मीटिंग करके नहीं बताया। आप जान बूझ कर उधेडते रहे। चीन के लिये आपका क्या दिमाग है, यह मालूम होता है। जानबूझ कर मीटिंग नहीं की। चीन की निन्दा करने के लिये मीटिंग नहीं की, मीटिंग करने के लिये कोई नोटिस नही निकला।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): यह गलत है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** (रायसिहनगर): This is wrong. We think, this is actually wrong.

**श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): यह बिल्कुल गलत है।

**श्री उपाध्यक्ष**: Order! Order!!

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : It is actually wrong. The Home Minister can verify that meeting was held in Alwar..........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं माननीय सदस्य को चेलेन्ज करता हूं कि गंगानगर जिला इसकी मिसाल है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order order!!

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है इस संबंध में उसको एक्सपन्ज किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please!

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** : मैंने कहा उससे इतना नाराज होने की बात नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order Please! Order !! The Chair is on its own legs.

There is nothing in his phraseology which would be expurged. It is just a strong expression of opinion and if any member has objection to it he will have his opportunity when he speaks; but one should be liberal enough to hear other members' point of view.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : Wrong facts have been placed before the House.

**श्री उपाध्यक्ष** : You will have a chance to refute them, and then you may express as strongly as the other side has.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : They have put wrong facts. On a Point of Order, Sir........

**श्री उपाध्यक्ष** : There is no point of order.

**श्री हरिराम चौहान** : हमें भी मौका दिया जाय जो गलत बयानी की गई है उसको डिफेण्ड करने का।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको मौका मिलेगा।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** : मैं सम्माननीय सदस्यगण से कहूंगा कि उनको मेरी कौनसी बात बुरी लगी ? मैंने तो सदन में इतना ही फरमाया.....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप तो फेफडे से बाहर निकल कर बोलिए।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अच्छा हो आप कांग्रेस से निकल कर जनसंघ में मिल जाइए क्योंकि उनका एसोसियेशन आपको काफी रहता है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : उससे भी ज्यादा दिमाग आपकी बातें सुनकर बिगडता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : (श्री ज्वालाप्रसाद से) आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

**श्री ज्वाला प्रसाद**: जितना समय उन्होंने लिया यह टाइम काट दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : जितना समय आप लेंगे कांग्रेस दल का कम हो जायगा।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा**: मैं बहुत धीरे से कहना चाहता हूं, मैंने सिर्फ यह कहा था कि जिस वक्त हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ, जब देश चारों तरफ से खडा हुआ, सारे विचारों के लोग खडे हो गए उस वक्त आपने किसी ने मीटिंग नहीं की।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा**: This is a wrong statement. सबसे ज्यादा मीटिंग कम्युनिस्ट पार्टी ने की गंगानगर जिले में।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मैं तो अजमेर जिले के लिए कह रहा हूं, दादा। आप टेबल ऑफ दी हाउस पर वह लिस्ट रख दें कि आपने कितनी मीटिंगें की हैं।

उस समय आपका जो तरीका रहा है वह तो इतिहास बताएगा। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि रामानन्द अग्रवाल से पहले मैं कम्युनिस्ट था।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बिद्र किया इसलिए निकाल दिए गए।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** : सबसे बडे कलीग थे उस वक्त के, उसकी गवाही पुराने कम्युनिस्ट श्री मथुरादासजी माथुर देंगे।

श्रीमन् मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वह समय था दुश्मन के बारे में कुछ कहने का और करने का। जिस समय मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था, मैंने देखा बाहर के देशों से ये बंधे हुए हैं तो मैं उनसे अलग निकल आया……

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप खरीद लिए गए।

**श्री योगेन्दनाथ हांडा** : और बाजार के चबूतरे पर चढ गए।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : श्रीमन् मैं जो बात कह रहा हूं वह कडवी लगती है तो माननीय सदस्यों को नीचे से मिर्ची लग जाती है। मैं कह रहा था कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड के अन्दर यह चाहते हैं कि डिसकॉण्टेण्ट-मेंट फैले और उससे जनता का जो इग्नोरेंस रहता है उससे बेजा फायदा उठाया जाय और जनता को भडकाया जाय। तो उन्होंने यह भी मौका नहीं छोडा। मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था, फिर भी कम्युनिस्ट भाइयों को यह बुरा लग रहा है। कम्युनिस्ट भाई समझ नहीं रहे हैं, ये लोग तो चाहते हैं कि जनता में असन्तोष पैदा हो और उससे हम फायदा उठावें। श्रीमन् इसलिए मैं कह रहा था इनसे होशियार रहने की जरूरत है। इन दिनों में वे और भी साफ हुए हैं जब कि कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए कि वे देश के लोगों को इन टैक्सेज को देने के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लिए तैयार करें, लेकिन वैसा नहीं किया। आज राजस्थान के ऊपर ३५ करोड का कर्जा है। आज इसकी हालत उस राजकुमार की तरह है जो नया नया गद्दी पर बैठा। जब लोग उसको यहां आकर कहने लगे कि लोग गरीबी के कारण भूखों मर रहे हैं तो उसने कहा भूख से क्यों तडप रहे हैं, अनाज नहीं है तो मिठाई खालें। आज भी उसी तरह की हालत है। किसान भूखा पडा है, उसको कहा जाता है कि मिठाई क्यों नहीं खा लेता। आज किसान की स्थिति यही हो रही है कि वह मिठाई क्यों नहीं खा लेते। आज जिस प्रकार की उसकी स्थिति है उसमें आप उससे कहते हैं कि मिठाई क्यों नहीं खा लेता।

आज हमारे यहां तीस पर्सेंट अनइकोनामिक होल्डिंग हैं। इनको कपडा-रोटी नहीं मिलता। आप १५) रु० ही किसान को दे दीजिए जब कि मजदूर यहां ४५) रु० माहवार लेता है, लेकिन वह ४५ नहीं मांगता सिर्फ १५) रु० मांगता है, वह उसको दे दें। आप उसका खेत ले लीजिए अन्न जो पैदा करता है वह ले लीजिए, वह देने को तैयार है, गांव ले लीजिए। आज स्थिति यह है कि उसको १५) रु० नहीं मिलता। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे यहां ३० पर्सेंट अनइकोनामिक होल्डिंग है, फिर भी आप उन पर भी टैक्स लगाने जा रहे हो। जो अपना पेट पालने के लिए, जिन्दा रहने के लिए, दिन रात खून पसीना एक करके अपने खेत सींचते हैं फिर भी कभी पाला पड जाय और उसका हरा भरा खेत नष्ट हो जाता है तो उसको उसका हर्जाना कौन देता है। उनकी ताकत नहीं कि वे इतने टैक्स दे सकें। आप इण्डस्ट्रीज पर टैक्स लगा दो, बन्द होगी तब पता चलेगा। किसान के घर चलो। आप कहते तो हैं कि हम तकावी देते हैं, कर्जा देते हैं। आप तकावी क्या उनको घिस्सा देते हैं। आपकी जो तकावी दी हुई है वह कभी गरीब किसान को नहीं मिलती। तकावी और कर्जा उन लोगों को मिलता है जो पहले से मालदार हैं, एक भी गरीब किसान को नहीं मिलती और टैक्स लगा रहे हैं उन गरीब किसानों पर। जो कर्जा आपने उनके लिए नहीं किया उसका भार डालते हैं उन गरीब किसानों पर।

अब मैं अन्त में एक बात और कह देना चाहता हूं जिसको सोचना हर माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है। हमने पिछली बार सेल्स टैक्स लगाया, उसकी सेंक्शन राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट द्वारा ली गई। हमने जो मंजूरी दी थी वह चार पर्सेंट की थी, यही एक्ट में हमने पास किया। उसके बाद, श्रीमन्, एक दिन उठते हैं, सरकार आपके वित्त मंत्री की तरफ से नोटिफिकेशन निकालती है ११ मई, १९६२ को। श्रीमन्, इसके अन्दर कहते हैं कि

"Receipt of the sale of all goods except only the goods specified in column no. ....in the list annexed shall be 5% on the taxable turn thereof....

पांच पर्सेंट की कोई सेंक्शन सदन की नहीं थी। ४ पर्सेंट का उन्होंने भी नोटिफिकेशन निकाला पर वसूल पांच किया। यह एक पर्सेंट जो जनता से आया है और जिस तरह से आया है उसे एक तरह से डाके की संज्ञा दी जानी चाहिए। इस राजस्थान की सरकार ने इस तरह से जनता के पैसे पर डाका डाला है। यह हुकूमत आज जनता पर डाके डालती है। जिस पैसे को

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)
कोई संक्शन नहीं, उसको टैक्स के द्वारा जनता से वसूल कर लिया जावे। यह कोई निरा टैक्स विदाउट टैक्सेशन की बात ही नहीं है, बल्कि यह बतलाता है कि जिस हुकूमत की मशीनरी पर लाखों रु० जनता की गाढी कमाई का खर्च किया जाता है, वह मशीनरी कैसी निकम्मी साबित हो रही है। कुछ स्थानों पर इस तरह की जोंकें लगी हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो हट नहीं रही है। आप नहीं हटा सकते इन जौंकों को, आप क्योंकि पंडित नहीं हैं इस सब्जेक्ट के। आप इन मामलों में जानते नहीं कुछ। आपके तो भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया जाता है। पर जो इस तरह के काम करते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं और चार की जगह पांच पर्सेंट वसूल कर लेते हैं वह गलत है। मैं इसको इस सदन की बेइज्जती मानता हूं। आज कोई भी तर्क इस के संबंध में मैं उचित नहीं मानता। आज जो यह लाये हैं इसमें लिखा है हम चार से ६ पर्सेंट करेंगे। आप इस तरह से चार को मानते हैं। पर वसूल पांच करते हैं। इस मशीनरी में सुधार होना ही चाहिए। इन गलतियों के लिए कौन जिम्मेदार है, उनको सामने लाया जाए।

श्रीमन्, एक टैक्स के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था। उसमें दो लाख टैक्स आया करता था। कॉम्प्रोमाइज हुआ करता था। जब कि हमारा अन्दाज था कि छः लाख होना चाहिए। हमारी बात हमारी सरकार ने मानी और आज छः लाख आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज भी मेरी सरकार मेरी बात सुनेगी।

पर साथ ही मैं यह कहूंगा कि करप्शन हमें मिटाना चाहिए। मैं करप्शन उसको कहता हूं कि यही नहीं कि हम ईमानदारी से काम करते हों, बल्कि यह होना चाहिए कि सच्चा विश्वास भी होना चाहिए। ईमानदारी से आपने काम किया, पर दूसरों को भी ऐसा लगना चाहिए। मिसाल दूं आपके लिए।

आप टैक्स लगाते हैं, सदन से स्वीकृति लेते हैं। बहुत सोच-समझ कर टैक्स लगाते हैं। पर इसके बाद आपके पास सेठिया आते हैं। बन्द कमरों में उनसे आपकी बातें होती हैं और आप टैक्स बाद में घटा देते हैं। कम लेते हैं, यह क्या बात है? वह पवित्र थाती थी आपके पास जो सदन ने आपको सौंपी, जनता ने सौंपी टैक्स के रूप में वसूल करने के लिए। पर आप सेठियों के चक्कर में आकर उस थाती के साथ खयानत करते हैं। उनसे आप लिखवाते हैं, रिप्रेजेन्टेशन मांगते हैं। उनमें से कइयों ने बोगस यूनियनें बना रखी हैं। इसी तरह का एक टैक्स था। आपने सबको बुलाया। तो क्या किया उस टैक्स का? उसे कम कर दिया। यह टैक्सों को इस तरह से कम करना ईमानदारी नहीं है, लोगों को नहीं लगती। आपकी ईमानदारी में शुबाह पैदा करता है। आप कम कैसे कर सकते हैं? क्या आपने पहले उसे सोच समझ कर नहीं लगाया था? आप पर्सुएशन से काम करते हैं और टैक्स कम करते हैं तो शुबाह होता है कि आपके कमरे के अन्दर आपने क्या किया। पता नहीं।

आपने बकरियों पर टैक्स लगाया नोटिफिकेशन निकाला कि २०) रु० एक बकरी की स्टेण्डर्ड कीमत समझी जावेगी। इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते कि

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

आपने सोजत के एक व्यापारी से इस बारे में बात की । अब टैक्स घटावेंगे तो गडबडी होगी, तो आपने इसके लिए रास्ता निकाला कि जो बकरी बाहर जावे उसकी तो २०) रु० कीमत रहेगी और कसाईखाने में जो आवे उसकी कीमत दस रुपया रखेंगे । आपके पास जादू है । जिसके जोर से बाहर जाने वाली २०) रु० की बन जावेगी और कसाईखाने में जाने वाली १०) रु० की हो गई । यह कैसे हो सकता है । इसमें बदबू आने जैसी बात है । गोश्त खाने वालों पर महरबानी करने के लिए आप करते हैं यह ? आपने किया है । यहां पर किया है और यह नोटिफिकेशन निकाला है । जहां तक मुझे मालूम है, मैं आपको नोटिफिकेशन की डेट वगैरह सब दे दूंगा । रसीदें भी पेश कर दूंगा, अगर आप मुझे चैलेन्ज करेंगे तो । इस तरह से वह टैक्स आधा हो गया । दर वही रही पर उसकी स्टैण्डर्ड कीमत में अन्तर आने से बाहर जाने वाली पर तो वही टैक्स रहा, पर यहां वाली कसाईखाने में जाने वाली पर आधा हो गया । उस रोज तो आपको बडा जोश आया था । हमारे विरोधी पक्ष के नेता को इतनी बडी बात पर जोश नहीं आता, उनको छोटी छोटी बातों पर आता है । नेगोशियेशन्स से टैक्स घटाना गलत प्रैक्टिस है । इससे विश्वास नहीं जमता जनता में । बाहर जाने वाले पर बीस के हिसाब से और कसाईखाने में जाने वाली पर दस रुपये के हिसाब से । कहते हैं कसाईखाने वाली को गोद में लेकर नापा जाता है । शुद्ध भाषा बोलिए । कस्टम हो जावेगा तो लगावेंगे कि नहीं । इससे अधिक अधिकारियों की बात कहता हूं । वह अधिकारियों के हाथ में करप्शन बहुत जोरों से जा रहा है । एक्साईज का करप्शन होगा । मैं कहूंगा, आप उसमें सुधार पैदा करो ।

मैं कह सकता हूं करप्शन की बात पुलिस के बारे में । चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं, पर जो यमदूत रात दिन घूमते हैं ये एक्साइज, के उनके लिए कह सकता हूं । इनके प्रति समाज की कोई सहानुभूति नहीं है । मैं इसलिए कहता हूं कि यह कि आपको उनके बारे में पता लग जावे । आप साफ साफ यहां कहिए कि कौनसा टैक्स आप कम करने वाले हैं, कौनसा नहीं ? यहां से परमिशन लीजिए । बकरी-गोट के बारे में इस तरह की टैक्स कम करने की बातें करके आप गलतफहमी खुद पैदा करते हैं । कोई गोद में लेकर बकरी की हैसियत नहीं देखी जाती । आपकी मेरी हैसियत देखी जाती है । मैं हैरत में हूं कि किस तरह से आपने इन एक्साईज के यमदूतों को जनता को लूटने के लिए छोड रखा है । बस इतना ही कहना चाहता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरदत्तसिंह ।

**श्री हरदत्तसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..........

**श्री उपाध्यक्ष** : (कुछ विराम से) श्री हरदत्तसिंह । मेरा मतलब श्री हरदत्तसिंह जी से है ।

**श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : मैं समझ गया था ।

पिछले तीन दिनों से मैं बहस सुन रहा हूं, पर अफसोस है कि सत्तारूढ पार्टी सदस्यों तक ने माननीय वित्त मंत्रीजी के साथ सहानुभूति के दो अल्फाज नहीं कहे । इसलिए उस परम्परा को तोडने के लिए

(श्री हरदत्त सिंह)

मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चीन की हमले की काली छाया को कलचट रंग में अपने भाषण में छपवाया और उसमें बहुत सुन्दर सरस उर्दू शब्दों में, उर्दू जुबान में अपने विचार रखे। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मुझे अफसोस है कि उन्होंने इतने लम्बे चौडे राजस्थान के हिसाब के आंकडों में माथापच्ची की, श्रम किया और फिर भी किसी ने दो शब्द सहानभूति के नहीं कहे। सो मैं यह चाहता हूं कि चीनी हमले ने जिस तरह से सारे हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न वर्गो को एक कर दिया और देश की सारी जनता एक ताकत के रूप में उसका विरोध करने को तैयार हो गई और जिससे चीन के पास बहुत बडी ताकत थी, फिर भी उसे वापिस हटना पडा। इसी तरह से बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो पेश किया है उसकी और बातों की तो परवाह नहीं, पर किसानों पर जो ३ टैक्स लगाए हैं उसके लिए मेरा विश्वास है, मेरी यह निश्चित धारणा है कि वे सदन की भावनाओं के विपरीत हैं और इन्हें उनको वापिस ले लेना चाहिए।

(१.०० म.प.)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने दो तरह की विचारधाराएं आई। एक पक्ष यह कहता है कि सरकार को बचत करनी चाहिए, खर्च कम करना चाहिए, योजनाओं में भी कुछ कटौती करनी चाहिए और बाहर की आर्थिक सहायता लेनी चाहिए और टैक्स नहीं लगाने चाहिए। दूसरा पक्ष यह कहता है कि हमें अपनी योजनाएं चालू रखनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, टैक्स भी लगाने चाहिए; लेकिन किसान और गरीब उपभोक्ताओं के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक किसानों के ऊपर और उनके मवेशियों के ऊपर टैक्स लगाने का सवाल है उसके ऊपर दोनों विचारधाराओं के लोगों का एक मत है कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करें। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के भाषण में समाजवाद का नारा दिया है। बहुत सुन्दर नारा है। जिस पार्टी से हमारे वित्त मंत्री महोदय आते हैं वह गांधीवादी और समाजवादी दोनों विचारधाराओं को लेकर चलने का दावा करती है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि आप इस बजट को किसी को भी दिखा लीजिए, किसी राजनैतिक के पास ले जाय चाहे कोई गांधीवाद का प्रतीक हो, चाहे समाजवादी धारा का प्रतीक हो-इस बारे में अभी आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने यह इशारा किया था और इस बात से मैं सहमत हूं कि बजट को बनाने वाला कोई गांधीवादी विचारधारा को मानने वाला नहीं है, इसको बनाने वाला कोई ब्यूरोक्रेट है जिसने ब्यूरोक्रेसी के तरीके पर यह सारा बजट तैयार किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आंकडों की लीपापोती से, समाजवाद का नारा लगाने से यह बजट समाजवादी नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा इसको कह सकते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक कह सकते हैं, कैपेटलिस्टिक कह सकते हैं जिसका आम जनता पर, देश की ८० प्रतिशत किसान जनता पर दमनकारी प्रभाव पड़ेगा।

(श्री हरदत्त सिंह)

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कम्युनिस्ट इस देश में डिसकाण्टेण्टमेन्ट के बीज बोना चाहते हैं, देश की हालत कमजोर करके अपना अधिपत्य जमाना चाहते हैं। अगर उनको वहम है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम्युनिस्ट यह चाहते हों या नहीं--अगर चाहते हैं तो भी कहने का हौसला नहीं कर सकते, लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है और जो टैक्सेज लगाए हैं अगर किसी तरह का कोई डिसकांटेण्टमेन्ट फैलेगा तो इससे फैलेगा। आप गरीबी मिटाना चाहते हैं और इस तरह का नारा देते हैं जनता को। आपने इस बजट में बताया है कि हमें गरीबी से लडना है। मैं कहता हूं कि आपने जो टैक्स लगाए हैं यह साबित करते हैं कि आप गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, बल्कि गरीबों को मिटा रहे हैं।

मैं थोडा सा हवाला देकर, क्योंकि इस बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के दिमाग को ज्यादा टैक्स नहीं करूंगा, कुछ टैक्सेज के बारे में कहना चाहूंगा। अनाज के ऊपर जो टैक्स लगा है, जमीन पर जो टैक्स लगा है; बारी-बारी से थोडा सा हवाला देता हूं। आपके राजस्थान में ३० रु० बीघा जमीन पर टैक्स लगता है और इस बात को सरकारी बेंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उदाहरण के तौर पर दिया है। देवगढ (भीम) से आने वाली माननीय सदस्या ने इसका विस्तार से हवाला दिया है। २०) रु० बीघा किसानों को आइन्दा और १०) रु० बीघा कम्पलसरी सेविंग के तौर पर आइन्दा साल देना होगा और १०) रु० जो ड्योढा टैक्स लगाया है आखिरी स्टेज पर उसके हिसाब से देना होगा। इस प्रकार से एक किसान को, राजस्थान के गरीब किसान को ४०) रु० बीघा टैक्स के तौर पर देना पडेगा। अब इतना टैक्स देने के बाद उसके पास क्या बच जाएगा? यह माननीय वित्त मंत्री महोदय के खुद के समझ में नहीं आ सकता। दूसरी चीज अनाज की है। पिछली बार बजट-सत्र के समय इन्हीं माननीय वित्त मंत्री महोदय ने हाउस को एक नई तरह की सूचना दी थी कि आम जनता की खुराक गेहूं है और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, चने पर लगेगा। लेकिन इन बारह महीनों में बडी मेहनत करके एक नई चीज और खोज निकाली और वह यह खोज निकाली कि ज्वार, बाजरा और मक्का के ऊपर टैक्स लगा दिया। आपको मालूम हो गया कि यह वह लोग खाते हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, आप तक पहुंच नहीं सकते। अभी एक किसान माननीय सदस्य ने इशारा दिया था कि किसानों पर टैक्स इसलिए लगाते हैं कि उनसे वसूल आसानी से होता है। दूसरा कन्सीडरेशन माननीय वित्त मंत्री महोदय का यह है कि उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जो कि बोलते नहीं हैं। आपने यह टैक्स उनके ऊपर इसलिए लगाया है कि क्योंकि वे बोल नहीं सकते और आपका वास्ता उनसे पडता नहीं। आप शहरों से चुन कर आए हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी किसान के घर गए हैं? क्या कभी आपने उसके झोंपडे को देखा है? क्या कभी आपने उसकी रोटी देखी है? आपने कभी उसका खुराक का अनुभव किया है क्या आपने

(श्री हरदत्त सिंह)
उनके नंगे शरीर की तसवीर देखी है और उनके मां-बाप की अर्धनंगी तस्वीर देखी है ? अगर देखी होती तो आप टैक्स नहीं लगाते । मैं पूछना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि जिस खुराक को किसान खाता है—बाजरा, मक्की और ज्वार उसकी रोटी अपने लिए अभ्यास के तौर पर खा लीजिए । मैं कहूंगा या तो आप स्वर्गीय हो जायेंगे या फिर टैक्स लगाना भूल जायेंगे । आप इस सत्ता की कुर्सी पर बैठ कर भूल जाते हैं । आप गऊ माता के बच्चे की मेहरबानी से यहां आते हैं । आप तो बहुत पुराने विद्वानों की औलाद हैं और उन्होंने पुराणों में लिखा है कि गऊ माता वैतरणी से पार कराती है मरने के बाद उसकी पूंछ पकड कर । वह सही है या नहीं, लेकिन यहां गऊ माता और उसके बच्चों को भी नहीं बख्शा है, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है । मैं कहता हूं कि इसको तो आप टैक्स से माफ कीजिए । किसानों को जाने दीजिए । आपका उनसे वास्ता ही नहीं है । तो मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि यह सरकारी समाजवाद जो आपको आपके सचिवालय से मिलता है और जिसके ऊपर दस्तखत करते हैं उसको एक बार सोच लें और हम पर, राजस्थान पर मेहरबानी कीजिए । अब तो आप भी सोलह आने राजस्थानी हैं ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले इसी सदन में फरमाया था कि हमारी खेती की पैदावार बढ रही है । आपको भी गलतफहमी हो गयी कि खेती की पैदावार बढ रही है । इसलिए ही आपने टैक्स लगा दिया है । लेकिन इसके लिए मैंने आपके द्वारा बनाए गए आंकडों को देखा है । १९५१-५२ में आपने अपने आंकडों को आधार बनाया । १९५५-५६ से १०० का पोइण्ट रखा............

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री) : यह आ चुका है सदन में ।

**श्री हरदत्त सिंह** : आपका ध्यान उस पर नहीं गया, इसलिए दिलाना चाहता हूं । फूड ग्रेन्स की पैदावार १९५६-५७ में १२६. २२ थी और १९६१-६२ में १३६.६३ हो गयी और आपको वहम हो गया कि ६ पर्सेन्ट पैदावार बढ़ गई...

**श्री बालकृष्ण कौल** : नहीं, वहम नहीं हुआ है ।

**श्री हरदत्त सिंह** : तो खुदाहाफिज़ है ।

ऑइल सीड्स १३४.६५ था ५६-५७ में और आज ६१-६२ में ११६.६५ रह गया । इसमें १८.३० की घटोत्तरी हुई । फाइबर में ५६-५७ में १२६.६३ और ६१-६२ में १२६-८३; तो इसमें पोइन्ट १० की घटोत्तरी हुई है ।

अब अगर यह फर्मावें कि अनाज किसान पैदा करता है तो कुछ तो खुराक में चला जाता है, बाकी बीज में चला जाता है और रहा सहा उसी वक्त और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बाजारों में सस्ते भावों पर बेच देते हैं— तो किसान की हालत ठीक हो गई । उनकी हालत तो मनी क्रॉप्स; जैसे ऑइल सीड्स, फाइबर्स की पैदावार बढ़ेगी और उस पर जो मुनाफा मिले तब उसकी खुशहाली हो सकती है । आपके आंकड़े साबित करते हैं कि मनी

(श्री हरदत्त सिंह)

कोप राजस्थान में घटी है । इसलिए आपके दिमाग में किसान के खुशहाल होने का वहम है, वह हट जाना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं । अभी तो एक घंटी बजी है । क्यों जल्दी कर रहे हैं ?

मैं अर्ज करता हूं कि पुरानी जमीन पर पैदावार घटती है और नई जमीन पर पैदावार बढ़ती है । इसका सुबूत यह है कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि गंगानगर का इलाका सबसे अच्छे हिन्दुस्तान में माल्टा और नींबू के लिए मशहूर था वहां पर पैदावार काफी घटी है । आपके सारे सलाहकार और विशेषज्ञ धरे बैठे रहे । किसानों के बड़े भारी दुश्मन पैदा हो रहे हैं, किसानों की फसल के दुश्मन पैदा हो रहे हैं उनको आप हटा नहीं सकते और टैक्स बढ़ा रहे हैं ।

उनका सबसे बड़ा दुश्मन प्राकृतिक बाधाएं है जिनमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी, ओले इत्यादि हैं । आपको ताज्जुब होगा वित्त मंत्री महोदय कि होली के रोज़ आप तो रंग में रंगे हुए मजा उड़ा रहे थे और होली के दिन जिला गंगानगर में ओलों की बरसात हुई थी और जिस किसान की फसल पर आप टैक्स लगा रहे हैं उसकी जो सबसे ज्यादा कीमती रबी की क्राप है, पैदावार है वह ६१ फीसदी किसानों की बर्बाद हो गई ।

दूसरी सरकारी बाधाएं हैं । सरकारी बाधाओं में करप्शन सबसे बड़ा है । उसको आप हटा ही नहीं सकते । दूसरा, आपके अधिकारियों की नेग्लीजेन्स, तीसरे सोवियेरिटी इन रिकवरी । आप उनसे वसूली करते हैं कर्जे की या लगान की, तो आपका आदमी उनके सिर पर भूत की तरह खड़ा हो जाता है; लेकिन करोडों रुपये वहां का एक मिल लिये हुए बैठा है उससे आप वसूल नहीं करते हैं । उसके लिए आप कहते हैं कि उसकी हालत अच्छी नहीं है । तो आपको हम ही दिखाई देते हैं । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वसूली के लिये यदि आपको पी० डी० आर० का इस्तेमाल करना है तो आप मिल मालिकों पर, करोड़पतियों पर करें ।

सरकार की ओर से सबसे बड़ी बाधा जो अब पैदा हुई है वह, श्रीमानजी मुझे माफ करेंगे . . .

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

वह है ये टैक्स । इनसे पैदावार तो पता नहीं कहां रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे और शायद आप भी नहीं आ सकते हैं, ऐसी हालत पैदा हो सकती है । इसलिए कांग्रेस के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, गरीब किसानों के नाम पर और कम से कम अपने आप पर तरस खाकर किसानों पर से टैक्स हटा दें । 'Tax is the equaliser of income" अगर आप यह सिद्धान्त सामने रखें और उसके मुताबिक रखें, क्योंकि पैसा वहीं से आयेगा जहां कि पैसा होगा, लेकिन आपके प्रयत्न तो भागीरथी प्रयत्न हैं । आप जहां पैसा नहीं है वहां से पैसा लाना चाहते हैं । आप कलियुगी भागीरथ हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट स्टडी का हवाला और देता हूं जो कि आज तक किसी ने

(श्री हरदत्त सिंह)

नहीं दिया है। टैक्स का जो हिसाब है लैण्ड रेवेन्यू का, वह बजट स्टडी के पृष्ठ ४३ पर दर्ज है। उसमें मद्रास में लैण्ड रेवेन्यू टैक्स १.७४ है, पंजाब में २.१५ है; लेकिन राजस्थान में, हिन्दुस्थान में आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए राजस्थान में और सब में पिछड़े हुए किसान पर आपने ४.३६ टैक्स लगाया है।

(शेम, शेम)

इस तरह से पैदावार को बढ़ाने और खुशहाली की बातें की गई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा एक फिकरा बाकी है।

**श्री बालकृष्ण कौल** : श्रद्धांजलि तो सुन लेने दें।

**श्री हरदत्तसिंह** : मैंने अर्ज किया था कि 'Tax is the equaliser of income.' लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कैटल पर जो टैक्स लगाया है तो मैं कह सकता हूं कि आपका Tax is the oppressor of the already oppressed peasantry of Rajasthan.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद एक मिनट।

३०००) की इन्कम वालों को आप इन्कम टैक्स से माफ कर देते हैं तो हमको भी माफ कर दें। औरंगज़ेब ने ज्यादती की थी और जजिया लगाया था तो उस वक्त तो चोटी थी वह चोटी कटवा ली और पिण्ड छूट गया लेकिन, अब तो चोटी भी नहीं है क्या कटायेंगे और पिण्ड छुड़ायेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं) श्री घासीराम यादव।

**श्री उपाध्यक्ष**:

**श्री घासीराम यादव** (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बजट रखा है इसमें टैक्स इसलिए लगाया है कि राजस्थान में जनता का विकास कर सकें और, यह बात सही भी है...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि चार बजे बाद सरकारी पक्ष का उत्तर होगा, इसलिए चार बजे तक अवसर है, और उसमें विभिन्न पार्टियां अपने समय के अनुसार विभिन्न सदस्यों को अगर बुलवाना चाहें तो उसी के मुताबिक अपना भाषण रखें।

**श्री घासीराम यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि टैक्स लगाना, जैसा कि सरकार ने बताया, जरूरी है। सरकार यह कहती है कि हम विकास करना चाहते हैं, और राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, और प्रदेशों के मुकाबले में काफी पिछड़ा है इसलिए इसमें आज विकास की जरूरत है। लेकिन आज मैं इस बात को सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या दरअसल में जिस तरीके से सरकार विकास करना चाहती है उसको ठीक समझने का ठेका सरकार का ही है या जनता का भी है? सरकार जिस तरह से कहती है कि हम इस तरह का विकास करेंगे, मैं यह महसूस करता हूं कि आम जनता इस बात को नहीं महसूस करती है कि यह तरीका विकास करने का ठीक है। सरकार कहती है कि डवलपमेन्ट का महकमा है, विकास का महकमा शुरू कर दिया है। देखने में ऐसा लगता है कि विकास के महकमे पर जो खर्च हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि डवलपमेन्ट महकमे

# Page No.27



(श्री घासीराम यादव)

में खर्चा अधिकतर खर्चा एक तरह से फिजूल खर्चा है और जनता को ज्यादा फायदा जो डवलपमेन्ट के जरिये से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। आपने डवलपमेन्ट कमिश्नर, जोइन्ट डवलपमेन्ट कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, दुनिया भर का स्टाफ रखा है जो कि किसान और गरीब आदमियों का किस तरह से डवलपमेन्ट करते हैं ? मैं यह महसूस करता हूं कि डवलपमेन्ट महकमे की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज का डवलपमेन्ट करना है तो संबंधित महकमों के जरिये से करिये। अगर आपको शिक्षा का डवलपमेन्ट करना है तो शिक्षा विभाग के जरिये से करिये। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा फिजूल खर्चा है। इसकी अगर कोई कमेटी बैठाई जाय और वह पता करे तो मालूम पड़ेगा कि क्या है। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट रखा हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने किसानों के लिए क्या किया ? इसके आंकड़े उठा कर देखिये तो ९८ लाख हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट पर खर्च कर रहे हैं। किसानों से पूछिये जिनके लिए आप कहते हैं कि खेती करने वालों के लिए महकमा रखा है, कि क्या फायदा किया उसने आज तक ? आपने १० साल, ६ साल, ८ साल, ५ साल और २ साल तक इतना रुपया खर्च किया है, हमने करोड़ों रुपया खर्च किया है उससे किसानों की क्या तरक्की हुई, उनकी कितनी पैदावार बढ़ी, क्या ज्यादा गहूं का बीज सुधरा ? जिस आदमी को आप ठीक समझते हैं उनको कहते हैं कि हम आपका विकास करना चाहते हैं, लेकिन उसको आप पूछते तक नहीं। मैं देखता हूं कि हमारे इलाके में लोग जानते तक नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट जैसा डिपार्टमेन्ट भी कोई है। तब फिर यह किसके फायदे के लिये बना है ? जो आफिसर अलवर जिले में बैठे हैं उनका किसानों से ताल्लुक नहीं और उनसे भी जो बड़े बड़े आफिसर हैं उनका तो मानो किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। बजट में आपने इतना स्टाफ रखा है कि एक डाइरेक्टर रखा है तो उसके नीचे जोइन्ट डाइरेक्टर तीन चार रखे हैं, उनके नीचे फिर डिप्टी डाइरेक्टर्स तीन-चार रखे हैं, फिर असिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स कई रखे हैं; एक बडी भारी परेशानी है। एक डाइरेक्टर है तो उसके पीछे एडीशनल डाइरेक्टर और जोइन्ट डाइरेक्टर्स और दूसरे इतने अधिक रखे हैं, आखिर वे सब लोग क्या करते हैं ? जो लोग टैक्स देते हैं उनको पूछने का हक है कि जो हम टैक्स देंगे वह कहां जायगा और जो आज तक दिया है वह कहां गया ? मैं कहता हूं अगर कमेटी बैठाई जाय तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का आधा स्टाफ खत्म हो सकता है। २ करोड रुपया सालाना का जो खर्चा आप इस विभाग पर करते हैं उससे कोई फायदा होता हो ऐसा किसान महसूस नहीं करते। तो फिर इस खर्चे का आधा यानी १ करोड रुपया का खर्चा क्यों नहीं कम कर दिया जाय ?

फिर आपने प्लान्ट प्रोटेक्शन का सब-महकमा और कर दिया। इस साल उसका डिप्टी डाइरेक्टर और बढा दिया, एक कोटन का डिप्टी डाइरेक्टर बढा दिया, एक ऑयल सीड्स का बढा दिया, एक एनिमल हस्बैन्ड्री का कर दिया। जिसने कहा हमारा नहीं है तो और बढा दिया। एग्रीकल्चर इन्फार्मेशन ऑफिसर्स दो और बढाये हैं। आखिर आपको बताना तो चाहिये कि आप क्या करना चाहते

(श्री घासीराम यादव)

हैं। उनका काम बढता है तो गांवों में बढता है या और कहीं वढता है या और कहीं शिक्षा देते हैं? आपने स्टेटिसटिक्स के ऑफिसर लगा रखे हैं, वे अलग आंकडे तैयार करते हैं। वे क्या करते हैं कि पटवारियों से और तहसीलदारों से आंकडे इकट्ठे करके रेवेन्यू बोर्ड में भेज देते हैं। यह काम तो पटवारी और तहसील वाले स्वयं कर सकते हैं, वे सीधे ही आंकडे रेवेन्यू बोर्ड में भेज सकते हैं। फिर इनका क्या काम है ? लेकिन क्योंकि इनको रखना है इसलिये ये पोस्ट्स कायम हैं।

कहीं कहीं पर आप मोडल फार्म बना लेते हैं। अलवर जिले में भी इस तरह का फार्म है। उसको देखकर किसानों को निराशा होती है। उस जमीन पर जितना अनाज किसान पैदा कर सकते हैं उसका आधा भी वे पैदा नहीं करते हैं, वर्बाद करते हैं। शिक्षा का प्रयोग होना चाहिये और उसके अनुसार खेती की उपज अधिक होनी चाहिये; वहां उसका आधा भाग भी नहीं होता है। आपने जो कुछ सीखा है उसका किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है।

इसी तरह से और महकमों को देखिये। पब्लिक हैल्थ को देखिये, एनिमल हस्बेन्ड्री को देखिये, शिक्षा के महकमे को देखिये। इन सब में बहुत फिजूल खर्चा है। आपने जो ठेका ले रखा है कि किसानों का फायदा करना चाहते हैं वह गलत है। इनसे किसानों को और गरीबों को कोई फायदा नहीं है। इनमें कमी होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तहसील लैवल पर आपने दो महकमे कायम कर रखे हैं; एक तहसील और दूसरा ब्लाक। सब लोग यही महसूस करते हैं कि आज तहसीलदार के पास कोई अख्तियार नहीं हैं सिवाय रेकार्ड रखने के और लगान वसूल करने के। सारे अधिकार ब्लॉक डवलपमेन्ट अधिकारी को दे रखे हैं। यह काम भी तहसील के नीचे रखना चाहिये और दूसरा जो स्टाफ है उसको खत्म करना चाहिये। इससे आपका सेविंग होगा। दोनों को आप क्यों रखते हैं ? तहसील की बिल्डिंग अलग है, स्टाफ अलग है और ब्लॉक को भी अलग कर दिया, आर. ए. एस. आफिसर उस पर बैठा दिया। तो उनको कम करना चाहिये। यह जो आपका खर्चा है उसका आधा हो सकता है। इस तरह से आप दो-ढाई करोड रुपयों का सेविंग कर सकते हैं। हम लोगों का, किसानों का सरकार से पूछने का हक है, क्यों नहीं आप इसमें कमी करते ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसको सरकार विकास कहती है, आम लोग उसको विकास नहीं मानते। सब लोग शिक्षा चाहते हैं, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स चाहते हैं, इनमें विकास होता है तो यह विकास है। सब लोग चाहते हैं कि रोजगार के साधन बढें, यदि ये बढते हैं तो यह विकास है। कृषि में कुछ सुधार हो तो यह भी विकास है। लेकिन आपने और कई विकास बना रखे हैं वे ठीक नहीं हैं। मैं अपनी कांस्टिट्यूएन्सी की मिसाल देता हूं। हमारे यहां के लोगों ने स्कूलों के लिये बिल्डिंग बना रखी है ५०-५० हजार रुपये लगाकर और चाहते हैं कि तहसील में चार स्कूल्स खुल जायं, लेकिन आप उनको कहते हैं हाई स्कूल तो नहीं खोलेंगे लेकिन यदि आप चाहें तो एक्सटेन्शन ब्लाक खोल देंगे या बी. डी. ओ.

(श्री घासीराम यादव)

को जीप दे देंगे । जीप को वे विकास नहीं मानते हैं। आपको हाई स्कूल खोलने चाहियें। जब देने वाले ५० हजार की बिल्डिंग बनाकर दे रहे हैं, १० हजार का खर्चा दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं बनाते ?

दूसरी बात गांव वाले कहते हैं कि सडक बना दीजिये, बिजली लगा दीजिये तो आप कहते हैं सडक के लिये तो पूरे अलवर जिले के लिये २ लाख रुपये रखे हैं और बिजली के लिये कहते हैं कि पैसा नहीं है और उसके बदले में कहते हैं डेरी फार्म ले लीजिये । डेरी फार्म को क्या करेंगे ? जिसने डेरी फार्म के लिये पैसा लिया है उसने ही मिसयूज किया है । लोग खा गये । सरकार इतनी कमजोर है कि वसूल नहीं होता है ।

आप कहते हैं तकावी ले लीजिये । मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है । लोग कहते हैं, कुओं में पंपिंग सेट लगा दीजिये, मीडियम इरिगेशन वर्क बना दीजिये, इरिगेशन के साधन जुटा दीजिये, पर यह सब कुछ नहीं होगा । तकावी देते हैं वह भी समर्थ लोगों को देते हैं । आप दूसरे तरीकों से विकास करिये । आप जो विकास करते हैं उसको लोग ठीक नहीं मानते । लोगों की जो भूख है उसको मिटाइये तो लोग आपको टैक्स देंगे । पर मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है किसानों पर टैक्स लगाने की । अभी जैसा कि पूर्व वक्ता श्री हरदत्तसिंहजी ने आंकडे बता कर कहा था कि राजस्थान में हाइयेस्ट टैक्स हैं। जब रजवाडे थे, लोगों पर तकलीफ थी, राजाओं पर तकलीफ थी, आमदनी के साधन नहीं थे उस समय लैंड रेवेन्यू हाइयेस्ट रहता था क्योंकि वही आमदनी का साधन था । आज आप के आमदनी के इतने साधन हो गये हैं; जैसे इन्कम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, सेन्टर से एड लेते हैं फिर लगान इतना अधिक बढाने की क्या आवश्यकता है ? हमारे बराबर पंजाब प्रान्त है वहां पर लगान हमसे एक तिहाई है, जब कि वहां पर भी इसी प्रकार की खेती है, इसी प्रकार की मार्केट वेल्यू है पैदा भी उतना ही होता है, फिर भी पंजाब में यहां से एक-तिहाई लगान लेते हैं और हम तिगुना लेते हैं। क्यों लेते हैं ? हम अलवर जिले में पैदा हुए, अलवर राज्य में पैदा हुए, राजा वहां के थे हम भुगतते रहे, कस्टम भुगतते रहे। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि कस्टम हटा दिया, लेकिन लगान भी कम करना चाहिये । हमारी मांग है कि उतना ही लगान होना चाहिये जितना पंजाब में है। लेकिन आप लगान कम करने के बजाय बढा रहे हैं, यह अनुचित है । आपकी नजर किसानों की तरफ जाती क्यों नहीं ? लोग कहते हैं कि किसानों की हालत अच्छी हो गई । क्या अच्छी हो गई? क्या उनमें से किसी के पास मोटर है या मोटर गैरेज है या उनका बैंक बेलेन्स है या उन्होंने बडे बडे मकान बना लिये हैं। वे सीधे सादे तरीके से अपना गुजर कर लेते हैं। इस पर भी आप उन पर टैक्स बढाते जा रहे हैं । क्या प्रोप्राइटरी है उसमें, कोई प्रोप्राइटरी नहीं है। राजस्थान में सैटल्ड तरीके से लगान लेना चाहिये । लेकिन यह गलत बात है कि आप टैक्स बढाते जावें । यदि आप पैसा चाहते हैं तो आप अपने खर्चे में कमी करिये, पर किसानों का लगान मत बढाइये ।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस बजट के ऊपर हम चार दिनों से बराबर बातचीत

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कर रहे हैं उस बजट को देखने से साफ प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री महोदय को भी अपने भाषण के अन्दर जिन बातों को सिद्धान्ततः पहले रखना चाहिए था उनको सबसे आखिर में रखा है और वह है उनकी पार्टी की नीति जिसके आधार पर देश में वे राज्य चलाना चाहते हैं और वह है प्रजातांत्रिक समाजवाद क्योंकि वे सही तौर पर जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने बजट में इस साल भी और गए साल में रखा वह बिलकुल प्रजातांत्रिक समाजवाद के विरुद्ध है और कोई ताल-मेल नहीं है। इसलिए जिन सिद्धान्तों को बजट स्पीच में पहले लिखना चाहिए था उनको बाद में लिखा और जो चीज बजट में पेश की उससे साफ जाहिर होता है कि वित्त मंत्रीजी और सरकार की नीति क्या सही माने में समाजवाद कायम करने की है ? या वो हमारे इस देश के अन्दर इस तरह का समाज बनाना चाहते है जिससे कि हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले सत्तर प्रतिशत आदमी हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं और मध्यम वर्गों के व्यापारी और आदमी हैं—वे दबते हुए चले जाएं और तीस प्रतिशत, जिसके अन्दर पुराने जमींदार हैं, जागीरदार हैं, केपिटलिस्ट्स हैं वे बढोत्तरी करते जायं। इस तरह का बजट आज हमारे सामने है और उसके अन्दर जिस तरह के टैक्स लगाने की बात कही गई है, उसके अन्दर जो चीजें हमारे सामने रखी हैं, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात इससे पहले की बजट के बारे में कहूं, गए साल के बजट के बारे में कहना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने गए साल १ करोड २८ लाख के टैक्स लगाने की घोषणा इस सदन में की थी और वे लगाए गए, और उस बजट के अन्दर इतना ही उन्होंने घाटा बताया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात उस बजट में कही थी, कि हम उस चालू वर्ष के अन्दर चार करोड के सार्वजनिक लोन हमारे इस बजट के लिए लेंगे और जिसका जमा-खर्च गए साल के अन्दर जमा के खाते में बताया था। उसके आधार पर चार करोड के बजाय साढे चार करोड के लोन हमारी सरकार के ऊपर लिए और इस तरह पचास लाख रुपया उन्होंने अपने बजट में बताए हुए आंकडे के ऊपर लेकर, इस प्रान्त के ऊपर ज्यादा लोन लेकर उससे हमको प्रभावित किया है। इसके बाद उन्होंने सत्तर लाख रुपए के नए टैक्स १९६२-६३ के साल में लगाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ बजट बनाने वाले लोगों से, माननीय वित्त मंत्री से और ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि इस तरह के आंकडे बजट में पेश करते हैं, जनता के सामने पेश करते हैं, उनको बहुत ही सोच-समझ कर इस तरह के आंकडे पेश करना चाहिए जिससे कि उनमें ज्यादा हेर-फेर नहीं करनी पडे और लोगों को यह महसूस नहीं हो कि यह धोखेबाजी की बात जनता के साथ की जा रही है। पचास लाख रु० ज्यादा उधार ले लेना, सत्तर लाख रुपए के ज्यादा टैक्स लगा देना, पचास लाख की बचत एडमिनिस्ट्रेशन में बताना और फिर भी बजट डेफीसिट में रहे और फिर सप्लीमेण्ट्री डिमांड इस हाउस में रखना, क्या यह बजट बनाने का सही तरीका है, क्या यह सही आंकडे पेश करने का तरीका है, क्या यह हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेने का, जनता को सच्ची

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बात बताने का सही तरीका हो सकता है ? परन्तु उसके अन्दर एक चेंज या एक परिवर्तन ही नहीं किया, बल्कि साल के अन्दर पांच सात दफा परिवर्तन किए गए । उपाध्यक्ष महोदय, ठीक इसी तरह का बजट आज भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है । जो आंकडे इस बजट के अन्दर दिए हैं और जो जमा की तरफ बाकी लिखा है, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब यह साल खत्म होगा, या इसके बीच में जब गुजरेगा, मैं बहुत दावे के साथ, जो हमारे प्रीविअस एक्सपेंसेज हैं उनके आधार पर कह सकता हूं, इस बजट, जिसके अन्दर साढे चार करोड का घाटा बताया गया है, इससे कहीं ज्यादा रुपयों का घाटा इस बजट में रहने वाला है । इसका मूल कारण है कि इन्होंने जमा की तरफ रकम को जोडा है, जो कि लोगों के अन्दर हमारी सरकार का रुपया बकाया है, उनसे वसूल होगा—उसको इसके अन्दर जोडा है, जो जमीन की बिक्री से होने वाला रुपया है उसको इसके अन्दर रखा है, जो बेटरमेंट लेवी से आने वाली रकम है, उसको इसके अन्दर जोडा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को लेने में, वसूल करने में अगर सरकार कामयाब होती तो आज चार करोड रुपये का घाटा बता कर ये टैक्सेज इन्होंने लगाए हैं, वे आज राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर लगाने की नौबत नहीं आती । ये लोग जो आज ट्रेजरी बैंचेज पर बैठ कर लम्बी—चौडी बातें करते हैं, सिद्धान्तों की बात करते हैं, और आज भी जितने कांग्रेस बैंचेज से बोलने वाले साथी हैं, उन्होंने बहुत जोर से टैक्सों का विरोध किया है, इस बजट का विरोध किया है, परन्तु मैं आज नहीं बल्कि कुछ दिनों में इस बात को बताऊंगा, जब वोट देने का सवाल आएगा तो वे अपनी आत्मा की पुकार को दबा कर इसके पक्ष में वोट देंगे । और यह है प्रजातंत्र का जमाना । उस गरीब जनता ने स्पष्ट रूप से देखा है, जिससे वोट लेकर आप यहां आकर बैठते हैं कि आप कहते कुछ हैं और करने के नाम पर कुछ और करके उनके ऊपर बोझ लाद देते हैं । वास्तव में आपकी कान्शियन्स आपको अलाऊ नहीं करती परन्तु क्या करें, चन्द लोगों को कुर्सी पर बिठाए रखना आपके हाथ में है, इसलिए उनको बिठाए रखने के लिए इस तरह की बात करना लाजिमी हो जाता है ।

आज मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूं, तो जो बातें कही थीं कि एमर्जेन्सी के टाइम में यह बजट पेश किया गया है, इसलिए हमको चाहिए कि ज्यादा त्याग करें, तपस्या करें और उदार होकर अपने देश के लिए धन दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, इस देश के ऊपर जब से चीन का हमला हुआ, और इस देश में हमारे राष्ट्रपति ने इस असाधारण स्थिति की घोषणा की, मैं हिन्दुस्तान के हर नागरिक को इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपनी जिम्मेदारी को समझ कर सब कुछ तन-मन-धन, खून सारा का सारा इस देश के लिए बलिदान करने के लिए अपने आप आगे कदम बढाये। सरकार के कहने पर उन्होंने कदम नहीं बढाये, और जब सरकार के इन चन्द लोगों जो ऑफिसर लोग कहलाते हैं, जो अपने आपको जनता का ठेकेदार समझते हैं, ने इस सरकार के लिए या इस देश के लिए जब जबरदस्ती इस काम में कदम बढाये तो वह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सारी प्रगति, वे सारे विचार जो जनता में स्वतः पैदा हुए थे, में एक फर्क आ गया और उसकी वजह से इस काम में कदम बढाने में बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं आज कहता हूं कि त्याग, तपस्या और बलिदान दूसरों से जब तक नहीं कराया जा सकता, सबसे पहले त्याग, तपस्या और बलिदान अपने से शुरू होता है। अगर कहने वाले त्याग, तपस्या और बलिदान नहीं करते हैं तो दूसरों पर उनकी बात का असर नहीं पडता है इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन राज्य कर्मचारी लोगों ने जाकर इस बात के लिए चन्दा इकट्ठा करने की बात कही। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात अर्ज करूं कि इन चन्द गवर्नमेंट के लोगों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और कहा कि आप हमसे चन्दा मांगते हैं जब कि आपने एक दिन की तनख्वाह दी है। दो हजार माहवार पाने वाले ने भी एक दिन की तनख्वाह दी है और पिच्चयासी रुपये पाने वाले ने भी एक दिन की तनख्वाह दी है और किसान के घर जाते हैं तो पुलिस के लोगों को लेकर, गवर्नमेंट के तहसीलदार को लेकर जाते है और हुकूमत का डंडा बता कर कहते है कि पैसा देना चाहिए जिसने अपनी जिम्मेदारी समझ कर सब कुछ अपने आप से न्योछावर करने की कोशिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे रहने वाले लोगों से और हमारे सम्माननीय उन साथियों से, जो अपने आपको देशवासी मानते होंगे, और जो सेक्रेटेरियट के अन्दर कुर्सियों पर बैठते हैं अर्ज कर सकता हूं कि एमर्जेन्सी के अन्दर वे कोई ज्यादा सेक्रिफाइस नहीं करें, त्याग न करें, सिर्फ हमारे वित्त मंत्री और चीफ मिनिस्टर को यह लिख कर दे दें कि हमें जो अतिरिक्त तनख्वाह मिलती है वह एमर्जेन्सी के अन्दर छोडने के लिए तैयार हैं। यह बात भी कर दें जो कि हमें समझना चाहिए इस जनता के ऊपर जितना टैक्स लगाते हैं उसका सबसे ज्यादा भाग उनकी जेब में जाता है। इतना त्याग करने को वे तैयार हों और ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले लोग सिर्फ इतना त्याग कराने के लिए तैयार हों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाखों रुपया हमारे इस प्रान्त का इस तरह से बचाया जा सकता है।

दूसरी बात, आपने जो टैक्स लगाये, इसके अन्दर चार करोड रुपये के और चार करोड रुपये के टैक्स के अन्दर तीन करोड रुपया गरीब किसानों से आप वसूल करेंगे, आप मजदूरों से वसूल करेंगे, छोटे छोटे व्यापारियों से वसूल करेंगे लेकिन आपने उन लोगों को बिल्कुल छोड दिया है, जिनके पास वास्तव में पैसा है। तो जहां इस तरह की बातें आती हैं, वहां समाजवाद नहीं आता है, वहां समाजवाद के सिद्धांत कभी मेल नहीं खाते हैं और इस तरह का बजट जब पेश करते हैं तब हमको इस बात की शंका होती है कि जिस सिद्धांत को आप मानते हैं या आपने अपने मेनीफेस्टों में जो लिखा है, कांग्रेस ने जो सिद्धांत तय किया है, प्रजातांत्रिक समाजवाद, एक वर्गविहीन समाज कायम करने की बात कही है, क्या इन सिद्धांतों के ऊपर आप चल सकेंगे ? बिल्कुल नामुमकिन है। आज किसानों के ऊपर कितना टैक्स है, आपने टैक्सों में वृद्धि की—हासिल बढा दिया, पिलाई बढा दी, आपने जो कन्सोलिडेशन किया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उसका खर्चा उस पर डाल दिया, बेटरमेन्ट लेवी का खर्च उस पर डाल दिया, इसके अलावा आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाये, उनके नीचे की जमीन पर १२ आना टैक्स था, उसके बजाय ४ रु० ६० न. पै. टैक्स लगा दिया, और उसके बाद हैरत हुई यह देखकर कि किसी तरह से किसान ऊंचा नहीं उठ सके इसलिये उस पर २५ पर्सेन्ट ३३ पर्सेन्ट और ५० पर्सेंट टैक्स लगा दिया और पंचायत समिति के ५ पर्सेन्ट का अधिकार था उसको विथड्रा कर लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत अदब के साथ आपके द्वारा ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले लोगों से कहना चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं, जिन्होंने पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हुई बहस का जबाब देते हुए कहा था, "हम यहां बैठते हैं, हमें शौक नहीं है बैठने का। हम इस तरह के टैक्स लगाते हैं तो हमारे लिये यह अच्छी बात नहीं रहती"। तो मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ये ४॥ करोड़ के टैक्स लगाये हैं। इतनी बचत करना चाहें तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को कम करके कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम कर दीजिये। आप मंत्रियों की संख्या में कमी कर दीजिये। और दूसरे फालतू खर्चे हैं उनको कम कर दीजिये। जिन लोगों को स्पेशल पे हैं उसको समाप्त कर दीजिये। जितने प्रेस और सर्किट हाउसेज हैं, डाक बंगले हैं उनको खुद की तरफ से न चलाकर उनको ठेके पर किसी दूसरों को दे दें तो इसमें भी आपको बचत हो सकती है। इस तरह से कई तरह से बचत की जा सकती है। हम एमरजेन्सी के समय में यह ४॥ करोड का टैक्स जो गरीब किसानों पर लगाया जा रहा है वह बचाया जा सकता है, यह नाज पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वह बच सकता है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष:**—अभी उन्होंने बोलना समाप्त नहीं किया है।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया**: पहले भी नाज पर कोई टैक्स नहीं था। यह सरकार खाने और पीने के लिये मुहैया होने वाली चीजों को भी जनता के लिये नहीं दे सकती है। तो मैं इन्हीं के शब्दों को दोहरा कर कहना चाहता हूं कि वह सरकार निकम्मी है जो आदमी को रोजी, पहनने को कपडा, खाने पीने की चीजों को भी नहीं दे सकती, वह सरकार निकम्मी है और ऐसी निकम्मी सरकार को ठोकर मार देनी चाहिये। अगर यही हाल रहा तो वह दिन जनता के सामने दूर नहीं है, जो आज से पहले था, जिस समय आप यह नारा लगाते थे। पब्लिक अब जग गई है और पब्लिक आपको ठोकर मार देगी।

**श्री शीशराम ओला** (खेतडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट हाउस के सामने प्रस्तुत किया गया है उस पर विचार करना है। यह बजट एक ऐसे वक्त का बजट है जब देश कठिन समय से गुजर रहा है। हर लोकतांत्रिक सरकार, टैक्स लगाती है और टैक्स लगने ही चाहिये। प्रजातंत्र में टैक्स लगते हैं उसका मैं विरोध नहीं करता। मैं इसके पक्ष में हूं कि टैक्स लगने चाहिये, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पसन्द नहीं हैं,

(श्री शीशराम ओला)

जनता के लिये हितकर नहीं हैं । इसलिये मैं अपने विचार उन पर रखता हूं।

लैंड रेवेन्यू पर जो टैक्स लगाया गया है यह कतई वाजिब नहीं है; और नहीं लगना चाहिये। मैं बताऊं कि क्यों लगना चाहिए दूसरे अनाज पर जो टैक्स है वह उचित नहीं है और नहीं लगना चाहिये । तीसरा जानवर पर टैक्स लगाया गया है, यह भी नहीं लगना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि ये तीनों टैक्स उचित नहीं हैं और नहीं लगने चाहिये । अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स उन लोगों पर लगने चाहियें जिनके पास कुछ होता है और उन पर नहीं जिनके पास कुछ नहीं होता है। जब आपके पास कोई बैंक बैलेन्स नहीं है तो बैंक वाले आपके चैक को रिटर्न कर देते हैं, पेमेन्ट नहीं करते । इसी तरह से आप टैक्स लेना चाहें तो उन लोगों से लें जिनके पास है और जिनके देने की कैपेसीटी नहीं है, अगर आप उनसे टैक्स मागेंगे तो वे आपको क्या देंगे ? मैं यह कहूंगा कि किसान ने आपको तन, मन और धन तीनों चीजें दी हैं। चीन ने हिन्दुस्तान पर जब आक्रमण किया तो किसान ने अपने आप को दिया, तन दिया, मन दिया और धन दिया । किसान आपको डिफेन्स में पैसा देने से पीछे नहीं रहा । उसने दिखाया कि वह सरकार के साथ है और आज किसान ने यह दिखा दिया कि वह मुल्क के प्रति कितना बफादार है । आज गंगानगर जिले ने हिन्दुस्थान में राजस्थान के नाम को उज्ज्वल किया है उसी तरह से झुंझुनूं जिले में धन और जवान देकर उस जिले ने अपना नाम उज्ज्वल किया है। उधर राजस्थान के लोगों ने युद्ध में लडते हुए वीरगति को प्राप्त होकर वीरता दिखाई है और प्रेरणा दी है । उसमें उदाहरणार्थ स्वर्गीय मेजर शैतानसिंह, दूसरे ले० इन्द्रराजसिंह हैं और एक जमांदार हैं जिनको वीरचक्र मिला है जिनका नाम हरिरामजी है । इस तरह से हमारे किसानों ने देश की सेवा और रक्षा के लिये तन, मन और धन सब देकर योग दिया है और आज हम उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं । आपने उसको सेवाओं के बदले में क्या दिया है ? आपने उनको मिट्टी के टीबे दिये । जो १५ वर्ष पहले नहीं थे । आपने डैजर्ट को रोकने की कोशिश नहीं की और हवा के कारण अच्छे से अच्छे खेतों में मिट्टी के टीबे बन गए । जो आज से १५ वर्ष पहले जमीन थी वह नहीं रही।

आप एक तरफ तो जयपुर में देखते हैं और दूसरी तरफ जब हम गांवों में जाते हैं तो महसूस करते हैं कि गांवों में रहने के लिये मकान नहीं हैं । आप देखते हैं कि गांव के लोगों के लिये रहने के लिये मकान नहीं हैं और उनको खाने को पूरा भोजन नहीं मिलता है। दोनों समय उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता और दो सब्जी तो दूर रहीं वे लोग चटनी बांट कर लूखी (रूखी) रोटी खाते हैं । आज आपने उस बाजरे की रोटी पर जो टैक्स लगाया है, यह उचित नहीं है । उधर उनके यहां पर कोई गांवों में सुधार नहीं हुआ है । उनकी वही हालत है जो आज से २० वर्ष पहले थी। उनके कच्चे मकान हैं जिनके बाडें लगी हैं और वहां पर रात को सांप निकलते हैं और कोई रात को पेशाब करने के लिये उठता है तो सांप उनको खा जाता है। उनके लिये कोई वहां पर अस्पताल नहीं, जबकि यहां शहरों में जानवरों तक के लिये हॉस्पिटल्स हैं । अगर कोई जानवर

(श्री शीशराम ओला)

बिमार हो जाता है तो उसको हॉस्पीटल में इलाज के लिये ले जाया जा सकता है लेकिन वहां गांवों में मनुष्यों के लिये भी, जो हिन्दुस्तान का बडा कीमती जवान होता है, पेशाब करने के लिये उठता है तो सांप के काटने से बच नहीं सकता। उसको रोने वाले घर के रोकर बैठ जाते हैं। इसी तरह से यहां पर औरतों के लिये जच्चाखाना मौजूद है और वहां पर बहादुर औरतों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं। जापे के समय उनको कोई दवा तक नहीं मिलती है और जो बच्चा होता है वह अक्सर मर जाता है। न मालूम वह बच्चा किस तरह का होता और बडा होने पर कितना होनहार व बहादुर होता, या नेता बनता, बेमौत वह मर जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उन गरीब किसानों के लिये और गांवों में रहने वालों के लिये न पूरा खाने का प्रबन्ध है, न पहिनने का और न इलाज का। यहां पर जानवरों के जापे के लिये हस्पिटल हैं, मगर किसानों के यहां इन्सानों के जापे के लिये भी कोई हास्पीटल नहीं है।

दूसरी तरफ एक फौजी जिसकी बुढिया माता है जिसने अपने पति और जवान लडके को लडाई में देश की रक्षा के लिये भेजा और वह मारा गया है उस बेचारी बुढिया पर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। उसने अपने बच्चों और पति का देश के लिये बलिदान किया कि उसको कुछ इनाम मिलेगी मगर आज आप उसको इस प्रकार की इनाम दे रहे हैं। उसका पति लडाई में मारा गया, बच्चा मारा गया उसकी ईनाम उसको मिली कि ज्यादा टैक्स दो। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि टैक्स नहीं लगने चाहियें, मगर मैं यह कहूंगा कि टैक्स उन लोगों से लेने चाहिये जिनके पास देने की शक्ति हो। हमने किसानों के लिये क्या किया है उसके खाने में कोई सुधार नहीं हुआ न उसके मकानों में सुधार हुआ। फिर हम टैक्स उनसे किस बात का लेते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका अनुमान आपको क्यों नहीं? वह बाजार में जाता है और चीजें खरीद कर लाता है उस समय उसको कपडे पर टैक्स देना पडता है, लकडी लाता है तो लकडी पर टैक्स देना पडता है, जब वह खरीदता है तो उसको टैक्स देना पडता है और जब वह बेचता है तो उसको टैक्स देना पडता है। अब आप उससे जमीन का भी टैक्स मांग रहे हैं।

आप देखिये, टैक्स के लिये एक आदमी की इन्कम ३ हजार मानी है, इससे कम आय वाले से टैक्स नहीं लिया पर शायद ही किसी किसान की ३ हजार की आमदनी होती है। जोकि अनइरिगेटेड एरिया में रहते हैं। वहां कभी वर्षा नहीं होती है, कभी टिड्डियां आ जाती हैं तो कभी अनाज पकन की हालत में आता है तो वर्षा नहीं होती है और इस तरह १० वर्ष में शायद ही एक फसल मिलती है, जिससे वह अपना सारा काम चलाता है। बालबच्चों को खिलाता है, पढाता है, सारे कर्म करता है, इतनी सी इन्कम से वह कैसे जी सकता है, इस पर आपने उस पर टैक्स लगाया है, वह यह टैक्स कहां से देगा, इस बात पर तो आपने खयाल किया ही होता।

इसलिये मैं इनका जोरदार विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो तीन टैक्स लगाये हैं वे नहीं लगने चाहियें।

(श्री शीशराम ओला)

आप हालांकि इसे मजाक समझेंगे पर वास्तव में यह मजाक नहीं है। होली के दिनों में किसान स्वांग निकालते हैं, जिसे फोक डान्स कहते हैं। तीन आदमियों ने स्वांग बनाया, एक ने मालदार का स्वांग बनाया दूसरे ने सरकारी अधिकारी, आई. ए. एस., आर. ए. एस. का स्वांग बनाया और तीसरा किसान बना। जो मालदार बना उसने कहा, टिर्डक डम, तो जिसने सरकारी अधिकारी का स्वांग बनाया था उसने कहा, 'खुशी न गम, खुशी न गम'; इस पर तीसरा किसान बोला, "मर गये हम, मर गये हम"। पहले मालदार ने टिर्डक डम कहा तो सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमें न तो खुशी है और न गम क्योंकि हम तो कुछ भी हों जैसे तैसे करके काम चला लेंगे। इस पर किसान कहता है कि मर गये हम, मर गये हम; मुश्किल किसान को है। इसे आप मजाक न समझें, किसान लोग होली पर इस तरह का स्वांग निकालते हैं। तो आज आप याद रखें कि आपका किसान भोला नहीं रह गया है, आपका किसान इतना भोला नहीं है कि वह यह भी न समझ सके कि तेरा भला कहां है और बुरा कहां है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम लोग खासतौर पर जो बोर्डर पर बसते हैं, झुंझुनं जिले में है, जो बोर्डर का जिला है, पंजाब में हमारा रिश्ता, संबंध आना जाना है, महेन्द्रगढ, हिसार सब डिविजन का इलाका इससे लगता है। हमारे खेतों में जब कभी हमारे इलाके में बारिश नहीं होती है तो हमारे मवेशियों को उनके वहां चरने के लिये डाल देते हैं और उनके यहां बारिश नहीं होती है तो वे लोग अपने मवेशी हमारे यहां डाल देते हैं, चर-कर उधर के मवेशी वहां चले जाते हैं और इधर के मवेशी इधर चले आते हैं। तो यह जो आपने पशुओं पर टैक्स लगाया है तो यह कौन मानेगा कि हमारे मवेशी पंजाब में चरने गये थे और पंजाब वालों के हमारे यहां आये थे। तो यह पशुओं पर टैक्स लगाना बहुत अनुचित है। यह टैक्स नहीं लगना चाहिये इससे बहुत करप्शन बढेगा।

इसके बजाय, राजस्थान में सात हजार पंचायतें हैं उन सबमें ग्राम सेवक रखे हैं, ग्राम सेवक की पंचायतों में कोई उपयोगिता नहीं है, हर पंचायत को एक ग्राम सेवक दिया हुआ है तो यदि आप ग्राम सेवकों को हटा दें तो इनसे ७५ लाख रुपयों की आपको बचत हो जायगी और इस तरह आपको पशुओं पर टैक्स नहीं लगाना पडेगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री मोहनराज!

**श्री मोहनराज** (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सामने बजट प्रस्तुत हुआ है और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसपर क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिये मैं इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम नियोजित विकास में और आयोजना के अनुसार प्रगति करने में विश्वास करते हैं तो हमारे लिये उस प्रगति के लिये आवश्यक साधन जुटाने पडेंगे। वे साधन किस प्रकार जुटा सकते हैं, यह सोचने की बात है। हम देखते हैं कि साधन या तो करों से उपलब्ध किये जा सकते हैं या बाहर की सहायता से, उधार के रूप में लेकर साधनों को मुहैया किया जा सकता है

(श्री मोहन राज)

सबसे पहली बात यह अर्ज करना चाहूंगा कि हम लोग एक स्वर से कहते हैं और मानते आये हैं कि राजस्थान हिन्दुस्तान में एक पिछडा हुआ इलाका है और इसका कारण हमारे साधन सीमित हैं, हम अपने साधन नहीं जुटा पाते। अगर हम दूसरे राज्यों की भांति प्रगति करना चाहते हैं तो भारत सरकार के ऊपर भी जबाबदारी है कि हमें आगे बढाने के लिये विशेष सहायता प्रदान करे। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे पिछडेपन को देखते हुए, हमारी गरीबी को देखते हुए, जैसा हमारे सारे देशवासी, और नेता कहते आये हैं, हम खुद कहते आये हैं, यहां सुना ही जाता है, भारत सरकार के सामने एक विशेष मांग रखें और उन्हें कहें कि अधिक से अधिक (उधार) सहायता द्वारा हमारी सहायता करें। भारत पिछडा हुआ है तो अमेरिका सहायता प्रदान करता है, रूस सहायता प्रदान करता है, जर्मनी और जापान हमारी सहायता के लिये आते हैं तो क्या बात है कि हमारे देश में हमारा राज्य सबसे पिछडा हुआ है तो हमारी ही भारत सरकार हमारी सहायता न करे?

हमारे सभी नेता कहते हैं कि इस समय राजस्थान में प्रगति की योजनायें बन रही हैं; राजस्थान केनाल, चम्बल बांध और दूसरी योजनायें चल रही हैं, कल-कारखाने खोल रहे हैं, १० साल बाद राजस्थान का नक्शा बदल जायगा। तो मैं राजस्थान सरकार से अपील करूंगा कि १० साल बाद राजस्थान की धरती जिस पर रेत के टीले हैं, वहां अनाज के ढेर पडे मिलेंगे, हमारी खानों से सोना निकलेगा कल-कारखाने खुलने से लोगों की माली हालत बहुत सुधर जायेगी तो १०–१५ साल बाद ही हम पर टैक्स लगाइये, उस समय हम हमारी तरक्की के लिये ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के जो दूसरे हिस्से पिछडे रह जायेंगे, उनको आगे लाने के लिये भी टैक्स देंगे। मगर आज हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम टैक्स दे सकें। आज हमारी गिरी हुई आर्थिक स्थिति है उसको भारत सरकार के सामने रखना चाहिये और सहायता के लिय अर्ज करना चाहिये।

जिन टैक्सों का आम लोगों में विरोध हो रहा है वह वास्तविक विरोध है, भावना का विरोध कह कर टालना उचित नहीं होगा। यह जो जमीन के लगान पर टैक्स लगाया गया है उसके लिये अर्ज करूंगा कि यह टैक्स वास्तव में हमारे किसानों की हालत को और भी बदतर बनाने वाला है।

योजनाएं ऐसी हैं कि हमारा किसान खुशहाल होगा, पर राजस्थान का किसान सदियों से शोषित रहा है। उसका अपनी जमीन पर कुए पर अधिकार नहीं था, उसकी रहने की झोंपडी पर उसका अधिकार नहीं था, आज यहां तो कल वहां खदेडा गया, किन्तु किसान आज इस हालत में आगया है कि नंगे तन पर लंगोटी बांधे और आज हम उसकी लंगोटी भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, यह कह कर कि १० साल बाद कीमखाब के कपडे होंगे, मखमल और जरी के कपडे तेरे शरीर पर होंगे, आज तेरी लंगोटी छीनकर हम विकास करेंगे तो मैं कहूंगा कि जो जरी और मखमल के कपडे पहिनते हैं, जो आराम तलब बंगलों में रह कर आराम करते हैं, उनसे पैसा लेकर आप इन गरीबों की लंगोटी को सुधारें, आवश्यकता आज इस बात की है।

(श्री मोहनराज)

मैं यह नहीं कहता कि अगर टैक्स वसूल नहीं किये गये तो हमारी क्या हालत होगी ? जितना कर आप इस भूमि पर से वसूल करना चाहते हैं उतना आप और तरह से वसूल कर सकते हैं, इसके सीधे उपाय हैं। कई जगह ५०—६० वर्ष पहले की भूमि का लगान बंधा हुआ है, जो बहुत कम है, जहां लगान नया लगा है, वहां प्रति बीघा बहुत लगान लगा है। तो आपके पास समेरी सैटलमेन्ट का कानून मौजूद है, उसके तहत जहां भूमि की तरक्की हुई है, जहां हालत सुधरी है, वहां लगान बढा देते हैं तो किसानों को एतराज नहीं होगा और अपने आप इस तरीके से यह आमदनी हो जायगी जो आप इस टैक्स से वसूल करना चाहते हैं। इस तरह न भ्रष्टाचार बढेगा, न आपको मशीनरी बढानी पडेगी। एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कलैक्टिग मशीनरी है, उस ही से यह वसूली हो जायगी, नई मशीनरी नहीं बढानी पडेगी।

दूसरा एक उपाय और है और वह उपाय यह है कि आपके जो लम्बरदार, जो लगान वसूल करने के नाम रुपया लेते हैं, मैं ख्याल करता हूं कि यह जो लम्बरदारों की संख्या है वह बिलकुल गलत है। इससे गांव में झगड़े होते हैं, रिश्वतखोरी और भ्रटाचार बढ़ाने की एजेन्सी के रूप में वह काम करती है इसको हठा दें। आपका एक लाभ हो जायेगा। दूसरी बात मैं अर्ज करता हूं वह यह है कि आपने अनाज पर टैक्स लगाया है यह बहुत बूरा है। इस पर यह कहा जा सकता है कि अनाज पर टैकस लगाना लैंड पर टैक्स लगाना, यह तो भावनां की बात हुई भावना में नहीं बढ़ना चाहिए, भावना में बढ़ने से किसी राज्य का शासन तंत्र नहीं चलाया जा सकता। भावना में नहीं बढ रहा हूं। सामाजिक और आर्थिक जीवन में भावना का बड़ा महत्व है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर सिर्फ भावना की बात होती तो नमक पर टैक्स नहीं लगा है उस पर भी टैक्स लगाने की बात होती। खाने के लिए सेर, डेढ़ सेर अनाज दोनो वक्त काम में आता है किंतु नमक तो तोला भर ही चाहिये। उस पर क्यों नही टैक्स लगाया ? खार मिट्टी का भी महत्व है। उसके साथ भावना जुड़ी हुई है। सैर डेड सेर अनाज दोनों वक्त पेट भरने के लिए चाहिये। क्या हमारी भावना का प्रभाव वहां नहीं रहेगा ? क्या नहीं भावना का भी महत्व है और उसी दृष्टी से इसको सोचना चाहिये।

कुछ सुझाव दे रहां हूं जिससे जो घाटा टैक्स न लगाने से होगा उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पूर्ति के साथ साथ जो एक दूसरी चीज उसके साथ साथ होगी उन टैक्सों की वसूली में जो भ्रष्टाचार हो सकता है, टैक्सों का छिपाव हो सकता है वह नहीं, होगा। सदन में कहा जा चुका है कि जो लेन देन का काम करते हैं मनी लैन्डिग का काम करते, फाइनेनसियर का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, उन पर टैक्स लगा दिया जाय। लाइसेन्स फीस लागू कर सकते हैं। जो कोई लेन देने का धन्धा करता है, बैंकिंग का काम करता है, फाइनेनसियर का काम करता है उसकी लाइसेन्स फीस प्रति व्यापारी ५०) रु. रखते हैं; तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान से ८० लाख रुपये से लगा कर १ करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। आप मुझे कहेंगे कि मैं ओवर एस्टीमेट कर रहा हूं। आप अन्दर

Page No.39



(श्री मोहनराज)

एस्टीमेट करते आते हैं और आपका खुद का अनुभव होगा कि आपको अन्डर एस्टीमेट के कारण टेक्सों की आमदनी ज्यादा हुई। मैं कह रहा हूं वह सही हालत हैं। इस तरह यदि लाइसेन्स टैक्स लगाया जाय तो ८० लाख से १ करोड़ तक की आमदनी आपको हो सकती है। एक और लाइसेन्स है। यह दस पन्द्रह वर्ष से लागू था। जो बड़े बड़े अनाज के व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं उनसे १५) रु. लाइसेन्स के लिए जाते थे कुछ अर्सा हुआ यह लाइसेन्स खत्म कर दिया गया। यदि इस प्रकार के लाइसेन्स को पुनः रिवाइव किया जाय तो ५० लाख से अधिक आमदनी हो सकती है। यदि आप ये दो चीजें करेंगे तो में समझता हूं कि आपने जो घाटे का बात कही है वह पूरी हो जायेगी और इस प्रकार अनाज पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रहेगी।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन लाइसेन्सज की रकम वसूली है, इसके लिए दूसरे टैक्सों की वसूली के लिए जो मशीनरी है उसको काम में मत लाइये। आपने नये टैक्सों से आमदनी का खर्चा दिया है उसमें बताया गया है कि ६० लाख रुपया पंचायत और पंचायत समितियों को अनुदान के रुप में देंगे। ये जो दो प्रकर के लाइसेन्सेज हैं जो मैंने भी आपको सजेस्ट किये हैं उनकी रकम की वसूली का काम आप न्याय पंचायतों के ऊपर छोड़ दीजिये और उससे जो आय होती है उसका पंचायतों और न्याय पंचायतों में बराबर बंटवारा हो जाय। अगर आपने तहसीलों के जरिये लाइसेन्स वसूली का काम रखा तो २५ प्रतिशत भी वसूली नहीं होगी। पंचायतों और न्याय पंचायतों को मालूम है कि कौन कौन मनीलेंन्डिग का धन्धा करते हैं और कौन कौन अनाज के व्यापारी हैं और कौन कौन स्टाकिस्ट हैं। वे लोग रात दिन वहां रहते हैं और जो सूट होते हैं उनको वह मालूम होता है। इसके लिए आप पांच प्रतिशत शेयर पंचायतों के लिए रख छोड़ये। इससे उनको आमदनी भी होगी।

**बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री)**: मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अभी लैंड रेवेन्यू टैक्स के खिलाफ कह रहे थे और साथ साथ दलील दे रहे हैं कि पांच परसेन्ट पंचायतों को उससे हिस्सा मिलना चाहिये।

**श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : वित्त मंत्रीजी समझे नहीं हैं।

**श्री मोहनराज** : मेरा ख्याल है सब माननीय सदस्य समझ गये हैं, लेकिन वित्त मंत्रीजी की खातिर दोहरा देता हूं। जो पांच प्रतिशत आमदनी पंचायतों को मिलनी चाहिये वह इस रूप में है कि जो लाइसेन्सज इन्ट्रड्यूस करने के लिए मैंने सुझाव रखे हैं मनीलेन्डर्स और ग्रेनडीलर्स लिए उनसे प्राप्त होने वाली रकम की वसूली पंचायतों को करनी चाहिये और इसके लिए उनको पांच–सात पर्सेन्ट कलेक्शन चार्जेज के रूप में दें। टैक्स बेकार नहीं जावेंगी। बच नहीं पायेंगे और पूर्ण रूप से वसूल हो जावेंगे। संक्षेप में एक बात और अर्ज करूंगा। ग्राम सेवक के लिए कहा गया ग्राम सेवक पंचायतों में लगाये जाते हैं। अब उनका खर्चा बचाया जा रहा है। मैं नम्र शब्दों में निवदन करूंगा कि अगर सारे राजस्थान में ग्राम योजना और अन्नोत्तपादक योजनाओं को महत्व देना है तो ग्राम सेवक का पंचायतों में रहना

(श्री मोहनराज)

आवश्यक है। प्रोडक्शन प्लान बनाने वाले हैं और इस प्रकार की योजना हम जारी कर रहे हैं। यदि कोग्रॉपरेटिव और पंचायत दोनों को मिला कर, दोनों का तालमेल जोड़ कर वह चीज़ आगे नहीं बढ़ायेंगे तो हमारा विलेज प्रोडक्शन फेल हो जायगा, ठप्प हो जायगा और मेरा ख्याल है कि वह कागजी योजना मात्र ही रह जायगी। ग्राम-सेवक आता है तो सहकार और पंचायत दोनों में तालमेल बिठा कर वह योजना कार्यान्विति सहयोग देना। इस में किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहिये। विकास बढ़ रहे हैं। अनुभवों का आधार होगा। अनुभवों के आधार पर यह देखें कि ग्राम सेवक का गांव के अन्दर रहना आवश्यक है। उनके बिना गांव की जिन्दगी को बेकार कर रहे हैं। गत दस वर्ष के अनुभव के नतीजे पर यह पहुंचा जा सकता है कि एक गांव में एक ग्राम सेवक रखा जाय। प्रायोरिटी फिक्स की है प्रोडक्शन प्रोग्राम बढ़ाना चाहते हैं उस पर जोर देना चाहते हैं तो ग्राम सेवक का रहना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि ये जो सुझाव दिये हैं उन पर गोर करेंगे। जो टैक्स लगे हैं उनसे गरीबों को राहत नही मिल रही हैं, उनसे अधिक लिया जा रहा है उनको राहत देंगे और ऐसा बजट तैयार करेंगे कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो और सही माने में समाजवाद की ओर आगे बढ़ें।

**अनेक माननीय सदस्य**: उपाध्यक्ष महोदय . . .

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री विजयसिंह झाला।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जो बहस हुई बजट के बारे में उससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस बजट में हमारे वित्त मंत्री के दिमाग ने काम नहीं किया है। दरअसल जिस दिमाग ने काम किया है वह अधिकारियों के दिमाग ने काम किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों की सही स्थति को नहीं समझते जो ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को चिट्ठी समझ कर फाड़ कर फ़ेंक देते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जो में अभी नहीं रखना चाहता, किन्तु कटोती प्रस्ताव आवेंगे जब रखूंगा।

तो यह इस प्रकार के अफसरों के दिमाग द्वारा काम किया हुआ है जो जब कभी विधान सभाई सदस्य किसी योजना के बारे में मिलना चाहते हैं तो यह कह कर कि उनके पास समय नहीं है किसी क्लर्क को बता देते हैं। यह बजट ग्रामीण क्षेत्र के बारे में नहीं उनसे हम इस प्रकार का बजट बनाने की उम्मीद भी किस आधार पर कर सकते हैं ? लेकिन हमारे वित्त मंत्री ऐसे नहीं जो उचित-अनुचित का ध्यान रखें, उनके सामने जैसा ही बजट आया उन्होंने निद्रावस्था में हस्ताक्षर कर दिये। उन्होंने पढा तक नहीं, पढते तो इसके लिये सजेशन अवश्य देते। हमारे वित्त विभाग के लिये नौजवान मंत्री की आवश्यकता है। अगर हमारे वित्त मंत्री के अपने उप-मंत्री यदि इसमें टांग फंसाते तो यह रूप बजट का हमारे सामने नहीं आता।

**एक माननीय सदस्य** : वे तो मुकम्मिल जवान हैं।

**श्री विजयसिंह झाला** : आपका भाषण जो हमने सुना उसमें उन्होंने एक बडी भारी रियायत दी देशी जूते के बारे में। उनको बडी मोहब्बत है देशी जूते से। लेकिन उनसे

(श्री विजयसिंह झाला)
मेरा निवेदन है कि जिस दिन किसान इस जूते को समझ जायगा तो वह मोहब्बत महंगी पड जायगी। किसान के पास किसी प्रकार के दूसरे साधन नहीं जो वे अपने लिये अन्य साधन ढूंढ सके। मैं उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थितियों को देखते हुए दरअसल कमी करनी चाहिये, लेकिन बजट के अन्दर उनके दिमाग ने काम नहीं किया, नहीं तो दरअसल में जो कर बढाये हैं, भू-राजस्व पर कर बढाया है वे नहीं बढाते। सदन ने देखा कि इस चार करोड की आय में ९० करोड रुपया तो पंचायतों को सहायता के रूप में देने के लिये हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): ९० करोड नहीं; ९० लाख आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है।

**श्री विजयसिंह झाला** : जब मैं आपके सामने खड़ा होता हूं तो मेरा दिमाग भी चक्कर काटने लग जाता है। ९० करोड़ नहीं ९० लाख रुपया पंचायतों को सहायता के रूप में देने के लिये कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि सदन को यह धोखा देने की चेष्टा की गई कि पंचायतों का ९० लाख रुपया सहायता के रूप में दिया जायगा, लेकिन यह नहीं कहा, वह भी किसानों की ही जेब से टैक्स के रूप में निकलेगा, ५० लाख रुपये के दूसरे साधन जुटाये जायेंगे इस तरह से ये टैक्स ४ करोड ४० लाख के हो जायेंगे जिसमें से २.२५ भू-राजस्व वसूल होंगे, उसके बाद में ५० लाख के अन्य, इस तरह से सीधे ३ करोड के टैक्स किसानो पर पडेंगे जहां आपने किसानों से १९५५ में वादा किया था कि हम किसी प्रकार का कर इन दो योजनाओं में नहीं लगायेंगे, १९५४-५५ को एक संकल्प के ऊपर बहस करते हुए आपने कहा था कि अन-इकोनोमिक होल्डिग पर कोई कर नहीं लगेगा आज आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। इस तरह से आपके अपने सिद्धान्त से आप दूर होते चले जा रहे हैं। आप यह मत समझिये कि आपकी कुर्सियां इस तरह से सही सलामत रह जायेंगी। अब बहुत दिन नहीं, आपने किसानों पर इसी प्रकार टैक्स लगाने की चेष्टा की तो आपको बहुत ही जल्दी इन कुर्सियों से नीचे उतरना होगा, चिन्ता न करिये।

**एक माननीय सदस्य** : इनको चिन्ता तो बुढापे की है कि आगे क्या होगा?

**श्री विजयसिंह झाला** : मुझे आप गोद नहीं रखने वाले हैं।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री): सिर पर तो बैठ सकता हूं।

**श्री विजयसिंह झाला** : इसके बाद में स्टाम्प ड्यूटी आपने बढायी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि न्याय सस्ता मिलेगा। १९५१ में, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं जब पार्टनरशिप का डॉक्यूमेन्ट लिखते थे १० रुपये खर्च होते थे, आज उसी में ३० रुपये खर्च होते हैं। आज तिगुना खर्च करना पड रहा है, न्याय महंगा हो गया, किसान तंग होगया।

आप सेल्स टैक्स का प्रोसीजर देख लीजिये कहीं कहीं तो दो-दो बार सेल्स टेक्स देना पडता है। लास्ट पोइन्ट पर और फर्स्ट पोइन्ट पर क्योंकि इसकी परिभाषा नियत

(श्री विजयसिंह झाला)

नहीं की हुई है। मेथी और कपास जब छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से लेता है तो वहां पर उसको टैक्स जमा कराना पडता है बाजार में बेचता है तो टेक्स जमा कराना पड़ता है। उसी तरह उपाघ्यक्ष महोदय, लग्जरीज पर टैक्स बढ़ाया है जिनमें दंत मंजन को भी लग्जरीज में माना गया है । इससे ऐसा मालूम होता है कि हमारे मंत्री महोदय को लग्जरीज की परि–भाषा मालूम नहीं कि एक मिनिस्टर के बंगले पर जहां लग्जरीज का सामान लगा हुआ है उस पर तीस पर्सेन्ट टेक्स बढा दीजिये, लेकिन वहां पर नहीं गरीबों के जो चीजें काम में आती हैं उन पर आपने टैक्स बढाया है . . . .

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): आपका मतलब है, मिनिस्टरों के २२ हजार का फर्नीचर लगा है उस पर टैक्स बढ़ायें?

श्री **विजयसिंह झाला** : रेफरीजेटर है, कूलर है, इन पर टेक्स बढ़ा सकते हैं। लग्जरीज की चीजें तो ये हैं। लेकिन जो चीज जनसाधारण के काम में आती है उनको आपने लग्जरीज में ले लिया है

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपने सिद्धान्तों की हत्या ही कर दी है तो आप खादी पर टैक्स बढा दीजिये। जो बिजनेस पोइन्ट ऑफ व्यू से पहनने के काम में लेता है जिसको पहनकर किसी मिनिस्टर साहब के सामने अधिकारी जाते हैं और अपना काम निकलवा लेते हैं। इसके बजाय आपने जो अनाज पर टेक्स लगाया है उसको हटाइये। और चीजों पर आप भले ही लगाइये, कम से कम अनाज को तो छोड़ दीजिये।

इसके अलावा भी टेक्स प्राप्त करने के साधन थे। बड़े बड़े होटल हैं। जिनको लाखों की आमदनी होती है उन पर पैसा बढा दीजिये। इसके अलावा और कुछ मैं सुझाव रखना चाहता हूं। कभी आपने कोशिश की आपकी बकायात कितनी बाकी है और आपके टैक्स सही रूप में वसूल होते हैं या नहीं। उदाहरण तौर पर आपसे निवेदन करूं उदयपुर के बडे सेठों में आपका सेल्स टैक्स का पौने दो करोड़ रुपया बाकी है, कभी आपने कोशिश की है उसको वसूल करने के लिये।

इसके अलावा आर. टी. ओ. के अन्तर्गत जो आपकी गाडियां चलती हैं उनमें भी सेल्स टैक्स का पांच करोड रुपया बाकी है। इसी प्रकार और जहां गाडियां चलती हैं उनमें से भी १.७० लाख रुपया सेल्स टैक्स का बाकी है । इसी प्रकार आप सेल्स टैक्स विभाग को देखें, आपकी इतनी रिकवरी बाकी है कि आप उसको वसूल करने लगो तो आपको ये टैक्स ही लगाने न पड़ें ।

इसी प्रकार आपके सिनेमा में भी काफी रकम बाकी है । अशोक सिनेमा में ३ लाख रुपया बाकी है, क्या उसको वसूल करने की कार्यवाही चल रही है ? इसी प्रकार प्रेम प्रकाश में लाखों रुपये की बकाया है, राम-प्रकाश सिनेमा में आपकी बकाया है; आप इन बकायत को वसूल कर लें तो आपको टेक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पडेगी ।

इसके अलावा जो आपके यहां पैसों का दुरुपयोग होता है उसको भी रोकिये । आपकी ठेकेदारी प्रथा को देखिये । ठेकेदारी प्रथा के

(श्री विजयसिंह झाला)

अन्दर आपके पैसे का कितना दुरुपयोग होता है। इस ओर ध्यान दीजिये। ठेकेदारों के मार्फत जो खर्चा होता है उसका सही रूप से उपयोग नहीं होता। अभी बनास पर जो पुल बांधा गया है उसका उद्‌घाटन राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया, उसके बाद ही उसका एक ढोला क्रेक हो गया। इस तरह से ठेकेदारों के जरिये काम भी ठीक नहीं होता और पैसे का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकिये। इसके साथ साथ ठेकेदारी की फीस को बढ़ाइये ताकि आपकी आमदनी भी बढ़े।

इसी प्रकार जहां आर. ए. एस. आफिसर्स की पोस्ट्स हैं वहां आपने आई. ए. एस. अधिकारी को लगा रखा है उनको हटाइये। ट्रान्सपोर्ट अधिकारी जो आर. ए. एस. की पोस्ट है उसकी जगह आपने आई. ए. एस. अधिकारी को लगा रक्खा है, इससे खर्चा ज्यादा बढ़ता है; कभी आपने इस तरफ भी निगाहें दौडायी हैं।

पुलिस विभाग में एस. पी. और सी. आई. के बीच में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की क्या जरूरत है? सी. आई. जो कार्यवाही करता है उसको भी एस. पी. के पास जाना पडता है और डी. एस. पी. जो कार्यवाही करता है उसको भी एस. पी. के पास जाना पडता है, तो बीच की डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की पोस्ट की क्या जरूरत है?

इसके साथ ही साथ कहूंगा कि ग्राम सेवकों से ग्रामीण क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ है। अगर असल फायदा उठाना चाहते हैं उनसे तो पटवारी और ग्रामसेवक की पोस्ट को एक कर दीजिये। और पंचायतों को सौंप दीजिये। कुछ क्षेत्रों में ग्राम सेवक ३ पंचायतों को लेकर होते हैं। पर वे भी बैठे रहते हैं, काम उनके पास कुछ नहीं रहता तो काम बढाना चाहिये।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों और तहसीलों की बहुत सी पोस्टें हैं। २।। तहसीलें हैं एक चुनाव क्षेत्र पर, उसको एक तहसील कर दीजिये पंचायत समिति कर दीजिये। आपका खर्चा कम हो जावेगा।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

कौल भाषा में, जिस भाषा को मैं और संज्ञा नहीं दे सकता, आपने जो भाषण दिया और उसके द्वारा आपने जो अमोघ शक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश की है वह उपयुक्त नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : कुमारी उमा माथुर।

**कुमारी उमा माथुर** (रामगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी की इस बात के लिये सराहना करती हूं कि आपत्कालीन बजट को पेश करते हुए भी उन्होंने इस बात का साहस दिखाया कि अपनी पंच वर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में कोई अन्तर नहीं आने दिया। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं उनको कि राजस्थान की जनता देश की सुरक्षा के लिये और पंच वर्षीय योजनाओं के सुचारु सम्पादन के लिये बड़े से बडा त्याग भी करने को तैयार है और इसके परिणामस्वरूप जो भी टैक्स उस पर पडेगा उसको वहन करने को तैयार है।

('नहीं-नहीं' की आवाज)

(कुमारी उमा माथुर)

किन्तु साथ ही साथ इस जनता को यह विश्वास होना चाहिये कि जो वह इतना बडा त्याग करने को तैयार है, अपनी गाढी कमाई के पैसे में से टैक्सों को देने को तैयार है, जो देश की सुरक्षा के लिये अपने पेट काटने को भी तैयार है, उस पैसे का, उन टैक्सों द्वारा प्राप्त किये गये धन का उपयोग सही तरीके से और सफलता से किया जाय। उसका दुरुपयोग न होने दिया जाय। मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि यह सरकार जनता को यह विश्वास दिलाने में सर्वथा असमर्थ रही है। वह विश्वास वह नहीं दिला सकी और जो मितव्ययता के लिये भी विश्वास दिलाना चाहिये था वह भी यह सरकार नहीं दिला सकी।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने बहुत किफायतशारी की, जोरदार शब्दों में चर्चा की है और साथ ही यह भी फरमाया है कि सिर्फ रुपया, आने, पाई में ही बचत का कोई मूल्य नहीं है अगर उससे कार्य करने वालों की कार्यकुशलता पर आघात होता हो। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि यह कार्यकुशलता जिस प्रकार से हर विभाग के स्टाफ में दिनों दिन घटती जा रही है, हर जगह नये नये विभाग खुलते जा रहे हैं उससे निराशा ही हुई है उनमें भी कोई कार्यकुशलता नहीं बढी, बल्कि उल्टी घटी है। यदि वे पिछला रेकॉर्ड इन विभागों के स्टाफ का उठाकर देखें और उससे इस बात का अन्दाज लगावें कि कितना स्टाफ बढा है और जितना स्टाफ बढा है उसके हिसाब से सब पर समान रूप से काम का भार पडा है या नहीं, तो उनको यह पता लगेगा कि वह स्टाफ बढाना सारा बेकार है। साथ ही मैं यह कहने में भी संकोच नहीं करूंगी कि स्टाफ के बढाने के बावजूद भी कार्यकुशलता बढने के स्थान पर घटी है, इन-एफीशियेन्सी बढी है। कोई भी साधारण से साधारण काम रुटीन में नहीं होता, समय पर नहीं होता। एक-एक पत्र के लिये, एक-एक आवेदन-पत्र के लिये, उसका जवाब हासिल करने के लिये आदमी को एक आफिस से दूसरे आफिस में चक्कर लगाने पडते हैं और एक एक कागज का पीछा करना पडता है तब वह कागज उस दफ्तर के चक्कर से निकल सकता है।

(२.२२ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

इसका परिणाम स्पष्ट है और वह हमारे सामने है। आज दफ्तरों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बुरी तरह से बढती जा रही है। लोगों को मजबूर होकर अपना कागज निकलवाने के लिये, अपना काम करवाने के लिये रिश्वतें देनी पडती है। यहां तक कि मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि न्यायालय जैसे स्थान भी इससे अछूते नहीं हैं, बल्कि विशेष तौर से इन न्यायालयों की हालत बहुत खराब है। आपको छोटी से छोटी एप्लीकेशन के लिये, छोटे से छोटे काम के लिये क्लर्क से लेकर प्रिसाईडिंग ऑफिसर तक इस प्रकार की रिश्वतें देनी पडती हैं और इस प्रकार की रिश्वतें हर रोज चलती हैं।

अब मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिये आगाह कर देना चाहती हूं कि अगर वे अपने मन्त्रित्व का बाना उतार कर मेरे साथ चलें इन जगहों पर तो मैं उनको बता सकूंगी

(कुमारी उमा माथुर)
कि किस प्रकार से इन स्थानों पर भयंकर रूप से रिश्वतखोरी चल रही है।

आज इस रिश्वत के बल पर तो कोई भी नाजायज से नाजायज काम इन आपके सरकार के दफ्तरों से कोई भी करा सकता है।

**एक माननीय सदस्य**: very good.

**कुमारी उमा माथुर**: मैं वित्त मन्त्री महोदय के सामने कुछ बातें किफायतशारी के विषय में रखना चाहूंगी। मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने भी कहा था और मैं भी कहती हूं कि आज पंचायत समितियों में बेकार का कुछ स्टाफ पडा हुआ है। उसे वहां से हटाकर काम में लगावें। पंचायत समितियों में कुछ टैक्निकल स्टाफ भी मौजूद है जिसका वहां कोई उचित उपयोग नहीं होता है। एक तरफ हम शिकायत करते हैं टैक्निकल पर्सोनल्स की कमी की व दूसरी ओर आपके असिस्टेन्ट इन्जीनियर, वैटर्नरी डाक्टर और दूसरी तरह के टैक्निशियन, केवल पंचायत समितियों की मीटिंगें अटेन्ड करके अपना समय बर्बाद करते हैं और आपका रुपया व्यर्थ जाता है। एक बार एक वैटेनरी डाक्टर से मैंने पूछा, आप यहां क्या क्या काम करते हैं और अब तक क्या क्या किया ? उसने उत्तर दिया कि जो हमने तीन-चार साल में ट्रेनिंग लेकर सीखा है उसे भुला रहे हैं, पंचायत समितियों की मीटिंगें मात्र अटेन्ड करते हैं और चन्दा जमा कर रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इस मसले पर गौर किया जावे और जिस जगह इस तरह से स्टाफ बेकार पडा है उसका उचित उपयोग लिया जावे और केवल डिसेन्ट्रालाइजेशन के नाम पर टैक्निकल आदमी की नोलेज को बरबाद न किया जावे।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं रेवेन्यू के बारे में। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी न जाने कितनी लम्बी एक कतार लगी है इस विभाग में, जब कि पंचायत समिति बन जाने से एस. डी. ओ., बी. डी. ओ. के हाथ में ये चले गये हैं। इन दोनों को कन्सोलिडेट करके एक सही तरीके से ऐसा रास्ता निकाला जावे जिससे बी. डी. ओ. का उपयोग इन कामों में अधिक लेकर बाकी की पोस्टों को एबोलिश कर दिया जावे और इस तरह से खर्चे में बचत की जावे।

मैं डाक्टरों के विषय में निवेदन करूंगी। राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में सुनाई देता है कि डाक्टरों की कमी है। किसी अस्पताल में ८ के बजाय ३ ही से काम चलाया जा रहा है, किसी में १० के स्थान पर चार ही दे रक्खे हैं। जनता को बडी परेशानी होती है। मेरी जहां तक जानकारी है, और देशों में डाक्टर लोग भी आठ-आठ घंटे काम करते हैं जैसे और दफ्तरों में लोग काम करते हैं वैसे। तो मेरा निवेदन यह है कि इस कमी को देखते हुए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए चार चार और पांच पांच घंटों के लिये ही जिनको आज काम दे रखा है उसके बजाय उनको भी पूरी तरह से आठ घंटों तक यूटिलाइज किया जाय और काम के घंटे उनके भी आठ कर दिये जावें।

इसी तरह टैक्स बढाने के बजाय, नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी आप बढावें और किफायत-

(कुमारी उमा माथुर)

धारी से काम लें तो इन टैक्सों की जरूरत ही नहीं रह जावेगी ।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में समाजवाद की चर्चा बहुत तेजी से की । मैं नहीं समझती कि जो नये प्रोपोज्ड टैक्स हैं वे उससे कहां तक मेल खाते हैं ।

जहां तक स्टाम्प ड्यूटी का सवाल है यद्यपि कुछ लोगों ने न्याय की दुहाई देकर इस टैक्स को नाजायज कहने का उपक्रम किया है परन्तु मैं सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी और विज्ञापन टैक्स आदि के बारे में निवेदन करूंगी कि इनको भले ही बढा दिया जावे, कोई बात नहीं; विलासिता की वस्तुओं के टैक्स को ७ से २० पर्सेन्ट कर दिया जावे, किन्तु विलासिता की वस्तुओं की लिस्ट जो आप देना चाहते हैं उसको ध्यानपूर्वक स्क्रुटिनाइज कर लिया जावे, उसमें दैनिक जीवन की अनिवार्य वस्तुएं न आने पावें । जनरल टैक्स पांच से छ: बढा दिया गया है, इसका मैं घोर विरोध करती हूं ।

आज इन टैक्सों के भार से जनता की कमर टूट पडी है और दिन-रात हमारे काम आने की चीजें इस प्रकार दिन प्रति दिन कन्ज्यूमर्स पर बोझ पडता गया तो जिस जनता के लिये हम समाजवाद लाना चाहते हैं जिसके जीवन स्तर को हम ऊंचा उठाने के लिये अपनी पंच वर्षीय योजनाओं को जल्दी से आगे बढाना चाहते हैं जब तक ये योजनायें कामयाब होंगी तब तक वे लोग शायद खत्म हो जायेंगे । मैं; सभापति महोदय, अनाज पर बडे सुन्दर तरीके से, वित्त मंत्री महोदय ने सुन्दर भाषण में जो कहा है जवार, बाजरा और मक्का को छोडकर यानी जिससे पढने के समय बहुत ही सुन्दर तरीके से ऐसा प्रतीत होता है वित्त मंत्री महोदय ने मेहरबानी करके जवार, बाजरा और मक्का को छोड दिया है और बाकी अनाज पर टैक्स लगाया है मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जवार, बाजरा और मक्का विशेष रूप से ऐसे अनाज हैं जिसको दो वक्त खाकर गरीब जनता अपना पेट भरती है । आप जब समाजवाद लाना चाहते हैं और गरीबी और अमीरी की खाई को मिटाना चाहते हैं तो जो अनाज पेट भरने के लिये उस पर आप टैक्स लगाकर गरीब जनता को दबाना चाहते हैं, यह चल नहीं सकता और जिस जनता से देश की रक्षा के लिए और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिये सहयोग चाहते हैं वह जन्ता अपना मानसिक संतुलन भूखे पेट नहीं रख सकेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुन: विचार करे और टैक्स को हटायें ।

सभापति महोदय, : अब मैं भू-राजस्व कर के विषय में दो शब्द कहना चाहती हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में और हिन्दुस्तान के और स्टेटों के मुकाबले में भू-राजस्व पहले ही अधिक लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप भू-राजस्व इस प्रकार से लगायेंगे कि छोटे से छोटे काश्तकार को भी अगर नहीं छोडा गया तो यह बहुत अन्याय हो जायेगा । इसके अलावा सेन्टर के द्वारा लगाये कम्पल्सरी सेविंग से तो यह किसान पिसकर कहीं का न रह जायेगा । आप यह चाहते हैं कि कृषि का उत्पादन बढे और कृषि के ऊंचे ऊंचे साधन हों, वे सब समाप्त हो

(कुमारी उमा माथुर)
जायेंगे क्योंकि किसान जब पेट भर रोटी नहीं खायेगा, किसी प्रकार का उत्साह उसको आपके द्वारा नहीं मिलेगा तो वह किसी प्रकार का काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सुझाव देना चाहती हूं . . .

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जिससे नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढाकर अपना काम कर सकेंगे। सभापति महोदय, फिल्म इन्डस्ट्री को नेशनलाइज करना स्टेट के हाथ की बात नहीं है किन्तु राजस्थान सरकार अपनी रेवेन्यू बढाने के लिये फिल्म प्रदर्शन को अपने हाथ में ले सकती है और जहां जहां भी सिनेमा हाल बनें उनको अगर राजस्थान सरकार खुद चलाये तो बहुत बडी रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम नये खुलने वाले सिनेमा हालों को राजस्थान सरकार खुद चलाये और खुद ही उसका प्रबंध करे तो इस प्रकार से वह रेवेन्यू का अच्छा खासा सोर्स हो सकता है। इससे दूसरे लाभ भी हो सकते हैं। जो बेहूदी और भद्दी फिल्में आज दिखाई जाती हैं और जनता पर जिनका बहुत बुरा असर पडता है उसको राजस्थान सरकार कम से कम राजस्थान के लिये रोक भी सकती है। इस प्रकार से एक काम से आपके दो साधन पूरे हो सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री, शिक्षा): Point of Order, Sir. The Chair should catch the eye as early as possible.

**श्री सभापति** : श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

एक बात याद रखिये। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, कृपया १० मिनट से ज्यादा किसी हालत में न लें।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई): सभापति महोदया, इस बजट पर . . . .

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना): Point of order, Sir. ऐसा है कि जो टाइम अलाट था वह कांग्रेस पार्टी को कम मिला है। अपोजिशन पार्टी ने सारा टाइम ले लिया है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को बोलने का मौका मिलना चाहिए।

**श्री सभापति** : पार्टी को जो टाइम दिया गया था उसमें २१ मिनट इनके और हैं।

**श्री नत्थीलाल** (भरतपुर): हमारा यहां आने का क्या मतलब है, हमें कोई बोलने नहीं दिया गया।

**श्री सभापति** : श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई): सभापति महोदय, इस बजट पर गत तीन दिनों से वाद-विवाद चल रहा है। उस दौरान में जो माननीय सदस्यों की तकरीरें हुई उनसे एन हकीकत तो इस सदन के सामने आई कि सारे सदस्यों ने इन टैक्सों का विरोध किया है और सरकार की जो इनएफीशियेन्सी और एडमिनिस्ट्रेशन की अव्यवस्था है उसके ऊपर असंतोष प्रकट किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि आपकी जम्हूरियत के अन्दर जम्हूरियत की कद्र करते हुए इस हकीकत को पहचानने की कोशिश करें कि आपकी पार्टी के सदस्य भी इन लगे हुए टैक्सों का विरोध कर रहे हैं, और मैं यह

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

समझता हूं कि वह इन जज बात को पहचानते हुए जनता को इन लैण्ड रेवेन्यू, सीरीयल्स और अनाज के टैक्सों से राहत देने की कोशिश करेंगे, वरना आपकी भी वही हालत होने वाली है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप तो पैरासूट से आये हैं। आप इसमें न रहें कि आपकी इस नीति की एक सदस्य भी ताईद नहीं करता आपकी तारीफ नहीं करता यह यह आपके लिए एक हकीकत पहचानने की चीज है। मैं समझता हूं कि आप इससे सबक लेंगे और इस सबक को लेते हुए अपनी जिद्द को नहीं रखते हुए जनता को राहत देंगे, और यह पहचानेंगे कि आप अगर कायम रहना चाहते हैं, आप सरकार को कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि इस हकीकत को पहचानते हुए जनता को इससे राहत दें।

मैं साथ ही आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपके बजट से एक चीज मिलती है कि आप टैक्स लगाकर सरकार की आमदनी के जरिये की वकालात करते हैं कि आपको पास करके मन्जूरी दे दें लेकिन आप अपने दूसरे फर्ज को नहीं पहचानते कि आपका यह भी फर्ज है कि जो खर्च होता है उसके ऊपर भी आप काबू लें, नियंत्रण लें। लेकिन ऐसा दिखता है कि अपने उस फर्ज को तो आपने नजर अन्दाज कर दिया, और केवल आपने तकरीर में यह कहा कि मैंने तो आने के बाद कुछ कटौती की, कुछ महकमे तोड़े हैं, कुछ सरकारी मुलाजिमों को सरप्लस करके बचत की है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात को पहचाना कि आपके साथी १३,०००) रु० तनख्वाह पावें और १८,०००) रु० टी०ए०, डी०ए० लेलें। क्या आपने बजट के आंकडों को देखा है सारी आमदनी में से तनख्वाह खर्च दिखा रखा है उसमें टी० ए० का जितना बडा आइटम है वह उस महकमे में विकास के कामों में खर्च किये जाने वाली राशि से कम नहीं है। आप देखें मेडीकल के अन्दर १० लाख ८७ हजार टी० ए० के लिए लिखे हुए हैं। आप एग्रीकल्चर के अन्दर, एनीमल हसबेन्डरी के लिए देख लें कि कितना रुपया ट्रेवलिंग अलाउन्स के लिए है। ३८ जीपें हैं और टी० ए० का आंकडा छुपाना चाहते हैं लेकिन वह बजट में मौजूद है। इसी तरह से आपके सरकारी मुलाजमान ने भी तरीका निकाल लिया है अलाउन्स पकाने का और जब वह मिनिस्टरों को देखते हैं तो वह भी यही करते हैं और सब के लिए जरिया हो गया है तनख्वाह से दुगना टी० ए०, डी० ए० कमाने का। आप इसको जस्टीफाई नहीं कर सकते, और आपको आमदनी के लिए टैक्स लगाने की जरूरत पडती है। मैंने यह देखा कि बजट के आंकडों के साथ यह भी दे रखा है कि हर महकमे में नवीन स्कीम, न्यू आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर मेडीकल के अन्दर ९ लाख ८१ हजार है, एग्रीकल्चर में २५ लाख ८२ हजार है तो यह आपने नहीं देखा कि इसके कोई डिटेल नहीं और हर डिपार्टमेन्ट के साथ में न्यू आइटम ऑफ एक्सपेन्डीचर मौजूद है।

तो आप लोगों के सामने सदन में बहुत से सुझाव आये हैं कि आप चार करोड़ को पूरा करना चाहते हैं तो उन चार करोड को पूरा करने के लिए मैं तो आपके सामने एक तजवीज पेश करूंगा कि आपने जितने भी बजट के अन्दर नये आइटम हर महकमे के अन्दर खर्च के लिए लगाये हैं उनको ही काट दें, तो इस वर्ष के अन्दर चार करोड का घाटा पूरा हो सकता है, और चार करोड के घाटे को पूरा करने के लिए आपको नये टैक्सेज लगाने की

**(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)**

जरूरत नहीं पडेगी, क्योंकि इस वर्ष के बजट में पिछले साल जो खर्चा हुआ है उतना ही कायम रख कर यह बजट रखें।

इसी तरह से आपके महकमे में कई सरकारी मुलाजिम यह महसूस नहीं करते हैं कि इन रुपयों का बराबर यूज होता है कि नहीं। हमारा कोई यह फर्ज भी है कि जितनी मंजूरी हुई है उसको सही तरीके से खर्च किया जाय। आपके पास कोई भी एजेन्सी नहीं है, जिसके जरिये से आप उस को कन्ट्रोल कर सकें। आपके पास बजट के आंकडे आते हैं ऑडिट रिपोर्ट आती है तो ऑडिटर यह कहते हैं कि हमारा फर्ज है कि जितना रुपया था उसकी रसीदें हैं या नहीं। ऑडिटर कोई यह नहीं जाकर देखता है कि जितने ४-५ हजार या लाख का खर्चा किया वह वाजिब तौर पर लगा या नहीं। आपके पास में कोई एजेन्सी है या नहीं। आप अगर नियन्त्रण करना चाहते हैं, खर्च पर काबू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप ऐसी एजेन्सी बनायें जो यह देखे कि जो खर्चा हुआ है वह सही तौर से लगा है, इसकी जांच करे। आप नजरअन्दाज करते हैं पी. ए. सी. की रिपोर्ट को आप नजरअन्दाज करते हैं, एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को आप नजरअन्दाज करते हैं इन सबको। मैं एक मिसाल के तौर पर बताता हूं कि आप कहते हैं कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन मैं आपकी तवज्जह दिलाऊंगा कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट देता है कौन? यूटिलिटी सर्टिफिकेट वही आदमी देता है जिसको रसीद बनानी होती है। आपके सामन मिसालें हैं। ये जिन्दा सबूत हैं। किसी भी महकमे में जितना रुपया खर्च हुआ है उतना नहीं लगा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा ५०-६० पर्सेन्ट लगा होगा और ४० पर्सेन्ट के झूठे हिसाब पेश होते हैं आपके सामने और पंचायत समितियों में भी इसी तरह से होता है। लोन तकावी दी जाती है, लोन दिया जाता है उसका ब्याज नही। आप इन्डस्ट्री में देखिये, इन्डस्ट्री में साढे सात लाख बकाया है। उसी तरह से ट्रान्स-पोर्ट में बकाया है साढे तीन लाख। मंत्रियों में मौजूद है बकाया, जाने वाले मंत्रियों में बकाया मौजूद है, और आपके विभाग में·········

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

५ मिनिट।

**श्री सभापति** : पांच मिनिट नहीं, दो मिनिट।

**श्री मथुरेश बिहारी माथुर** : मैं यह अर्ज कर रहा था कि आप कहते हैं कि फन्ड्स की कमी है, मुझे अफसोस है, लेकिन इस बात पर तवज्जह दिलाऊंगा कि खर्चे पर नियन्त्रण करें, आप बकाया की वसूली करने की कोशिश करें और ६३-६४ के अन्दर, मैं अर्ज करूंगा कि जितनी बकाया है उसकी वसूली ज्यादा हो। मैं आपकी तवज्जह दिलाता हूं वित्त मंत्री महोदय, कि ४ करोड के टैक्सेज को आप इस साल माफ करें तो भी आपको घाटा नहीं होगा। यह मेरा दावा है। इस बात की तरफ तवज्जह देंगे। बकाया की वसूली करेंगे, मनी का प्रॉपर यूज करें और न्यू स्कीम आफ एक्सपेन्डीचर सब को खत्म करें तो आपका सब घाटा पूरा होगा और यह जो आपके सामने·····

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

चारों तरफ के आरोप हैं, मैं पुरजोर लफ्जों में कहूंगा कि इनको खत्म किया जाना चाहिए। यह आपकी और सदन की शोभा नहीं होगी कि लैण्ड रेवेन्यू और अनाज पर टैक्स रहे, जानवरों पर टैक्स रहे, उसी तरह से कागज पर दिल्ली में जो टैक्स है उससे दुगना है। जो आपके सामने रंग है उसको आप देखेंगे तो आपने टैक्स दुगना लगाया है। जानवरों पर टैक्स पंचायत समिति भी लेती है और आप भी लेते हैं ·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो सेन्टर का २ रुपया और आपका भी दो रुपया फी आदमी टैक्स बढ़ा है वह असहनीय है। मैं महसूस करता हूं कि उसमें राहत देने की कोशिश करेंगे यह मेरी पुरजोर अपील है। मैं समझता हूं कि समय के अभाव में ज्यादा नहीं कह सकता।

**श्री सभापति** : श्री शंकरलाल : १० मिनिट से ज्यादा नहीं। आप खयाल रखें।

**श्री शंकरलाल जाट** ( सादडी ) : सभापति महोदय, आज चार रोज से बजट भाषण पर वाद-विवाद हो रहा है जिसको बःकरार सुनते आ रहे हैं। सभापति महोदय, विरोधी पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने काफी हमदर्दी बताई और प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के बारे में भी आपने विचार प्रस्तुत किये। लेकिन एक कहावत है हमारे डूंगरपुर जिले की वह मैं कहना चाहूंगा कि आपका एकतन्त्रीय शासन या उस वक्त व्यक्तिगत प्रशासनिक सुधार थे वह इस तरह के थे। एक आदिवासी घी बेचने के लिए डूंगरपुर जा रहा था तो वह जो घी की बाडी थी वह मिट्टी की बनी हुई थी उसमें से घी टपक रहा था। उसके कपडे चीकने हो जाने की वजह से उसने सागवान का पत्ता तोडकर बाडी को उसके अन्दर रख दी। उधर से उस क्षेत्र के राजा-महाराजा या महारावल कुछ भी कहें वह महारावल शिकार खेलने या टहलने के लिए निकले तो वह रास्ते में मिल गया, तो सागवान का पत्ता देखकर उन्हें बडी भारी ग्लानि हुई और उससे कहा कि यह पत्ता तूने कहां से तोडा है तो उसने कहा कि मैंने सागवान से तोडा है तो उसको उस दरख्त के पास ले गये और सारे का सारा जो घी था वह उस दरख्त की जड में छोड दिया गया ···

**एक माननीय सदस्य** : और घी की कीमत दे दी उसी समय, यह आपने नहीं बताया।

**श्री शंकरलाल जाट** : टाइम को नहीं देखेंगे कि उसका टाइम खर्च हुआ है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि उन्हें याद होगा इसलिए वह सरकार बनाना चाहते हैं ···

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : अगर आप पुराने जमाने की बात याद दिलाना चाहते हैं तो पुराने जमाने की हम भी १० बातें याद दिलायेंगे।

**श्री चन्दनमल बैद** (उप-मंत्री, वित्त) : जरूर दिलाइये।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : २५ दफा आप घी की बात करने के लिए इनको रोकेंगे नहीं तो उसका हम भी जवाब देना चाहते हैं। आपके पापों का घडा भर रहा है और वह भण्डा फूटेगा थोडे दिनों के अन्दर। हमारे साथ तो वह हो गया अब आपका भी भर गया है।

(शोरगुल)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप.मंत्री, शिक्षा): यह हमारी परम्परा है माननीय सभापति महोदय और इस परम्परा को कायम रखें। यही मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

**श्री भैरोंसिह :** आप परम्परा बदलने की बात कर रहे हैं कि उस परम्परा को बदलिये और आप कहना चाहते हैं कि परम्परा को रखा जाय।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मैं परम आदर के साथ में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रासंगिक रूप से १५ वर्ष पहले की बातें आपने सदन के समक्ष किसी माननीय सदस्य द्वारा रखी जाती है तो उसका उत्तर देने का हमारा परम उत्तरदायित्व है, और उस उत्तरदायित्व को परिपूर्ण करने के लिए हम कोई कोर-कसर उठा नहीं रखेंगे। अगर मेरे शासन के अन्दर २० वर्षों के अन्दर २ मनुष्य मारे गये जिसका कि मुझे बहुत दुःख है तो मैं यह उदाहरण दे सकता हूं कि डूंगरपुर जिले में इन १४ वर्षों के अन्दर १३ आदमी मारे गये और सब पुलिस के हाथों मारे गये··

(शेम, शेम)

अत्याचार किसकी तरफ से ज्यादा है। आपका इतना ज्यादा है कि वह पुराने शासन में सम्भव नहीं।

**श्री किशनसिंह बठड** (लक्ष्मणगढ़): आपके शासन में काफी जुल्म हुए हैं। हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है।

**श्री सभापति** : Order Please। आप अपना भाषण आरम्भ रखिये।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : रीसेंट घटनाएं घटी हैं उनको हम भी बताना जानते हैं। २० वर्ष पहले की बातें····

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : Point of order, sir, I would request the chair to call the House to order.

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : Chairman, with great respect I bring this issue to your gracious notice that this is not an occasion when old things should be revived, when old controversies should be repeated. It is bad taste, but if bad taste comes from the other side I shall respond in equal terms. Please do not mistake me.

**श्री सभापति** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि बेकार वाद-विवाद न कर अपना भाषण शुरू करें।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : In your vein of democracy, if you talk in these terms, then you are practising the worst form of tyranny, I say.

**श्री शंकरलाल जाट** : जो बजट देखा तो

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : They should practise democracy first and then try to preach to others what democracy means. It is high time you control your organisation before its disruption.

**श्री सभापति** : मैं बार बार यह निवेदन कर रही हूं कि रोषपूर्ण वाद-विवाद न करके भाषण शुरू करें।

# Page No.52



**श्री शंकरलाल जाट** : हमने माननीय वित्त मंत्रीजी के बनाये गये बजट को काफी गौर से देखा । वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में यह भी फरमाया है कि समाजवादी ढंग से यह बजट बनाया गया है। आखिर हमने देखा कि जो बजट भाषण की पुस्तिका हमें दी गई थी उसके पेज नं० ३३ पर राजस्व पर जो कर लगाया गया है वह पशुओं पर, खाद्य पर जिस प्रकार से लगाया गया है उसको देख कर हमने यह पाया कि वाकई यह समाजवादी बजट नहीं है, क्योंकि यह तो उन गरीबों पर, मजदूरों और किसानों के ऊपर सीधा भार डालेगा जो स्वयं मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं और हमेशा, रात-दिन, सर्दी, गर्मी और वर्षा आदि में परिश्रम करते हैं। इसलिये जिसको समाजवादी बजट कह कर बजट बनाते हैं वह समाजवादी बजट नहीं हो सकता बल्कि शोषणवादी बजट का प्रतीक मालूम होता है ।

सभापति महोदय, श्री वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण की पुस्तिका के कॉलम १५ में यह बताया कि माननीय सदस्यों के सुभीते के लिये और मजदूरों के लिये, किसानों के लिये क्रियाशील इरादे से भी इस साल का बजट पेश किया गया है । जिसमें भाषा को विशेष महत्व दिया गया है लेकिन सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आता कि एक तरफ हमारी संसद में और राज्य लेवल पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करने का आन्दोलन चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे यहां जो बजट पेश हुआ है उसी पर भाषण उर्दू भाषा में दिया गया है । इससे ऐसा लगता है कि कहीं हमारे यहां भी भाषा का आन्दोलन शुरू न हो जाय।

मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा कि पहले कहा, राजस्थान की एक रियासत में एक प्रकार का नियम था कि जब कोई वहां के राजा का देहावसान हो जाता और दूसरा राजा गद्दी पर बैठाना होता तो ऐसा नियम था कि जो आदमी मिल जाता उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता ( करतल ध्वनि और कई सदस्यों के एक साथ बोलने से डिस-ऑर्डर)

तो सभापति महोदय, आपकी मार्फत वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी गुजरात राज्य में भी राजस्व कर वापिस लिया गया है उसका उदाहरण सामने रखते हुए अपने यहां भी करों को वापिस लिया जाय ।

**श्री सभापति** : श्री भगराज ।

**श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय . . . .

**श्री सतीशकुमार शर्मा** (बानसूर) : इस तरह से तो विरोधियों को कोई मौका ही नहीं मिलेगा बोलने का ।

**श्री सभापति** : अभी १ घंटा और १६ मिनिट बाकी हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** (किशन पोल, जयपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी ऐसे मेम्बर को बुलाया जाय जो टैक्सेज के समर्थन में बोलता हो . . . .

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : और सारा टाइम उस मेम्बर को दिया जाय।

**श्री सभापति** : Order please! Shri Bhag Raj.

**श्री भगराज चौधरी** : (रानीवाडा) सभापति महोदय, आज राष्ट्र के सामने दो महान समस्यायें हैं एक तरफ देश की सुरक्षा की समस्या है तो दूसरी तरफ देश के विकास का प्रश्न है। ये दो महान समस्यायें राष्ट्र के सामने मुंहबाये खडी हैं। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है हमने अपने जवान लडाई के मैदान में भेजे और यथाशक्ति आर्थिक सहायता हर व्यक्ति ने दी है और दे रहा है। और जहां तक विकास का सवाल है, विकास में भी यथाशक्ति सहयोग दे रहे हैं। लेकिन योजनाबद्ध विकास के लिये आवश्यकता इस बात की है कि हमारा प्रशासन शुद्ध हो, निष्ठा वाला हो और उसमें कार्यक्षमता हो। दुर्भाग्य से कहना पडेगा कि राजस्थान का और देश का प्रशासन भ्रष्ट है और भ्रष्ट प्रशासन की सारी जिम्मेदारी मैं इस मंत्रीमण्डल पर थोपता हूं। क्योंकि हमारा मंत्रीमण्डल ही मौजदा सरकार है।

**श्री सभापति** : अपने शब्दों पर संयम रखें तो अच्छा हो।

**श्री योगेन्दना हांडा** : बहुत सुन्दर शब्द कहे हैं।

**श्री भगराज चौधरी** : हमारा शासन ..ष्ट है यदि इस पर कण्ट्रोल नहीं किया तो एक दिन वह आयेगा जिस दिन कि देश की हालत बहुत ही बिगड जायेगी।

**एक माननीय सदस्य** : आ गया है वह दिन।

**श्री भगराज चौधरी** : हमारी योजना को चालू रखने के लिये आवश्यक है कि हमारे देश का प्रशासन शुद्ध हो, निष्ठावान हो, कार्यक्षमता वाला हो। चाहे किसी देश की कितनी ही नीतियें अच्छी क्यों न हो लेकिन जब तक देश का प्रशासन निष्ठावान और कुशल नहीं होता तब तक देश की गति आगे जाने वाली नहीं होती। कहने को कहते हैं कि हमने पिछले १० साल में देश की तरक्की की लेकिन मैं देखता हूं कि हमने जो कुछ किया है वह बहुत थोडा है अभी हमें बहुत रास्ता नापना है, जो नापना है वह बहुत दूर है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें प्रशासन पर कण्ट्रोल करना चाहिये। जब तक प्रशासन पर कण्ट्रोल नहीं कर लेत तब तक विकास कार्य-क्रम का इम्पलीमेन्टेशन सही ढंग से नहीं हो सकता। दूसरी ओर जहां देश की रक्षा का सवाल है हमें इसके लिये अपनी स्थिति को सुदृढ करना होगा।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): वित्त मंत्रीजी सदन में नहीं हैं, किसको कह रहे हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : डिप्टी मिनिस्टर मौजूद हैं।

**श्री ज्वाला साद शर्मा**: डिप्टी मिनिस्टर को मान्यता नहीं होती।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपकी मान्यता न्याय-संगत नहीं है, इसलिये इस मान्यता का निराकरण करना चाहिये। आप बार बार रिफलैक्शन देते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर की मान्यता नहीं है। ये हमको मानते हैं या हम उनको मानत हैं यह अलग प्रश्न है। . . . .

(३.०० म. प.)

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : इसकी सच्चाई आप बतादें तो हम मान सकते हैं और आपका खतरा दूर हो सकता है।

**श्री सभापति** : उप–मंत्री यहां मौजद, आप भाषण जारी रखें।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह**: It seems to me that there is a strief *inter-se*.

**श्री मगराज चौधरी** That is between you and ourselves.

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना): आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** How very pleasant !

**श्री भगराज चौधरी** : आज के प्रशासन में आज की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए त्याग की भावना नहीं पनपाई गई है। आज प्रशासन की भावना यह होनी चाहिए कि वह जन–सेवक बन कर कार्य करें। यह सत्य है कि वे जन–सेवक नहीं बन कर आज जन-शासक बन कर कार्य कर रहे हैं। जो त्याग की भावना सरकार को प्रशासन में डालनी चाहिए लेकिन वह नहीं डाल पाई है।

जहां टैक्सेज के भार का सवाल है, यह भार उन्हीं पर पडना चाहिए, जो टैक्स देने की क्षमता रखते हैं। वित्त मंत्रीजी ने इस साल जो कर प्रस्तावित किये हैं, उनमें लड रेवेन्यू पर कर भार ( Cess ) लगाया है, पशुओं पर कर लगाया है और अनाज पर कर लगाया है, ये निन्दनीय कर हैं। मैं इन तीनों टैक्सों को जन-विरोधी और समाज-विरोधी कर मानता हूं। हम समाज-सुधार का नारा लगा कर हमारे यहां कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। मैं यह कहूंगा कि तब तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सही मायने में नहीं कर सकते जब तक इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि गरीबों की हालत में सुधार हो, गरीबों और अमीरों में जो दूरी है, उसको हमें कम करना होगा। लेकिन आज गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे मंत्रि मंडल में जितने सदस्य हैं, उनमें आठ में से सात शहर के लोग हैं, सिर्फ एक दो आदमियों को गांव का रिप्रजेंटेशन दिया गया है। इसमें मूलभूत परिवर्तन लाना जरूरी है और मैं यह कहूंगा कि इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे मुख्य मंत्रीजी पर है······

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** (उप–मन्त्री, शिक्षा) On a point of order, sir, यह केबिनेट क कम्पोजीशन पर बहुत बडा रिफ्लैक्शन है। कौन जानकार है, कौन जानकार नहीं है यह तो आप बतला दें, अगर नहीं बतलाते हैं तो हमें एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिले····

**श्री भगराज चौधरी:** यह इन्टरप्शन है, इस प्रकार इन्टरप्शन नहीं कर सकते। यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। जिस वक्त मिनिस्टर बोलते हैं और उनको इन्टरप्ट करते हैं तो उन्हें चैयर का प्रोटैक्शन मिल जाता है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य:** मैं पोइन्ट आफ ऑर्डर पहले रेज किया है। आप नहीं उठा सकते पोइन्ट ऑफ ऑर्डर।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
मेरा निवेदन है कि यह कबिनट के कम्पोजीशन पर रिफलेक्शन है ...

**श्री भगराज चौधरी:** This is not a reflection, Sir.

**श्री निरंजननाथ आचार्य** हम गांव के नहीं है, यह कहना गलत है, निराधार है और ....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:** This is not a point of order.

**श्री भगराज चौधरी** This is not a point of order.

**श्री निरंजननाथ आचार्य:** seek protection of the Chair, sir. Under Rule 276, I have a right to demand an explanation of the aspersions made.........

**श्री भगराज चौधरी** : This is no point of order.

**श्री निरंजननाथ आचार्य:** I am in possession of the floor.

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य को अधिकार है कहने का। मैं उपमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे बार-बार डिस्टर्ब न करें।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह:** Madam Chairman, this is an illustrious example, How guilty conscience pricks !

**श्री भगराज चौधरी** : मेरा ख्याल है कि उप-मंत्रीजी यह भूल गये कि यह हमारा मूलभूत अधिकार है जनता के रिप्रेजेन्टेटिव होने के नाते कि जनता की डिफीकल्टीज को यहां रखें। कोई मंत्री या मुख्य मंत्री ही क्यों न हो, अगर वे गलत रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने का हमारा परम कर्तव्य है। अगर नहीं लायेंगे तो गांवों का जो उत्थान करना चाह रहे हैं, वह गांव में नहीं हो पायगा। मैं अब इस पर ज्यादा जोर न देकर अपने सब्जेक्ट पर आना चाहता हूं।

कृषि की उन्नति के लिये जो काश्तकारों को हमने सहूलियतें दी है, वे सहूलियतें अभी काफी नहीं हैं। हमने केवल गांवों में जो जागीरी प्रथा थी, जो एक काश्तकारों पर बोझ डाले हुए थी, उसको जरूर हटाया है। लेकिन जब तक काश्तकारों की माली हालत नहीं सुधर जाती तब तक सही मायने में हमने किसी तरह का सुधार नहीं किया है। इसलिये यह आवश्यक है कि जो भूमि का अधिकतम सीमा का कानून पडा हुआ है, उस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करें। सरकार अब तक नहीं कर पाई, इस कारण से जो राजा-महाराजा हैं, एक्स रूलर्स हैं, एक्स जागीरदार हैं, जिनके पास सैंकडों बीघा जमीन पडी थी, उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इसका कारण यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने किसी प्रकार उनसे मिलकर उनको टाइम दे दिया है। अगर उनको टाइम नहीं देते, तो आज जिस सही भावना को लेकर यह कानून बनाया गया है, उसका काश्तकार फायदा उठा सकते थे और गरीबों को जोत के लिये जमीन दे सकते थे .....

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): मुख्य मंत्री ने ?

**श्री भगराज चौधरी:** मैं समझता हूं कि टैक्सों का भार गरीबों पर नहीं पड कर

(भगराज चौधरी)

धनवानों पर पडना चाहिये। इसके अलावा आज शहरों का विकास हो रहा है, शहरों में बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, लाइब्रेरी बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कालेज बन रहे हैं जब कि गांवों से अस्सी प्रतिशत इन्कम की जाती है, उन गांवों में यदि कोई पब्लिक सार्वजनिक कार्य करना चाहती है, तो उसके लिये उसको ७५ पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन देना पडता है, जबकि उनकी हालत आज बहुत खराब है। हम देखते हैं कि किसान के पास आज पहिनने के लिये कपडा नहीं है, पेट भरने के लिये टाइम पर भोजन नहीं मिलता है, फिर भी हमारी सरकार की तरफ से यह वर्ताव किया जा रहा है, यह महरबानी की जा रही है। यह अलग प्रकार से सोचने का तरीका है। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि हमारे वित मंत्रीजी शहर के रहने वाले हैं, उनको गांव में रहने वालों की स्थिति का पता नहीं है। वे कभी देहातों में जायं और देखें कि गांव के काश्तकारों की क्या हालत है। लेकिन वे तो पहले काश्मीर के रहने वाले हैं और आजकल अजमर में बस गये हैं। अजमेर एक ऐसी जगह है जहां ऐसे गरीब नहीं हैं.......

**श्री मानसिंह महार** (आमेर): अजमर से पहले कहां रहते थे?

**श्री भगराज चौधरी**: पहले कश्मीर में रहते थे।

**श्री बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री): माननीय सदस्य मेरे इतिहास से वाकिफ हैं, इसलिये उन्हें खबर है कि मैं कश्मीर में रहता था।

**श्री विजयसिंह झाला** : (नाथद्वारा): बजट पेश करने से कुछ दिन पहले आप गांव में कुछ दिन रहे थे।

**श्री बालकृष्ण कौल** : आप जब पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं गावों में जाया करता था।

**श्री विजयसिंह झाला** : गांवों में क्या करते थे?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): माननीय सदस्य तो पैदा ही गाव में हुए थे।

**श्री भगराज चौधरी**: माननीय वित्त मंत्री.....

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): आपका मतलब यह है कि आप टैक्स लगा कर गांवों में जायें।

**श्री विजयसिंह झाला**: टैक्स लगाकर गांवों में जायें तो अब दुर्गति होगी।

**श्री भगराज चौधरी**: माननीय वित्त मंत्री ने साढे चार करोड के घाटे का बजट पेश किया है। उनका कहना है कि इस घाटे की पूर्ति कर दी जायगी तो हमारे विकास के कार्य ठीक तरह से चालू रहेंगे, हमारे रक्षा कार्यों में हमें अच्छी तरह से तैयारी करने का मौका मिलेगा जिस प्रकार से हमने सोच रखा है। मेरा उनसे निवेदन है कि जितनी फिजूल खर्ची हो रही है उसको रोकिये। जब तक फिजूल खर्ची को नहीं रोक पाते हैं तब तक एक पैसा भी लिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि आपकी ईमानदारी पर हमें विश्वास नहीं है। उनका विश्वास आप पर से हट गया है। उनका कहना है (शेम, शेम) इस तरह से सरकार पर से भरोसा हट गया है.....

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: On a point of order, ....

**श्री भगराज चौधरी**: यह सरकार···

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि·····

**श्री भगराज**: I am in possession of the floor, Sir.........

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: मुझे पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर रखने का मौका दिया जाय। मेरा पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर है, ग्रापका जो एक्सप्रशन है, जैसा ग्रापने कहा है। इनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है यह···

**श्री भगराज चौधरी**: किसानों की धारणा है कि····

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: दूसरे शब्दों को छोड़ते हुए ये शब्द हैं 'इनकी ईमानदारी के ऊपर भरोसा नहीं हैं' यह रिफ्लेक्शन हैं पर्सनल कन्डक्ट पर····

**श्री भगराज चौधरी**: This is no reflection, Sir.

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: मेरा निवेदन हैं कि इन शब्दों को हटाया जाय या ग्रापको कहा जाय कि इनको वापिस लें, जिससे हम ग्रपनी परम्परा को मेन्टेन कर सकें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**: We don't understand, in what way, it is a reflection.

**श्री भगराज चौधरी**: It is not a reflection, Sir, (Nadam) What I mean to say was that the people have lost faith in the present Government.

(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य की ऐसी मन्शा नहीं थी। ग्राप जारी रखें। उप-मंत्री जी बारबार इन्ट्रप्ट कर रहे हैं कृपया इन्ट्रप्ट न करें (हिग्रर, हिग्रर)।

**श्री भगराज चौधरी**: जहां तक संकट-कालीन स्थिति का सवाल है····

**श्री भैरोंसिंह**: ग्रॉन ए पॉइन्ट ऑफ ग्रार्डर, सभापति महोदया, पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के ग्रनुसार जिस किसी मेम्बर का यदि नाम लेकर उसको संकेत किया जाय, किसी मेम्बर या मंत्री को नेम ग्राउट किया जाय तो पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस ग्रौर सदन की सारी पवित्रता को बनाये रखने के लिए यह लाजिमी है कि वे सदन में खड़े होकर रिग्रेट शो करें। मैं निवेदन करूं कि उप-मंत्रीजी की ग्रालोचना की है नाम लेकर, इसलिए पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस की हेल्दी परम्परा ग्रौर शुद्धता को बनाये रखने के लिए हाउस में वे रिग्रेट शो करें····

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): नाम नहीं लिया है। नाम नहीं लिया है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर)· नाम का मतलब है जैसे यह कहा है कि उप-मंत्री जी बीच में बार बार डिस्टर्ब करते हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: सभापति महोदय···

**श्री सभापती:** मुझे खेद है, मैं बार बार निवेदन कर रही हूं कि इस प्रकार इन्ट्रप्ट नहीं किया जाय। आप भाषण जारी रखे, बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री भगराज :** Thank you, Thank you. मैं निवेदन कर रहा था कि देश की रक्षा के लिए हमने यहां से जवानों को भेजा, पैसा भेजा, सोना भेजा लेकिन हमारे यहां की जनता आज टैक्सों का भार वहन करने में बिल्कुल असमर्थ है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ठंडे दिमाग से वे सोच-विचार करें और इस प्रकार के टैक्सेज लगायें जिन टैक्सों का भार शहरों की जनता के ऊपर पड़े। आज शहरों में लाखों मकान पड़े हुए हैं, जिनकी आज से दस साल पहले की कीमत एक हजार थी, आज उनकी कीमत तीस हजार, पचास हजार हो गई जिनकी कीमत बढ़ गई है, उन पर आप टैक्स लगायें और किसानों के नहरी पानी भेजने पर बैटरमेंट लेवी लगाते हैं तो उसी प्रकार शहरों की हालत जो अच्छी हो रही है उस पर भी टैक्स लगाये जाने चाहियें।

भूतपूर्व राजा महाराजाओं को उनके मकानों में आप मुफ्त में पानी और बिजली देते हैं क्या? वह भी आपको तुरन्त मुफ्त देना बन्द कर देना चाहिये। । आपको प्रशासन के खर्चों में कमी करनी चाहियें। आपके समितियों में एक्साइज ऑफिसर आदि है जो कुछ काम नहीं करते हैं। इसलिये आपको उसमें कमी करनी चाहिये और प्रशासन में सुधार लाना चाहिये और खर्चों में कमी करनी चाहिये। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी बेकार पड़े हैं उनको तुरन्त

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हटायें और केवल दो-दो ग्राम पंचायत के बीच में एक-एक सेक्रेटरी आदि रखें और अपने खर्चों में कमी करें। इस प्रकार कमी होने से बजट ठीक हो जावेगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने ३५ करोड़ के बजट में बचत प्रावधान रखा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इन टैक्सों को वापिस लेने की कोशिश करें और मौजूदा प्रशासनिक व्यय व अन्य फिजुल खर्चों में कमी करें।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

(बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री बालूराम चौधरी** (फतेहपुर): सभापति महोदया, कांग्रेस सरकार के इतिहास में यह मौजूदा बजट है वह एक Turning पोइन्ट है। जो सरकार आगे से आगे गतिशील की तरह बढ़ रही थी आज हमें मालूम हो गया है कि उसी सरकार के पैर आज पीछे पड रहे हैं, और आगे बढ़ने से रुक गये है, और जिस सरकार पर गरीबों की गरीबी को दूर करने का जिम्मा था आज वही सरकार न जाने उसको अचानक क्या दिखाई पडा है कि वह पीछे चल पड़ी है मैं आज यह समझता हूं कि यह सरकार वापिस अन्धेरे में भटक रही है और सही दिशा उसके पैरों के नीचे से निकल गई है और यह सरकार कहां जावेगी उसका हमें पता नहीं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): खड्डे में जावेगी।

**श्री बालूराम चौधरी :** आम तौर से ऐसा देखा जाता है कि जो विकासशील सरकार

(श्री बालूराम चौधरी)
होती है वही जनता की भलाई और बहुमत के कल्याण के लिये कुछ न कुछ ऐसे उपाय निकालती है जिससे कल्याण हो। लेकिन हमारी सरकार ने बेकारी दूर करने के लिये क्या किया? हमारी सरकार ने गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिये क्या किया? इस तरफ इस बजट में कोई ईशारा नहीं है। देखने से यह बजट ऐसा लगता है जैसे कि एक कहानी है कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी वह रोज सोने का एक अन्डा देती थी। आखिर एक दिन उस मुर्गी के मालिक को सूझा कि यह मुर्गी हमेशा सोने का अन्डा देती है। इसके पेट में बहुत से अन्डे होंगे इसलिये इसके पेट के अन्डे एक साथ ही मिल जावें तो अच्छा हो। हमारे यहां सोने का अन्डा देने वाले किसान थे। आज यह सरकार को मालूम हो गया कि सोने का अन्डा देन वाली मुर्गी यही किसान है। इसको मार लो तो एक साथ सोने के सभी अन्डे मिल जावेंगे और गरीबी की जो हालत सरकार की है वह दूर हो जावेगी और सरकार जो मुसिबत में है, उस पर जो कर्जा है, वह दूर हो जावेगा। अब उन्होंने सोना देनीवाली मुर्गी को मारने का निश्चय कर लिया है।

वास्तव में देखा जाए तो दो ही वर्ग हैं। एक तो मजदूर और किसान वर्ग और दूसरा वर्ग अमीर वर्ग। इस बजट से जो कर लगाये गये हैं इससे गरीबों पर बहुत बड़ा बोझ पड़गा। वे लोग पहले ही से टैक्सों के भार से दबे हुए हैं। टैक्स लगाने वाले यदि पब्लिक में जावें तो उनको मालूम होगा कि आम तौर से इन टैक्सों के बोझ से मृतक सी नजर आवगी। आपको मालूम है कि ८० पर्सेन्ट जनता गांवों की है और जिनके वोट लेकर आप आये हैं और आपने सरकार बनाई है। आप उनको भूल गये हैं। उन लोगों ने आपको देवता बना कर पूजा और देवता समझ कर उन्होंने आपको यहां भेजा मगर अब वे समझ गये हैं कि जिनको उन्होंने देवता समझा था वे अब दानव बन गये हैं, और वे अब देवता नहीं रहे दानवों में बदल गये हैं। वे आज पागल हो गये हैं और जब पागल आदमी हो जाता है तो उसका नतीजा यही होता है कि वह अपने ही लोगों को काटता हो उन्हीं लोगों को काटता है जिनको जनता ने दूध पिलाया और आज वे लोग जिन्होंने उनको दूध पिलाया, जहर पिला रहे हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर वे जिन्दा रहना चाहते हैं तो जिस दिशा में वे अभी चल रहे हैं वह दिशा बहुत खतरनाक है, और आगे चल कर और भी खतरनाक होगी इसलिये उनको इस दिशा को छोड़ देनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हम बहुत खुश होते अगर इस में इतना भी इशारा होता कि शासन में भ्रष्टाचार है और उसको दूर करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसका कोई संकेत नहीं है। और यह बजट साफ बताता है कि यह बजट कांग्रेस विधायकों का नहीं है यह घंटी का बजट है। यह घंटी बजाने वाले अधिकारी लोग हैं उनका बजट है। कांग्रेस का नहीं है। कोई कांग्रेस विधाई इसके पक्ष में नहीं बोला। किसी की भी आत्मा इसके पक्ष में नहीं है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह घंटी का बजट है किसी कांग्रेस विधायी का नहीं है। घंटी बजाने वाले जो नौकर हैं उनके चुंगल में हमारी केबिनेट है। नौकरशाही ने उनको इस तरह से जकड़

(श्री बालूराम चौधरी)

लिया है कि वे इधर से उधर नहीं हट सकते। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि यह बजट न तो कांग्रेस विधायकों का है न अपोजिशन के विधायकों का है। हमें यह मालूम है कि बजट कहां से कहां जा रहा है।

इसके अलावा मैं एक बात बता दूं कि टैक्स विकास के लिये लगाये जाते हैं, आवश्यकता के लिये लगाये जाते हैं और जब टैक्स लगाये जाते हैं तो उसका प्रोपर चैकिंग होना चाहिये। यह देखना चाहिए कि उसमें चोरी नहीं हो। मैं यह कहूंगा कि भीतर से शासन खोखला हो गया है जिसमें भ्रष्टाचार घुस गया है। उसको रोका जाय। आपका सेल्स टैक्स अकेला ऐसा टैक्स है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिसके जरिये अकेले जयपुर शहर में करोडों रुपये मिल सकते हैं। मगर कोई चैकिंग नहीं होता है। इसके अलावा जितने आप टैक्सेज बढावेंगे उससे टैक्स की चोरी रुकने वाली नहीं है बल्कि बढ़ेगी। उसमें ज्यादा चोरी होगी। इसलिये चैकिंग हो। सिर्फ टैक्स के नाम से कोई टैक्स वसूल नहीं होता है। आपके यहां दो ही प्रकार के टैक्सेज ईमानदारी से वसूल होते हैं:

एक तो वे कर जो काश्तकारों से वसूल किये जाते हैं और दूसरे वे कर जो नौकरों पर इनकम टैक्स के रूप में वसूल होते हैं। क्योंकि ये दोनों ही बन्धे हुए कर हैं। काश्तकार का कर रेवेन्यू के लैन्ड रेकार्ड पर होते हैं तो दो जगह से ईमानदारी से कर वसूल होते हैं बाकी ७५ पर्सेन्ट टैक्सों में चोरी होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और बोलूंगा।

हम राजस्थान में किसानों के विकास के लिए टैक्स लगाते हैं लेकिन हमारी योजनाएं यह बताती है कि राजस्थान की योजनाएं किसी व्यक्ति की योजना नहीं है। हम संपत्ति को देखने लग जावें। व्यक्ति को नहीं देखते हैं हम किसी काश्तकार या मजदूर को नहीं देखते हैं। यह कभी व्यक्ति को नहीं कहते कि तेरे कल्याण के लिये यह करने वाले हैं। आज आप किसी भी नागरिक से किसान से या मजदूर से पूछिये कि तुम्हारी हालत कैसी है तो वह यही कहेगा कि हालत खराब है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जब हम व्यक्ति को महत्व देंगे तभी हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार कहलावेगी अन्यथा नहीं।

बिजली का नाम लेते हैं कि इस पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ है। इस में टैक्स लगाया जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि आपने किस काश्तकार के कुए पर बिजली लगाई है यह तो बतावें। हम तो कहीं भी नहीं देखते हैं। किसी जिले में आपने लगाई होगी लेकिन हमारे जिले में बिजली आज दो वर्ष हो गये आई हुई है, लेकिन किसी काश्तकार को उसके कुए पर बिजली नहीं मिली है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब काश्तकार को बिजली नहीं मिली तो उस बिजली से काश्तकार को क्या लाभ मिला? आम तौर से राष्ट्रीय सड़कें और दूसरी सड़कें बनती हैं, काश्तकारों की भूमि के टुकड़े सडकों के नीचे चले जाते हैं। तो कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं सोचती कि जागीरदारों को जिस तरह

(श्री बालूराम चौधरी)
जमीनों का मुआवजा दिया गया था तो क्यों नहीं काश्तकारों को भी मुआवजा ऐसा देते जिससे कि उनकी आजीविका चलती रहे। नाम मात्र का मुआवजा देते हैं, १००) रुपयों से उसका कुछ भी नहीं होता। तो जहां से रेल्वे लाइन निकलती है, सड़कें निकलती हैं, उनके नीचे काश्तकारों की भूमि आ जाती है तो उस भूमि का मुआवजा ऐसा देना चाहिये कि जिससे उसकी आजीविका चल सके।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात मेरी बाकी है, वह यह है कि जो भी बचाने वाले टैक्स हैं उनको नहीं बचाया जाता जैसें कई बार सदन में जिक्र आया कि रेवेन्यू कलेक्शन का ५ प्रतिशत पटेलों को छूट के रूप में दिया जाता है वह पटेलों को न देकर पंचायतों को दिया जाय। पी. सी. सी. ने भी यह प्रस्ताव पास किया और सुखाडियाजी ने भी यह स्वीकार कर लिया था पर हमेशा मीठे शब्दों में विधायकों को चकमा देकर बेवकूफ बना देते हैं। मुख्य मंत्री वादा करते हैं तो उस वादे को पूरा करना चाहिये वायदा पूरा नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास उठता है।

इसी तरह ग्राम पंचायतें बना दीं, पर आपके बजट में ग्राम पंचायतों के लिये क्या है ? ग्राम-सेवक, ग्राम-चाची, बढ़े मीठे मीठे नाम हैं और इन मीठे मीठे नामों के पीछे हमें भूल-भुलैया में डाला है। ग्राम पंचायतों से ग्राम-सेवकों का समन्वय नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है।

(३.२० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

हर गांव में उसे जमीन देकर डिमान्सट्रेशन देकर गांव वालों को बताया जाय कि नये साधनों से, नये तरीकों से इस तरह उपज बढ़ेगी। इसी तरह सहकारिता के जरिये ऋण देते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। अपनी खेती के डिमान्स्ट्रेशन के अनुसार गांव वालों को समान रूप से कृषि की ये चीजें, कृषि के सामान दिलावें ताकि वे किसी और काम में न आकर कृषि के ही काम में आये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : दो हरिप्रसाद हैं सदन में। मैं बोलता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा, कांग्रेस।

**डा० हरीप्रसाद शर्मा** (मंडावर) : उपाध्यक्ष महोदय, . . . . . . . . . . . . .

**एक माननीय सदस्य** : On a point of order, Sir.
कांग्रेस वालों को बहुत टाइम मिल चुका है, हमें टाइम नहीं मिला है।

**श्री हरिराम घारू** (सिवाना, सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें हरिजनों के लिये भी बोलना है, तो नम्बर निकाल दिया जावे, बारी बारी . . .

**श्री उपाध्यक्ष** : order!order please!! यथाशक्ति प्रयास किया जाता है कि सबको बोलने का मौका दिया जाये पर बोलना प्रारंभ करते हैं तो वे ही समय को निर्धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिये यह दिक्कत आती है।

**डा० हरिप्रसाद शर्मा** (मंडावर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का बजट सदन के समक्ष पेश करना और उसकी स्वीकृति लेना, यह प्रजातंत्रवाद की बहुत ही स्वस्थ प्रणाली है। यदि हम इंग्लैण्ड के इतिहास को देखें तो वहां हमें मालूम पड़ेगा कि साढे सात सौ साल गुजरे वहां उन्होंनें डेमोक्रेसी की कोई थ्योरिटिकल लाइन नहीं पकड़ी, उन्होंने मोटे मुद्दे की बात पकड़ी है, हाउस ऑफ कॉमन्स का बजट पर पूरा कण्ट्रोल रहे और इस राइट के बारे में वे इतने जेलस हैं कि हाउस ऑफ लार्ड्स को भी हटा दिया और आज स्थति यह है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का बजट के बारे में पूर्ण और ठोस जुरिस्डिक्शन है। इंलैण्ड ने वोल्टअर, रूसो, और मोन्टेस्क्यू पैदा किये, उनका सारा बैकग्राउण्ड इस एप्रोच को लेकर चला कि यदि सरकार के खर्च पर सही तौर से पाबन्दी लगा दें तो हमारा प्रजातन्त्रवाद सुरक्षित रहेगा। आज समय थोड़ा है इसलिये सब चीजें थोड़ी थोडी कहूंगा, पर एक दो चीजें जरूर रखूंगा। इंलैण्ड के प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन ने पूरे जोर से इस बात को कहा:

"The finances of the country are associated with the liberties of the country. It is a powerful of liberalism by which English liberty has been acquired. If the House of Commons by any possibility lost the control of the grants of public money........"

मतलब यह है कि इस चीज पर जितनी विश्लेशण किया जाय जितनी छानबीन की जाय, वह सब हमारे प्रजातन्त्र को, डेमोक्रेसी को आगे ही बढ़ाती है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक चीज और कह दूं, हमारे वित्त मंत्री मौजूद नहीं हैं, इंग्लैंड के अन्दर डिबेट होती है, उसके अन्दर भी बहुत जोरों से और जोरदार शब्दों में डिबेट होती है। एक डिबेट का एब्स्ट्रेक्ट जरा यहां संक्षेप में बता दूं २६. में इकोनोमी बिल के थर्ड रीडिंग के समय विस्टन चर्चिल ने खड़े होकर बताया कि इस रीडिंग में रोबेरी, डाका, राहजनी इन शब्दों का ६७ टाइम्स यूज हुआ है।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : यह राजस्थान है।

**डा० हरिप्रसाद** : मैं तो मोटे तौर पर बता रहा हूं कि वहां का ऑपोजिशन बहुत स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज करता है, "ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रोबरी'; इन शब्दों को यूज करता है........

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : तो उपाध्यक्ष महोदय, हम भी चोर डाकू कह सकते हैं?

**डा० हरिप्रसाद शर्मा** : यह रूलिंग तो चेअर से लेनी पड़ेगी। मैं इंलैंड की बात सुना रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : व्यक्ति को संकेत करके नहीं कह रहे हैं।

**डा० हरिप्रसाद शर्मा** : इस बारे में सदन जितनी जागरूकता बतावे वह हमारी परम्परा को आगे बढ़ाता है। पर साथ ही सदन की एक जिम्मेदारी इतने ही जोर से हो जाती है

(डा० हरिप्रसाद शर्मा)

कि वह भी जो विश्लेषण करे, क्रिटिसिज्म करें उतनी ही जिम्मेदारी से करे। आज हमारे सामने जो बजट पेश हुआ है वह एक खास परिस्थिति, खास टाइम को देख कर हुआ है, किस परिस्थिति में बनाया गया है और अगर उन परिस्थितियों को हम सही तौर पर नहीं समझें तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के भी पूरे तौर से अधिकारी नहीं हैं।

मोटे तौर से बैक ग्राउन्ड में मैं यह बता दूं, जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया में ३ रिवोल्यूशन हुए, फ्रेन्च रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन और तीसरा रशियन रिवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवोल्यूशन से पोलिटिकल रिवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवोल्यूशन से सोशियल और रशियन रिवोल्यूशन से इकोनोमिक रिवोल्यूशन हुआ। तो इन तीनों रिवोल्यूशन्स से जो कुछ हुआ उसको हम २०-२५ साल में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, यह एक भाग्य की प्रवंचना कहिये कि जब हम हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन से गुजरते हैं तो उसको महसूस नहीं करते हैं। हम दिलचस्पी से पढ़ेंगे कि रशिया में क्या हुआ, फ्रान्स में क्या हुआ? हम यह महसूस नहीं करते है कि हम खुद एक रिवोल्युशन के अन्दर हैं। अभी अखबारों में पढ़ा। ईराक में रिवोल्यूशन हुआ। रिवोल्यूशन का आज जो मतलब हो रहा है वह यह होता कि लोग सड़कों पर आ गये और जो गवर्नमैन्ट है उसको हटा कर फैंक दिया। हम रिवोल्यूशन का मतलब नहीं समझे हैं। मैं बड़ी अदब से पेश करता हूं कि वह रिवोल्यूशन है कि जो राजस्थान सूखे टीबों में लाखों सालों से पड़ा हुआ था और हिमालय का जो बर्फ है जो लाखों सालों से इसी प्रकार से पड़ा रहा है उसको चेनल करके, उसको हारनेस करके पानी यहां ला रहे है। ईराक में रिवोल्यूशन हुआ, फोरिन कन्ट्रीज का नाम नहीं लेना चाहिये, किन्तु मैं एक एग्जाम्पल के बतौर कहना चाहता हूं। ६-७ साल पहले मेजर जनरल कासिम की गवर्नमेन्ट आयी और सात साल बाद दूसरे जनरल आ गये। और वे हटा दिये गये। रिवोल्यूशन का मतलब जो आजकल कर रहे हैं वह मतलब नहीं है। हम सब लोग चले जावेंगे यानी मर जावेंगे, पांच सौ, सात सौ साल गुजरेंगे, इतिहास लिखा जायगा, और इस डिबेट का एक मतलब निकलेगा तो यह निकलेगा कि यहां भाखरा डेम बना, राजस्थान कैनाल जैसी चीज बनी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें प्रोपर पर्सपेक्टिव रखना चाहिये और जिस टाइम और जिस ढंग से गुजर रहे है उस को अगर सही तौर पर सामने नहीं रखते हैं तो इन चीजों की प्रगति समझने में दिक्कत आयगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**माननीय उपाध्यक्ष**, मेरी पार्टी का काफी समय है।

**श्री उपाध्यक्ष** : There are quite a number of people to speak and, therefore, I would request you to confine your speach within as little time as you can.

**डा० हरिप्रसाद शर्मा** : तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कह रहा था।

दूसरी चीज जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे सामने

(डा० हरिप्रसाद शर्मा)

इस साल के दर्मियान में खबर आयी कि एटोमिक एनर्जी का स्टेशन राणा प्रतापसागर के पास बनेगा और हमने उस चीज को इतना ही महत्व दिया कि बडी चौपड़ से छोटी चौपड़ के बीच में एक प्याऊ हो जाय या बस स्टैन्ड हो जाय। हमने यह कतई नहीं समझा कि कितना बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो रहा है, इस चीज से। इतिहास लिखा जावेगा तो यह लिखा जावेगा कि इस साल में यह एटोमिक एनर्जी हार्नेस की खबर यहां आयी! माननीय उपाध्यक्ष, एटोमिक एनर्जी के बारे में दो मिनट जरूर कहना चाहूंगा। दुनियां में बडी बडी डिस्कवरीज हुई हैं, हजारों साल से होती रही हैं, न सिर्फ चीन, रशिया और अमेरिका में हुई, सारी मानव जाति के बारे में डिस्कवरीज हुई हैं, बडी भारी डिस्कवरीज हुई हैं, न्युटन लॉज आदि उनके मुकाबले में एटोमिक इनर्जी को हार्नेस करने की बडी भारी डिस्कवरी हुई हैं। आज से ठीक २० वर्ष पहले, १९४३ की बात है, हमको कतई मालूम नहीं था कि हमारे हाथ में एक ऐसी चीज आ जावेगी, मैं निवेदन करूं कि जो अकाउन्ट्स इस सम्बन्ध में मैंने पढ़े हैं, ऐन्स्टाइन जो दुनियां का सबसे बड़ा साइन्टिस्ट माना जाता है······

तो मैं यह कह रहा था कि साइन्टिस्ट ऐन्स्टाइन एक दफा प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट के सामने गये और यह बात कही; "Mr. President, we can do this job."

प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट का उत्तर यह था "The nation should trust in him." मेरे कहने का मतलब यह है कि इस चीज का महत्व सही तौर पर मानें। क्या चीज थी? हजारों साल आगे के लिये एक नयी चीज खुली है। उस चीज को राजस्थान में ले आये और उसकी जरा चर्चा भी सदन में नहीं। यहां पटवारी और पुलिसमेन का दुख कहा जाता है, सही है। यह जान लेते हैं कि उसको लाकर सही सेवा करते हैं लेकिन साथ साथ सेन्स ऑफ प्रोपोर्शन नहीं छोड़ देना चाहिये, इसका हमें ध्यान रखना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, कुछ साल पहले यहां केथोराइन मेयो की किताब लिखी गई थी। यह कुछ पर्टीनेन्ट मालूम पडता है। केथोराइन मेयो ने मदर इन्डिया कि सारी बुराइयां लिख दीं। सारी बुराइयां ही देखीं, अच्छाई कुछ नहीं। मक्खी, मच्छर, गन्दगी, आदि सब कुछ लिखा। बनारस के लिये लिखा कि पानी है वह लिक्विड सीवेज है और किनारे हैं वे सोलिड सीवेज हैं। पहले ऐसा होता था कि दस दस वर्ष की लडकियों का ६० वर्ष के बूढों से शादी विवाह कर दिया जाता था और अस्पतालों का जिक्र करते हुए लिखा कि गंदगी है···

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): हमारी पार्टी के दस मिनिट बाकी हैं।

**डा० हरिप्रसाद शर्मा**: इस तरह से केथोराइन मेयो की किताब का सवाल जब गांधीजी के सामने आया तो गांधीजी ने कहा कि रिपोर्ट और किताब सही तो हैं, लेकिन यह एक सिवेज इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है। सारा ध्यान एक तरफ गया उसका कि एक सिवेज की तरह है। उसने अच्छाई नहीं देखी। तो गवर्मेंट की गलतियां बता देने से पिक्चर कम्पलीट नहीं होगी।

# Page No.65



(डा० हरिप्रसाद शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष, इसके बाद मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो भी कुछ हमारे यहां तीन फाइव इयर प्लान्स चल रहे हैं, इनमें जो भी हम कर पायेंगे, हार्ड डिसिप्लिन और कोई शार्ट कट नहीं है। कॉम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बोलते हैं, लेकिन रिवोल्यूशन का मतलब नहीं समझे हैं। लेनिन और स्टालिन सबके सब एक मत हैं इस माने में कि जब तक अन्डर डेवलप्ड कन्ट्री है और डेवलपमेन्ट की स्टेज को पार करते हैं तो दिक्कतें उठानी पडेगी और रोज की चीजों को इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। जो कुछ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स हैं उनको मान कर हमें चलना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक चीज डेवलप्मेन्ट में जो हमेशा होनी चाहिये वह है इन्वेस्टमेन्ट; इसके लिए टेक्सेशन करें या बोरोइंग करें। दूसरे देशों में बोरोइंग अधिक होता है। दूसरी चीज टेक्सेशन की रह जाती है। टैक्सेशन, आज यह सच है, चाहे १७६ आदमियों में से एक ही रह जाऊं मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। यदि हम प्लान्ड इकॉनोमी का रास्ता ग्रहण करते है, उसको मानते हैं तो टैक्सेशन का भार स्वीकार करना पडेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप इससे आगे किसी नतीजे पर न पहुंचे मैं यह कह दूं कि जो टैक्स आज हमारे किसानों पर लगाये जा रहे हैं, या जो टैक्स अनाज पर लगाये जा रहे हैं उनका समर्थक मैं भी नहीं हूं।

लेकिन कारण मेरा दूसरा है। इस चीज को लेकर नहीं चलता कि ऑपोजिशन के लीडर ने कहा कि कमर तोड है, सिर तोडा है या हड्डी तोड़ी है या जो जो एड्जेक्टिव उन्होंने प्रयोग किये। जवार, बाजरे को लेकर काफी रोष प्रकट किया गया। अगर एक फेमिली जिसके अन्दर ६ आदमी हैं, बाजार से यदि साल भर के लिए भी जवार खरीद करता है और यदि साल भर में अधिक से अधिक तीस मन का उसका खर्चा है तो साल भर का उस पर कुल १०) रु० टैक्सेशन है और प्रति आदमी के ऊपर १) साल भर का टैक्स पड जाय तो कमर-तोड, सिर-तोड या हड्डी-तोड नहीं है। मैं समझता हूं कि यह संज्ञा जरा जिम्मेदारी से आनी चाहिये। किन्तु जिन कारणों से मैं इसके खिलाफ हूं थोडी देर बाद पेश करूंगा।

**एक माननीय सदस्य** : समय का ख्याल रखें।

माननीय उपाध्यक्ष, दूसरी चीज जो मैं पेश करना चाहता हूं वह यह कि यह बजट जिस टाइम पर पेश हुआ उस समय को भी हमें ध्यान में रखना है। चीनियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया हमारे साथ जो धोखा किया वह इस समय कहने का वक्त नहीं है। लेकिन एक चीज हमें हमेशा निगाह में रखनी होगी। आज आजादी संभालने का बोझ हमारे पर है। हमारी पहली पीढी चली गई, उसका उत्तर-दायित्व हमें निभाना है। लाखों आदमी फांसी पर चढ गये, लेकिन हम आज के दिन कई एक बातें आसानी से कह देते हैं, यह भी कहा जाता है कि हम अपनी अन्तिम बूंद तक लडेंगे, लेकिन कभी कल्पना की है लडाई की। लडाई में क्या होता है ? यदि हम आजादी को रख नहीं पाये तो आने वाली पीढी के सामने क्या जवाब दे पायें। आज के समय हमारे पर चीन का आक्रमण है; मुझे माफ करें, मझे वडा खेद है कि जो चीन के आक्रमण के प्रति सदन के अन्दर जो भावना होनी चाहिये वह अदब के साथ कहना चाहूंगा वह देखने में नहीं मिली।

(डा० हरिप्रसाद शर्मा)

कि कुछ पार्टीज की निष्टा किसी के साथ हो सकती है, किन्तु जो दर असल खतरे की चीज है उस पर तो हमें ध्यान देना होगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अब अपने विषय पर आ जावें तो ठीक ह ।

**डा० हरिप्रसाद** : यह मैंने जिक्र इसलिये किया है कि हमारे प्रधान मंत्री हमारे प्रेसीडेन्ट और हमारे डिफेन्स मिनिस्टर रोजाना इस बात को कह रहे हैं, डे आफटर डे कह रहे हैं कि खतरा हटा नहीं और कॉम्पलीसेन्सी इजहार करते हैं; कल से अगर लडाई शुरू हो जाती है तो जनता को जाकर हम क्या जवाब देंगे ? आगे होने वाली लडाई का स्वरूप क्या होगा, यह वह पोइन्ट है जिससे हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिये । मैं यह नहीं मानता कि किसी में देश भक्ति की कमी है, लेकिन एक चीज जरूर है कि लडाई किस तरह की होती है इसका अनुभव हमको नहीं है। हम रिजोल्यूशन पास कर दें या किसी जगह चल कर भाषण दे दिया, इसी से जिम्मेदारी खत्म हो गई, यह नहीं मानना चाहिये। जिन लोगों ने पिछली लडाई में भाग लिया उस समय क्या चीजें हुई बर्लिन, मॉस्को आदि शहर जहां लडाई का असर पडा उस लडाई में इतना सारा मलवा इकट्ठा हो गया जिसको हटाने में काफी अर्सा लगा । अभी तक उसके निशान मौजूद हैं । एक अमेरिकन ने लिखा है कि एक सोल्जर को लडाई में तीन-चार टन लोहा १५ आदमी फैक्टरी में काम करने के लिये चाहिये तब जाकर एक सोल्जर को मेन्टेन कर सकते ह । अभी एक बडे नेता नेफा के इलाके में घूमकर आये और उन्होंने यहां आकर कहा कि एक सौ गायें हरियाना की मिल जायें तो उनको पीने के लिये शुद्ध दूध मिल जायेगा । वैसे तो यह बात बडी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो टोटल इग्नोरेन्स है वह जाहिर होती है । कभी उन्होंने यह नहीं सोचा कि जो बीस हजार फीट ऊपर लड रहे हैं उनके लिये कैसे संभव हो सकेगा १०० गायें रखने का ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य १५ मिनट से ज्यादा ले चुके हैं ।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के अभी दस मिनिट बाकी हैं हमें बोलने का मौका दिया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय कम होने की वजह से जितना एडजस्टमेन्ट किया जा सकता था किया । उसके लिये पार्टीज को पर्याप्त समय भी दिया जा चुका है यदि उस हिसाब से देखा जाय तो सभी पार्टीज का समय बाकी रह जाता है । इतना एडजस्टमेन्ट करने का प्रयास किया गया है जो बिल्कुल बियर किया जा सकता है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : आपका भाषण चौपड पर रखा जाता तो अच्छा था ।

**डा० हरिप्रसाद शर्मा** : लडाई की जिम्मेदारी को समझ कर लोगों ने खुल कर चन्दा दिया, ग्रामीण जनता ने चन्दा दिया और भी जरूरत पडी तो इससे चार गुना, आठ गुना तक यह देश देने को तैयार है, इसमें शक नहीं लेकिन इसके साथ साथ जनता को यह विश्वास होना चाहिये कि गवर्नमेन्ट जो हमारे पास से पैसा ले रही है वह सही तरीके से खर्च कर रही है ....

**श्री मानिकचन्द सुराणा** ( कोलायत ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया उस पर बहुत टीका टिप्पणियां हो चुकी हैं । अभी अभी

(श्री मानिकचन्द सुराना)
माननीय श्री हरिप्रसादजी ने इन करों की आलोचना की और हमारे वित्त मंत्रीजी को सिवेज इन्स्पेक्टर की उपाधि देकर उन्होंने भी इन करों का विरोध अभी अभी किया है।

इन करों के मुतल्लिक तो मैं कहूंगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कुल बजट पर यदि कुछ राय जाहिर की जावे तो मैं समझता हूं कि यह कहना बहुत उचित होगा कि हमारे वित्त मंत्री राजस्थान के वित्त मंत्री की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार के एक टैक्स कलेक्टर की तरह या बिल कलेक्टर की तरह कार्य कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री को इस बात की चिन्ता नहीं है कि राजस्थान के आर्थिक विकास के लिये पैसा कहां से आवेगा, पर उनको चिन्ता इस बात की है कि भारत सरकार से लिये हुए कर्जे की किश्त किस तरह से चुकाई जावेगी।

मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बजट, हम समाजवाद के सिद्धान्तों की बहुत चर्चा करते हैं, उस पर चलने का दावा करते हैं, अपना लक्ष्य बताते हैं, पर हमें यह बजट हमारे उस समाजवाद के लक्ष्य की तरफ किसी प्रकार भी आगे नहीं बढाता। यह बजट जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जनता को जगाने वाला जरूर है, पर सरकार को नींद में सुलाने वाला भी है।

सरकार और वित्त मंत्रीजी ने जो चित्र पेश किया है, मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिये तो बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे वित्त मन्त्रियों, पुराने वित्त मन्त्रियों द्वारा की गई गल्तियों का लेखा-जोखा दिया और यह बताया कि दूसरी योजना में किस प्रकार साधन और साध्य में फर्क बढता गया और किस प्रकार साधन हमारे आज से कम रहे। हमारे साधन कम रहे और हमारा खर्चा बढता रहा। इसका उन्होंने दिग्दर्शन कराया। ६१-६२ में १५ करोड का कर्जा लिया गया भारत सरकार से और नये वित्तमन्त्रीजी के आने के बाद २० करोड का कर्जा और लिया गया भारत सरकार से और रिजर्व बैंक को चुकाया गया। इस पर भी सन्तोष है हमारे वित्त मंत्रीजी को कि आज सरकार पर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है। एक कर्जा नया लिया और दूसरा कर्जा चुका दिया और इस पर भी सन्तोष जाहिर किया है, यह हमारे वित्त मन्त्रीजी की समझ की बलिहारी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को हम आगे बढाना चाहते हैं तो इसमें न तो पुराने वित्त मन्त्रीजी की जो नीति थी कारगर हो सकी, न नये वित्त मन्त्रीजी की नीति जो कि बहुत कुछ इन्श्योरेन्स एजेन्ट की सी लगती है, वह कारगर हो सकती है। मुझे ताज्जुब होता है जब मैं सुनता हूं वित्त मन्त्री की तरफ से भी कि हमारे साधन कम हैं और जब यह सुनता हूं विरोधी दल के नेता की ओर से कि चूंकि राजस्थान के साधन कम हैं इसलिये इस प्लान को छोटा कर दिया जाय, इसे काट दिया जाय। मुझे अफसोस है कि जनसंघ के नेता ने भी यही राय जाहिर की है कि प्लान काट दी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की राय राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था से बिल्कुल नासमझी के आधार पर जाहिर की जा रही है जो हमारे आगे के आर्थिक विकास को रोकेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति व साधन इस प्रकार के हैं कि अगर

# Page No.68



(श्री मानिकचन्द सुराना)
सरकार ठीक ढंग से उनको समझे, आंखें खोलकर उनको देखे और उनका प्रयोग करे तो राजस्थान का न सिर्फ कोर आफ दी प्लान को ही बल्कि नॉन-कोर-ऑफ दी प्लान को भी पूरा करने में समर्थन है, इनको पूरा करने के पर्याप्त साधन उसके पास हैं।

मैं चार्ज लगाना चाहूंगा सरकार पर कि सरकार में भी इनको पूरा करने की निष्ठा नहीं है। प्लान के प्रति ईमानदार नहीं है। जो बजट उसका पेश है उससे लगता है, उसकी नियत उसे पूरा करने की नहीं है। मैं वित्त मन्त्री को बताना चाहूंगा कि अगर आप और आपकी सरकार ने और आपके मुख्यमन्त्री ने जिस ८० करोड को पैदा करने की बात की थी कि ८० करोड के साधन योजना-काल में इस राज्य को जुटाने होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस ८० करोड के एक एक पैसे को वसूल करने की पूरी योजना बनाई है और इसके बाद भी कहते हैं वे कि इससे पूरी नहीं होगी वह योजना ?

मैं याद दिलाता हूं कि पहली बार कोर ऑफ दी प्लान में २०० करोड लगाने की बात कही गई और इसके लिये २४ करोड के टैक्स लगाने की बात कही। इस तरह अपनी प्लान के लिये १४९० लाख की घोषणा की गई और इस घोषणा के साथ यह घोषणा भी की कि आगामी दो वर्षों में फिर कोई टैक्स नहीं लगावेंगे। १४९० लाख की योजना से तीन साल में १४ करोड रुपया नये टैक्स से मिलेंगे। ६ करोड पिछले साल मिल चुके हैं। १९६०,६१-६२ में टैक्स लगाये। ६ करोड के करीब, २४ करोड के टैक्स वे कुल लगा चुके हैं और किस प्रकार की यह आपकी टैक्स की नीति है यह तो वित्त मंत्री अपने भाषण में बतायेंगे; पर जो बात पहले उन्होंने कही थी कि उसके अनुसार वे घोषणा कर दें कि नये टैक्स नहीं लगावेंगे। पर मैं नहीं समझता कि वे ऐसी घोषणा करेंगे। पर अगर वे २४ करोड के टैक्सों तक ही सीलिंग करना चाहते हैं और मैं जानता हूं कि वे लगावेंगे। उनको आवश्यकता है। पर ३२ करोड के टैक्स भी वसूल करें और इसके साथ ही मैं बताऊं कि आपने अपने ८० करोड की मद में दूसरी मोटी बात बताई कि आपके कैपिटल रिसीट हैड में ३३ करोड, ९६ लाख आये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आपने ३३ करोड, ९६ लाख में से करीब २७ करोड रुपया आज की तारीख तक इस वर्ष में कैपिटल रिसीट में पैदा कर लिये हैं, आपने २७ करोड के साधन जुटा लिये हैं। ये पब्लिक डेट के आंकडे हैं।

इन पब्लिक डेट के आंकडों को देखने से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वित्त मंत्री ने २७ करोड रुपयों की कैपिटल रिसीट प्राप्त कर ली है। उनमें जो ८ करोड का पब्लिक लान लिया है। उनको भी शामिल नहीं किया है। अगर उसको शामिल करते हैं तो ३५ करोड होते हैं और स्पेशल लोन जो भारत सरकार से लिये हैं वे भी शामिल नहीं किये हैं, अगर उसको भी शामिल करते हैं तो ५५ करोड हो जाते हैं। यह दूसरा सबसे बडा सोर्स है।

तीसरा सब से बडा सोर्स है पब्लिक स्माल सेविंग्स का। इससे १० करोड रुपया हुआ। आप कहते हैं, हमारे सेविंग में ज्यादा आमदनी नहीं हुई। सेविंग में रुपया बचा नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगा हम जयपुर और

# Page No.69



(श्री मानिकचन्द सुराना)

दिल्ली की सरकार में फर्क नहीं समझते हैं। दोनों जगह कांग्रेसी सरकारें हैं। अगर दिल्ली सरकार ने भी ३।। करोड रुपया प्रतिवर्ष सेविंग के द्वारा पैदा कर लिये हैं, ५९-६० के लैंग्ड रेवेन्यू के आंकडों में ७ करोड की प्राप्ति हुई। इसका पचास प्रतिशत कम्पल्सरी ३।। करोड रुपया गांवों के सेक्टर से, किसान वर्ग से मिलेगा। यह तीन वर्षों में १०।। करोड होगा। आप दलील देंगे कि यह रुपया हमारे पास नहीं आवेगा। पर आप दबाव दीजिये कि स्टेट की इनकम तीसरी योजना के लिये जो रखी गई थी, आप नहीं खा सकते। वित्त मन्त्री महोदय को मैं इसके लिये आगाह करदूं कि जिस प्रकार भारत सरकार आपकी बहुत बडी सेविंग के सेक्टर को खा गई उस तरह आप भी उस जुर्म से बचे नहीं हैं। पंचायत समितियों के सोर्सेज आॅफ लैन्ड रेवेन्यू को आप भी खा गये हैं। आपने उस पर भी २५ प्रतिशत लैण्ड रेवेन्यू पर टैक्स लगाया है जो पंचायतें केवल पांच प्रतिशत तक ही लगा सकती थीं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, ३३ करोड रुपया आप कैपिटल रिसीट्स में ५ सालों में पैदा करेंगे क्योंकि २७ करोड रुपया आप कर चुके हैं। स्माल सेविंग में दस करोड दे रहे हैं। पब्लिक लोन में २० करोड में से ८ करोड ले चुके हैं, ५ करोड और लेंगे। १३ करोड ले चुके हैं और ७ करोड लेंगे। तो आप इन मदों में पैसा ले रहे हैं। अब सिर्फ कह सकते हैं तो यह कह सकते हैं कि सेल आॅफ लैण्ड और बैटरमेन्ट लेवी से जो आमदनी होनी थी वह नहीं हुई। तीसरी योजना जो आपने प्रकाशित की है अपनी, उसके पेज १९ पर आपने प्रकाशित किया है उसकी रिसीट और एक्सपेन्डीचर की मदों को देखें तो पता लगता है कि २०९ करोड की आपको रेवेन्यू रिसीट करनी थी। पर मैं बताना चाहता हूं कि आपने कितनी की है। आप इन पांच सालों में २०९ करोड नहीं, २९० करोड की रिसीट्स कर रहे हैं और इसके बावजूद ८१ करोड के बढाने के बावजूद, २१ करोड चूंकि पूरे नहीं हुए इसलिये हम तीसरी योजना को पूरा एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं।

यदि माननीय वित्त मन्त्रीजी को संशय हो कि ये २९० करोड के फीगर्स किस तरह से आये हैं क्योंकि मैं उनकी मुद्रा से यह समझ रहा हूं कि उनको इसमें संशय है या ये २९० करोड के फिगर्स गलत हैं। जानकारी उनको है वैसे। पर फिर भी उनकी जानकारी के लिए, सरकार की जानकारी के लिये और सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में फर्स्ट इयर आॅफ दी थर्ड प्लान में . (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) ४६ करोड की रेवेन्यू रिसीट हुई है और ६० करोड की १९६२-६३ में हुई है। ६३ करोड इस साल एस्टीमेट करते हैं तो इस तरह ये १२१ करोड बचते हैं, वे आप और मदों में प्राप्त कर चुके हैं। तो यह कुल २९० करोड की रिसीट होती है। २०९ करोड के अगेन्स्ट में २९० करोड की रिसीट करें और सिर्फ २१ करोड आपके पास नहीं आ रहे हैं सेल आॅफ लैन्ड और बैटरमेन्ट लेवी से, इस दलील पर आप तीसरी योजना पूरी करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्लान को २२६ करोड से २०८ करोड करदें तो इसका कोई आधार नहीं है, औचित्य भी नहीं है

(श्री मानिकचन्द सुराना)

वित्त मन्त्रीजी से में निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार के रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर अनावश्यक रूप से बढते जारहे हैं और प्लान एक्सपेन्डीचर को बढा नहीं पारहे हैं जिसमें ८ आने पर आठ आने भारत सरकार भी देती है, कहीं कहीं चार आने पर बारह आने भारत सरकार देती है। पर प्लान एक्सपेन्डीचर कम करते हैं और अगर नियोजित रूप से आपकी सरकार रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को बढाती है और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में सबसे बडा मद कोई है मेरे बहुत से साथियों ने प्रशासनिक खर्चे की चर्चा की लेकिन मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, सरकार के पास आंकडे नहीं हैं तो मैं दो फिगर्स कोट करूंगा १९५७-५८ के आपके बजट की स्टडी नेशनल कौन्सिल आफ एप्लाईड इकानोमिक रिसर्च नई दिल्ली ने जो की है उसके आंकडे आप देखिये। उन आंकडों के आधार पर राजस्थान राज्य में १९५७-५८ में प्रशासनिक खर्च ४१ पर्सेन्ट है। २६ करोड के रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में आपका १० करोड ८९ लाख रुपया सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च किया है, ४१ पर्सेन्ट जो उसका होता है और यह १९६०-६१ की स्टेट की डाइजेस्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पी. एच. डी. के स्कॉलर ने निकाली है उसके आधार पर ४० करोड रुपया १९६०-६१ में जो खर्च किया है उसमें से ४५ पर्सेन्ट खर्च आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन-सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशाशन, जेल प्रशासन और इन सारे प्रशासनों का ४५ पर्सेन्ट का खर्च है। कितना खर्च बढ गया? ४० से ४५ पर्सेन्ट हो गया और जहां कुल रेवेन्यू एक्सपेन्टीचर आपका २६ करोड था वहां १४ करोड का रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर बढा है, लेकिन उसके साथ प्रशासनिक खर्चा जो है वह १० करोड से बढकर १७ करोड हो गया। बढ हुए १४ करोड हैं साढे छः करोड का खर्च प्रशासनिक खर्चे पर पडा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक उदाहरण देकर इसको समाप्त नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मूल और एब्स-ट्रेक्ट जो कि इकोनोमिस्ट्स हैं हिन्दुस्तान के उन्होंने जो डाइजेस्ट तैयार की है १९५७-५८ में उसमें से एक आंकडा देता हूं जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ने दूसरे आंकडे दिये हैं इसलिये मैं आपको हिन्दुस्तान के बहुत बडे सर्वे-शास्त्री डी.एन. शिनोई ने की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा और प्रशासन दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान के प्रशासनिक खर्चे को १९५४-५५ के मद तक सीलिंग करना होगा। आप इससे अधिक खर्च को नहीं बढा सकते। इसके बावजूद आप रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को बढाते हैं तो नतीजा यह होगा कि प्लान एक्सपेन्डीचर में आपके पास पैसा नहीं है, नये स्कूल नहीं खोल सकते, एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर नहीं खोल सकते, एक सडक नहीं बना सकते, आप क्या कर सकते हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं। आप तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बढा सकते हैं और सारी इकोनोमी को अनबेलेन्स्ड कर सकते हैं। आपने जो इस बजट में ४॥ करोड रुपये के नये टैक्सेज प्रतिपादित किये हैं मैं उनका विरोधी हूं और इनका सभी माननीय सदस्यों ने विरोध भी किया है, लेकिन मैं उनमें से नहीं कि आप टैक्स न लगायें। आप टैक्स जरूर लगायें, लेकिन मैं आपका ध्यान उस

(श्री मानिकचन्द सुराना)

ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप टैक्स किस ओर लगा सकते हैं ? आपके डाइरेक्टर ऑफ इकोनोमिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स ने स्टडी दी है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने और आपने भी यह आंकडे नहीं पढे हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपने आंख खोलकर उनको देखा तक नहीं है। आपका कहना है कि राजस्थान की ग्रोस इनकम बढ गयी है और १९५४-५५ की कान्सटेन्ट प्राईस पर हम मान लेते हैं की ८४ करोड का मुनाफा हो गया है लेकिन वह ८४ करोड १९५४-५५ में जिसकी प्राइस १९६१-६२ में २०० करोड होती है जिन लोगों की जेबों में वह रुपया पडा है और १९५४-५५ में ८४ करोड रुपया जिनकी जेबों में पहले गया है आपको फुरसत नहीं कि आप उनकी जेबों में हाथ डालें। लेकिन आप तो किसानों की जेबों पर हाथ डालेंगे। आप कहते हैं कि २४० रुपया नेशनल इनकम हो गयी। कॉन्सटेन्ट प्राइस हम मानते हैं और १९५४-५५ में भी २३३ थी। आप कहते हैं कि १३ रुपये बढ गयी लेकिन यह आपको 'बजट स्टडी' कहता है पेज ३३ पर कि किसानों की इनकम, की मद को छोडिये यह ऊपर के चार विभाग हैं एनीमल हस्बेन्डरी, एग्रीकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्स-इन चारों की इनकम जोडेंगे तो ३०० करोड की टोटल नेशनल इनकम राजस्थान को मिलेगी और ३०० को घटा दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जरा इन आंकडों को समाप्त कर लूं। १९६०-६१ की प्राइस पर यदि आप १९५४-५५ की प्राइस पर ले लें और उसमें १॥ करोड आदमी जी कि राजस्थान के गांवों में रहते हैं, जो एग्रीकल्चरस्ट्सि हैं एग्रीकल्चर लेबर हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका आंकडा ७५ पर्सेन्ट आता है उसे डिवाइड कर दें तो ग्रामीणों की आमदनी १६० रुपये के करीब आती है। यानी शहर में रहने वाले की इनकम २३६ रुपया प्रति व्यक्ति और गांव में रहने वाले की आमदनी १६० रुपया है। क्या अधिकार है कि आप उसके ऊपर और टैक्स लगायें जिनकी जेब पहले से बहुत भरी हुई हैं जिनमें ८४ करोड रुपया पहले ही पहुंच गया है आप उनकी तरफ तो इशारा न करें और गरीबों पर ही और टैक्स लगायें, यह कहां का न्याय है आपका ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सारी की सारी जो टैक्स की पालिसी है वह बहुत ही रिट्रोग्रेड है। हम चाहते हैं कि आप अपने प्लान के प्रति फेथफुल रहें, आप प्लान के टारगेट्स को पूरा करें।

अभी हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने आंकडे दे दिये कि ४४ पर्सेन्ट बच्चे जिनकी आयु ६ से ११ वर्ष की है स्कूलों में जाते हैं। आपको मालूम है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना आंकडा ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों का स्कूल जाने का रखा गया है। वह आंकडा है ६६ पर्सेन्ट। अभी तो आपने राजस्थान को दुसरी योजना में खडा कर रखा है, प्रगति करने का नाम ही नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं कि हम २५० स्कूल खोलेंगे। आप ही बताइये कि इससे कितना आंकडा आता है वह आता है ०.५० के करीब, नेग्लीजीबल। इस रेट से न तो आप स्कूलों के आंकडे पूरा कर सकते हैं, न सहकारिता के आंकडे पूरा कर सकते हैं। हमारे सहकारी मन्त्री जानते हैं। उसमें

(श्री मानिकचन्द सुराना)
जहां हमने टार्गेट ६७ पर्सेन्ट जनता को कवर करने के लिये रखा है वह राजस्थान में उसके आंकडे १९६२-६३ की समाप्ति तक ४७-४८ पर्सेन्ट आता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सेज उन लोगों से वसूल करें जिनकी नशनल इनकम बढी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं उन तीन चार मदों की तरफ इशारा करूंगा कि जिससे हमारे रेवेन्यू बढ सकती है और इस बात को रखते हुए कि हमारे प्रशानिसक खर्चे में बहुत बडी कमी की जानी चाहिए जो खर्चा १९५७-५८ में साढे ६ करोड का १९६०-६१ में बढ गया हमें संतोष नहीं कि ४० लाख की कटौती करदी। मैं यह कहना चाहूंगा कि आखिर विधान सभा में जब आप वक्तव्य देना चाहें तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां माननीय सदस्यों को सब चीजों की जानकारी है– चाहे जानकारी न हो पर फिर भी सदन को सारे तथ्यों की जानकारी होती है इसलिए किसी भी प्रकार से सदस्यों को यदि भ्रम में रखना चाहें ४० लाख की कटौती करके और किसी प्रकार का सर्टिफिकेट लेना चाहें कि हमने बहुत अच्छा काम किया है वह सर्टि-फिकेट तो हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम कहते हैं कि आपने गलत प्रकार से साढे ६ करोड का खर्चा वढा दिया। इसलिये आपको अब घोषणा करनी चाहिए कि आगामी वर्षों में प्रशासनिक खर्च नहीं बढेगा, रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर नहीं बढेगा और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के बजाय प्लान एक्स-पेन्डीचर को बढायेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासन के बारे में एक उदाहरण देकर कि किस प्रकार से जो प्रशासन के अधिकारी हैं और किस प्रकार से हमारी सरकार डील करती है कह कर समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान के शहर हैं, शहर में मकानों के मालिक हैं, लैण्ड ओनर्स हैं उनके ऊपर आप अपना टैक्स डाल सकते हैं और जिस प्रकार २५ पर्सेन्ट लैण्ड रेवेन्यू पर डाला है उसी प्रकार से किराये की आमदनी पर २५ पर्सेन्ट का टैक्स आप राजस्थान में लगायेंगे तो १०॥ करोड की आमदनी कर सकते हैं और उसे आप रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिये इन बातों पर मैं विस्तृत विवरण न देकर यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रशासन का और जुडिशरी का ढांचा है उसका एक उदाहरण दूंगा।

नीम-का-थाना, जहां कोई केस हुआ और उस केस में वहां के मजिस्ट्रेट ने एक लडकी का बयान लिया ३७६ में कि ताजीरात हिन्द की धारा ३७६ में मेरे साथ इस तरह का जुर्म किया गया और उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, उन मजिस्ट्रेट महोदय ने दूसरा बयान लिया। पहला बयान इस बात का था कि ४॥ बजे रात को उसके साथ में रेप कमिट किया गया और दूसरा बयान मजिस्ट्रेट साहब ने जो मुस्तगीस थे उनसे मिलकर बनाया कि ७॥ बजे रेप किया गया और वह कागज दिये कि जो पार्टी मुलजिम के खिलाफ थी कि आप हस्ताक्षर करवा लायें, और वह मजिस्ट्रेट का बयान है, वह मेरे पास जिसकी फोटेस्टेट कॉपी में इस सदन में पेश करूंगा। वह बयान, लडकी ने दस्तखत

(श्री मानिकचन्द सुराना)

करने से इन्कार कर दिया··········

और उसके बाद में उस मुल्जिम के बयान पर कार्यवाही की गई। बयान मजिस्ट्रेट के हाथ का लिखा हुआ है उसको सेशन्स जजी में पेश किया गया, जिस पर सेशन्स जज ने फौरन मुल्जिम को रिहा किया। मुझे जुर्म से मतलब नहीं, जुर्म करने वालों से मतलब नहीं, या मुल्जिम को बचाने वालों से मतलब नहीं है, किन्तु मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट ने दो बयान किस तरह से लिखे और क्यों लिखे? हमारी सरकार ने जिस पर कि यह जिम्मेवारी है कि वह न्याय एडमिनिस्ट्रेटर करेगा कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से फोर्ज्ड डाक्यूमेन्ट्स बनाना क्या राजस्थान में परमिट किया जा सकता है और क्या राजस्थान सरकार ने उस पर कुछ कारवाही की?

गृह मन्त्रीजी ने कह दिया कि जांच हो रही है। हमें इस प्रकार की जांच से संतोष नहीं है। मैं राजस्थान के प्रशासन से सीधे लाइन्ड अप अधिकारियों की बात नहीं करता। जाने दें इन अधिकारियों को! कम से कम मजिस्ट्रेसी और जुडिशियरी को तो आप करप्ट नहीं करेंगे, और जो करप्ट हो जाते हैं उनको यहां से हटाने की योजना करेंगे। यह काम तो आप करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, उपाध्यक्ष महोदय,········

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस पर सरकार विचार करेगी और फौरन कार्यवाही करेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस तरह के बीसों उदाहरण हो सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं ह, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय से कि ४ करोड के टैक्सेज लगाते हुए राजस्थान का जो ८० करोड का कमिटमेन्ट है उस कमिटेड प्लान को भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं, इस लिए मैंने यह चार्ज लगाया है कि आप प्लान के प्रति फेथफुल नहीं हैं। आप यदि इस बारे में बहस करना चाहते हैं तो मैं बहस कर सकता हूं कहीं भी, यहां इस विधान सभा में कर सकता हूं कि आप ८० करोड में से एक एक पाई वसूल करेंगे और जो कुछ भी इसमें डिटेल दिये हैं इनके बावजूद आप किसी तरह भी प्लान को पूरा नहीं करेंगे··(समय–समाप्ति–सूचक घंटी) यह सरकार की राजनैतिक ईमानदारी का नमूना नहीं है, और चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री इस बारे में सरकार की जो नीति है उसका स्पष्ट उत्तर देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: सरकारी पक्ष।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य-मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस बार सदन में वित्त मंत्रीजी के भाषण के बाद इस बजट पर काफी सरगर्मी के साथ वाद-विवाद हुआ और कई प्रकार के सुझाव सामने आये। एक सुझाव यह था कि राजस्थान में हमारे पास साधनों की कमी है तो हम हमारी योजनाओं को सीमित साधनों को देखते हुए कम करके चलें। दूसरी तरफ यह सुझाव भी था कि हमें अपनी पंचवर्षीय योजना में कोर ऑफ दी प्लान ही नहीं बल्कि जो ओरीजिनल प्लान था उसकी पूर्ति हम करें। जहां तक अपनी योजनाओं को कम करने का सवाल है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)·

मैं ऐसा समझता हूं कि अपने साधनों को जितना बढाया जा सके उसको बढा कर जितनी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को हम पूरा कर सकें, उस प्रयत्न में यह सरकार विश्वास रखती है।

आज जब यह बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ और इस संबंध में चर्चाएं होने लगीं, तो खास तौर से दो बातों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिलाया गया और वे यह थीं कि हम प्रशासनिक खर्चों के अन्दर कटौती करें। दूसरा यह है कि हम नॉन-टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढायें, बजाय टैक्स लगाने के। जहां तक इन दोनों के पीछे उसूल का सवाल है मैं समझता हूं कि कोई मतभेद नहीं हो सकता नॉन-टैक्स रेवेन्यू के द्वारा ज्यादा से ज्यादा आमदनी सरकार के पास हो सकती हो, वह हम भी पसन्द करेंगे। साथ ही साथ खर्चे में जो कमी की जा सकती है उस कमी को करना हम भी पसन्द करेंगे। इस वर्ष में और इसके बाद भी कटौती करने का प्रयत्न करेंगे और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी कटौती सम्भव हो सकती है आगे भी सदन में जो सुझाव दिये गये हैं या जो हमारे दिमाग में सुझाव आयेंगे, उन सारी बातों को एग्जामिन करके जो कुछ किया जा सकता है यह सरकार अवश्य करेगी।

नॉन-टैक्स रेवेन्यू के संबंध में और दूसरे टैक्सों के सुझावों के सम्बंध में इस सदन में काफी जोरों से समाजवादी बजट और दूसरी बातों को लेकर नाना प्रकार के सुझाव रक्खे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भारतवर्ष की जो आर्थिक योजनाएं देश के अन्दर चल रही हैं एक बात साफ तौर से हमें समझकर चलना है कि हमारे देश में मिक्सड इकानोमी के आधार के ऊपर हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढा रहे हैं। हमें अपने देश में जो एक साम्यवादी अर्थ व्यवस्था है कि जिस अर्थ व्यवस्था के अन्दर प्राईवेट एन्टरप्राइज को बिल्कुल समाप्त करके सारे पब्लिक एन्टर-प्राइज रह जाते हैं, उसको स्वीकार नहीं किया है। जहां कुछ बडे उद्योग हैं और जो दूसरी इन्डस्ट्रीज हैं कि जिनका देश पर कोई असर पड सकता है और देश की कुन्जी बनती है, वे चीजें तो, उनको आज देश के अन्दर पब्लिक सैक्टर के अन्दर चलाया जा रहा है। इस सदन में जब इस प्रश्न पर विचार करें तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान अकेला इस बात का फैसला करना चाहे कि हां, अमुक उद्योग के ऊपर अमुक प्रकार का टैक्स लगाना चाहते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, उसके ऊपर भी गम्भीरता के साथ विचार कर लेना चाहिये। अभी राजस्थान में मुश्किल से कुछ चिमनियों से धुआं निकलने लगा है, राजस्थान में मुश्किल से नींव लगना शुरू किया है, कुछ जगह अभी कार्यवाही होना बाकी है, उस अवसर पर आज महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, बंगाल जैसे प्रदेश में, मद्रास और दूसरे प्रदेशों के अन्दर अगर वहां पर उद्योग लगाने की एक सुविधा है और राजस्थान अपने यहां एक दूसरी नीति अख्तियार करता है तो राजस्थान और यह विधान सभा यह समझती है कि वह उस नीति से राजस्थान के ज्यादा हित में कार्य नहीं है। तो हमें फिर सारी बातों को सोचकर उस निर्णय पर पहुंचना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, आज राजस्थान में और जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेश हैं उनके बीच में बडा भारी अन्तर

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

पड जाता है । जो विकसित प्रदेश होते हैं औद्योगिक दृष्टि से, जहां उद्योग होते हैं, आज ही जो उद्योग वहां पर लगवाने के लिये अगर कुछ सहूलियत भी देते हैं तो उद्योग से केवल हमें हमारे यहां पर वह उद्योग लगा करके और कोई लाभ नहीं होता है और उत्पादन होता है, ऐसा ही नहीं है । आज इन्टर-स्टेट सैल्स-टैक्स १ पर्सेन्ट से भारत सरकार ने २ प्रतिशत किया ह, राजस्थान को उसका लाभ शायद ३० या ४० लाख रुपया मिलेगा । आज महाराष्ट्र और बंगाल को ५-६ करोड रुपया लाभ होगा । इसकी खास वजह क्या है ? वहां पर बडी-बडी औद्योगिक बस्तियां हैं और वडे-वडे औद्योगिक कारखाने वहां होने की वजह से उनके उत्पादन का जो एक्सपोर्ट होता है हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों दो तो स्वभाविक है कि उसका लाभ वहां पर प्राप्त होने लगता है ।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि जो कारखाना जहां होता है, जो कम्पनी जहां होती है उसके इनकम टैक्स का एक हिस्सा जिस प्रदेश के अन्दर वह कारखाना होता है उस राज्य की सरकार को मिला करता है। कुछ हिस्सा दूसरे प्रदेशों को उसमें से मिलता है। जिस प्रदेश का उद्योग होता है वहां का रॉ-मैटीरियल वगैरह भी वहां काम आता है, जो मजदूर काम करें या जो हमारे यहां से मजदूर कारखाने में काम करें या ट्रान्सपोर्ट में काम करें, जो रुपया उसके पीछे खर्च होगा वह सेल्स-टैक्स, एक्साइज-टैक्स व दूसरे टैक्सेज के जरिये वापिस इन्डाइरेक्टली रिटर्न होगा। क्या हम यह चाहते हैं कि भारतवर्ष में एक साथ ऐसी नीति नहीं अपनाई जा सके जहां कोई काम प्राइवेट सैक्टर में नहीं होगा। तब केवल राजस्थान अपनी दिक्कत सोच कर चलेगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने कहा पब्लिक सैक्टर में होने में एतराज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बढा सकें तो बढावें। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि जो प्राइवेट सैक्टर पर बडे बडे टैक्स हैं इनकम-टैक्स, सैल्स-टैक्स, भारत सरकार के टैक्स जो वडे वडे कारखानों पर लगाये जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में कई और टैक्स लगाये जा रहे हैं उनके मुकाबले में यदि हम यह सोचते हैं कि राजस्थान की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि जिन परिस्थितियों में हम ज्यादा से ज्यादा कदम उठा सकें, आगे कदम उठाना चाहिए तो हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन किसी देश या प्रदेश का अपने विकास के लिये शुरू में बहुत सी चीजों की दिक्कत उठानी पड़ेगी। अंततोगत्वा हम पिछड जायेंगे इस लिये देखना पडता है ।

दुर्भाग्य से हमारी भौगोलिक आधार पर स्थिति ऐसी है कि हम पोर्ट से काफी दूर हैं, रा-मैटीरियल से काफी दूर हैं। ऐसी बहुत सी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, तो उद्योग आसानी से लग सकता है। उद्योग वहां लग सकता है जहां रॉमैटीरियल मिलता है या कन्ज्यूमर्स मार्केट है तो स्वाभाविक रूप से उद्योग लग सकता है या तीसरी चीज इन्सेन्टिव हो तो अक्सर कर सकते हैं । हम सारे प्रश्नों पर विचार करके हमें परिणाम पर पहुंचना चाहिए जिससे सारी इकानोमी पर टोटल इफेक्ट पडता है। इमसे आगे बढने में निश्चित बात है, जितना इनवेस्टमेन्ट पब्लिक और प्राइवेट में दोनों को मिला कर, कोऑपरेटिव सेक्टर मिलाकर एक स्टेट र

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

होगा उतना ही जाकर असर पडने वाला है। हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत कम हम इन्डस्ट्रियल सैक्टर में इन्वेस्टमेन्ट कर पाये। तीसरी योजना में पिछले दो वर्षों में जो कार्यवाहियां हुई उनकी वजह से मैं समझता हूं कुछ विकास हमारे यहां पर पब्लिक सैक्टर में और प्राइवेट सैक्टर में दोनों को मिलाकर इन्वेस्टमेन्ट होगा। मैं समझता हूं राजस्थान के लिये आज इस बात की आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट करके अपनी इकानामी को ठीक कर सकें। हम स्वयं चाहते हैं कि एक मायने में ज्यादा से ज्यादा वजन आम आदमियों पर नहीं डालना पडे और हम सब के सब सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा गया है ओवर-ड्राफ्ट किया है, खर्चा ज्यादा किया होगा। लेकिन सबको मालूम है कि जो बडे बडे इरिगेशन वर्क्स हुए, बडे बडे काम हाथ में लिये गय उनमें से यदि आज भाखरा को लिया जाय तो भाखरा पर जितना आज इन्ट्रैस्ट और मेन्टी-नेन्स पर खर्चा करना पडता है, ६३-६४ के आकडे देखेंगे तो उससे स्पष्ट होगा इन्ट्रैस्ट को छोड दीजिये, मेन्टीनेन्स अकेला भी उससे वसूल नहीं हो सकता, आज हम इस दौर के अन्दर हैं इसका कारण है। इसका कारण यह है कि चाहे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट लें, चाहे इरिगेशन को लें कुछ वर्ष ऐसे निकलेंगे कि जब तक डवलपमेंन्ट पूरा नहीं हो जावे तब तक के इस पीरियड के बीच में ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा। इन खर्चों की वजह से या तो तय करें कि जहां इन्वेस्ट-मेन्ट होता है उसका तुरन्त रिटर्न मिलना चाहिये और यदि रिटर्न नहीं होता तो योजना साथ में नहीं लें। भाखरा और चम्बल का उदाहरण ६३-६४ का लें तो भाखरा पर इन्वेस्टमेन्ट १ करोड १३ लाख और चम्बल पर ८५ लाख २२ हजार और रिसीट साइड जो भाखरा से मिलेगी वह है १६ लाख ३ हजार और मेन्टेनेन्स पर खर्चा होगा भाखरा पर २८ लाख ६ हजार। मेन्टेनेन्स और रिसीट के बीच में भी १२ लाख रु. का फर्क है और इन्ट्रेस्ट १ करोड का एडीशनल है जो पे करना पडेगा इसी प्रकार चम्बल पर असर पडता है। लेकिन यह सब किस लिये? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लोन दिया है उसका इन्ट्रेस्ट नहीं दे सकते। पिछली बार ३० लाख रुपये वेज एंड मीन्स के लिये दिये थे उसको पे करने की पोजीशन में वे नहीं आये, इन्ट्रेस्ट पे करने की कपेसिटी नहीं हुई। नहीं हुई, इसलिये नहीं, कि पे नहीं करना चाहते, पर यह स्वाभाविक बात है कि ५-६ साल तक प्रोजेक्ट जम पाता है और जमने के बाद रिटर्न की केपेसिटी होती है तब दे सकते हैं। आम तौर पर उससे पहले नहीं दे सकते।

आज मद्रास और दूसरे स्टेट्स के बजट की स्टडी करें तो उसमें अपने खर्च के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डेप्रिसियेशन फंड से और दूसरे मेजर्स से करोडों रुपये प्लान एक्सपेन्डिचर के लिये मिल जाते हैं जब कि हमारे यहां सवाल यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अभी डवलप करना चाहते हैं। आगे चल कर सारी की सारी परिस्थिति यह हो सकती है कि पे कर सकें। इन परिस्थितियों के बीच हमको आगे चलना होगा।

भाखरा और राजस्थान नहर से आमदनी का सवाल खडा होता है। इसमें भी देख

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

कर चलना होगा । कुछ जमीन लैण्डलेस के लिये और दूसरों के लिये रखनी होगी । साथ ही साथ ग्रामदनी करें, ठीक मौके पर ग्रामदनी हो सके, इस बात का खयाल रख कर चलें तो सदन में कई बार सवाल खडा होता है, जैसे एक महानुभाव ने कहा कि हम किसानों को राजस्थान नहर जहां जाती है, वहां से उनको बेदखल करना चाहते हैं, पूंजीपतियों को लाकर बसाना चाहते हैं । यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि हाई कोर्ट का फैसला बाद में आया, राजस्थान नहर के बारे में मैं पिछले सदन में कह चुका था कि एक सीमा तक जो लोग वहां बसे हुए हैं उनको नहीं हटाना चाहते । ग्राज यू. पी. ग्रौर पंजाब में पता लगाया जाय तो वहां पर जो सरकारी कल्चरेबल वेस्ट लैण्ड होती है उसको कीमत पर दिया जाता है जब कि प्रोजेक्ट एरिया नहीं है दूसरी ग्रोर यहां हम उनको अलाट करके चलते हैं ।

कहा जाता है कि जागीर एबोलिशन हुग्रा, किसी जगह तीस साल में कम्पेन्सेशन पूरा करने का तय किया गया ग्रौर किसी जगह ४० साल का तय हुग्रा, ग्रलग ग्रलग लोंग–टर्म तय हुई । हमने राजस्थान में प्रयत्न किया, यह बहुत बडा सवाल था । स्वर्गीय श्री गोबिन्दबल्लभजी पंथ को बीच में डाला, उन्होंने एवार्ड दिया । बाद में हमारे प्रधान मंत्रीजी ने एवार्ड दिया । ग्राज इस बात पर गौर किया जाय कि राजस्थान जैसी जगह में जो खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे की वजह से वजन ग्राकर पडता है । ग्राज २० करोड रुपये जागीर कम्पन्सेशन ग्रौर दूसरा रिहैबिली-टेशन कम्पन्सेशन में देते हैं ।

माननीय सदस्य कहते हैं कि जो बोंड दिये हैं उनको ग्रागे बढा दिया जाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जो बात स्वीकार की गई, जो निर्णय लिया गया हम को उसे उसी प्रकार से निपटाना है, उसी फैसले पर चलना है । ग्रब जागीर बोंड्स दे दिये गये, कई हाथों से ट्रांसफर कर दिये गये, कइयों ने मार्केट में बेच दिये, ऐसी हालत में यह हम कानून की दृष्टि से भी नहीं कर सकते । स्वेच्छा से मिलकर फैसला करने की बात हो तो ग्रलग बात होगी । लेकिन ग्राज यह सदन कह दे कि जो जागीर बोंड्स दिये हैं उनके इंस्टालमैन्ट्स, ३० साल के कर दिये जायं–मैं नहीं जानता, कानूनी पंडित कह सकते हैं कि इस प्रकार का फैसला हो सकता है क्या ? मेरे खयाल से जब कि बोंड्स इश्यू हो चुके हैं, इस प्रकार का फैसला नहीं कर सकते । लेकिन इस प्रश्न को छोडकर यह देखने की बात ग्राती है कि जो निर्णय लिया गया उसको निभाने की बात ग्राती है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो खर्चा किया जाता है वह एक प्रकार का इन्वेस्टमैन्ट है । ग्राज सारा का सारा खर्चा वजन के रूप में मालूम पडता है, लेकिन न यह कल्पना की जाय कि १९७७-७८ में या १९७८–७९ में जाकर कम्पेन्सेशन कम्पलीटली व्हाइप–ग्राउट हो जायगा, उससे दो साल पहले ग्राधा हो जायगा १९७६-७७ में । तो इससे एसेट्स बिल्ड हो रहे हैं लेकिन एसेट्स के लिये ग्राज सरकार को वजन उठाना पड रहा है ।

ग्राज तो उन सब चीजों को देखना पडेगा । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, यह सरकार किसानों का ध्यान रखने वाली सरकार नहीं है । माननीय उपाध्यक्षजी, यू. पी. के ग्रन्दर

( श्री मोहनलाल सुखाडिया )

लैंड रिफार्म्स किये गये, तो यू. पी. के अन्दर भूमदारी का हक देने के लिये किसानों से मल्टीपल चार्ज किया गया तब खातेदारी के हक दिये गये। माननीय उपाध्यक्षजी, सौराष्ट्र के अन्दर जो जागीरदारों को कम्पेंसेशन दिलवाया गया है उसको किसानों से मल्टीपल वसूल करके किया गया है। आज एक तारीख के दिन सारे राजस्थान में जो किसान जमीन पर काबिज हैं उन्हें बिना प्रकार का कम्पेंसेशन लिये हुए खातेदार घोषित किया गया है। आज कोई वजन लगाने की बात कही जाती है, कोशिश इस बात को कह देने की की गई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई यह समझ कर न चले कि हम यहां बैठ गये हैं इसलिये किसानों का हित समाप्त हो गया और दूसरी जगह जो बैठे हुए हैं उनके सामने किसानों का हित रह गया है। सिर्फ इसी वजह से यहां पर लैंड रेवेन्यू के मामले में यह प्रस्ताव रखा गया है, इतनी इसके अन्दर बढौतरी की गई है, इसलिये सारे के सारे किसानों के बारे में दृष्टिकोण नहीं है, ध्यान नहीं है। हर प्रकार यह रखा गया। मैं, उपाध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सदन के अन्दर इस बात की चर्चा की गई, जैसा मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने कहा कि तीन करोड से बढा कर हमने लैंड रेवेन्यू को ८ करोड रुपये तक पहुंचा दिया है। मैं समझता हूं, मैंने इसको पहले भी स्पष्ट किया था कि लैंड रेवेन्यू तीन करोड से आठ करोड बढाने की बात नहीं है क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू तीन करोड का था वह खालसा एरिया का था और जो चार करोड का एडीशनल हो रहा है, वह जागीर एरिया का हो रहा है। इस वजह से उसमें बढा इसके है। अन्दर, लगान जो कुछ था, उसमें बढौतरी की वजह से हुआ है, यह प्रश्न उसमें नहीं आता है।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष जी, हम इस बात पर विचार करें कि राजस्थान बना और राजस्थान आज है, उसके बीच में हमारे यहां पर राजस्थान की बडी इनकम तीन चीजों की थी: लैंड-रेवेन्यू, सेल्स-टैक्स और एक्साइज। ये तीनों हमारे मेजर हैड्स थे, जिनके अन्दर हमारी इनकम होती है। लैंड रेवेन्यू की इनकम के अन्दर अगर कुछ हुआ पिछले वर्ष के अन्दर तो लैंड रेवेन्यू के अन्दर यह हुआ कि बहुत से लोग-बाग, बेगार, कई तरह की चीजें थीं, वे समाप्त होकर एक जगह सैटल करके एक चीज तय की गई। मैं समझता हूं दस-पन्द्रह साल पहले वजन था, उसको बढाने की बात नहीं की गई। दूसरे, उपाध्यक्ष जी, इस चीज को और ले लें, सेल्स-टैक्स के बारे में पिछले वर्ष तक आमदमी ६ करोड ८० लाख की कुल राजस्थान के अन्दर रही। जिस वक्त कस्टम ड्यूटी राजस्थान में थी और जब सैल्स-टैक्स लागू हुआ, तो ४ करोड बीस लाख कस्टम ड्यूटी थी, आगे और कुछ नहीं था। जिसकी वजह से आज मार्केट में प्राइसेज हैं, व जो ट्रैन्ड चल रहा था उस टैक्स के इन्सीडैन्ट के लेवल को रखा जाता तो ६ करोड ८० लाख के बजाय ९ करोड, की आमदनी रहती। उसके मुकाबले, जो उस समय वजन था, किसानो पर, दूसरों पर वह बजन कम हुआ है यह हमारे यहां कस्टम होने की वजह से पिछली आमदनी के कम्पेरिजन में आसानी से समझा जा सकता है।

उपाध्यक्षजी, दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस लक्ष्य को देख कर

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

चले कि आज एग्रीकल्चर में, जो पहले की कन्डीशन्स थीं और आज की कन्डीशन्स हैं, पहलेकीकन्डीशन्स जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूं सिर्फ किसानों के पास से लगान लेना था, इसके सिवाय कोई दूसरा काम नहीं करते थे। आज जितना लगान लेते हैं उसके मुकाबले में, जहां पहले कुछ नहीं दिया जाता था, कोआप-रेटिव सोसाइटीज, पंचायत समिति के जरिये, जो फैसेलिटी मार्केट के अन्दर हम दे रहे हैं, उस पर विचार किया जाय कि इस सबका इम्पैक्ट क्या हुआ है ? आज जो किसानों के लिए पहले कन्डीशन्स थी, उसके अन्दर थोड़े दूसरे काम-काज चलते हैं। और चलते हैं उन सब चीजों का इकानोमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है ? मैं यह नहीं कहता कि किसान मालदार हो गये हैं, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे किसान खातेदार हो गये हैं। मैं नहीं कहता, लेकिन साथ साथ जो दूसरी बातें कही जाती हैं कि बिल्कुल गजब हो रहा है, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से जब हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास आगे बढ़ कर चले, इन परिस्थितियों के अन्दर, मैं आज का नहीं कहता, कम से कम दस-पन्द्रह साल तक उसका वजन उठा कर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये तैयार करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज चीन को लीजिये, रूस को लीजिये जब उनके वहां पर नई गवर्नमेन्ट कायम हुई, तो नई गवर्नमेन्ट कायम होने के बाद हमारे यहां तो टैक्स का यहां फैसला करके एक तरह करने का प्रश्न आता है लेकिन वहां पर हर एक व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवा कर, यहां पर यह नहीं लगवाया गया कि सबको काम करना पड़ेगा, तब जाकर देश का विकास हो सकता है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर हम जबरदस्ती और इस प्रकार काम करवाने में विश्वास नहीं रखते। आज मैं इस बात को निश्चित तौर पर जानता हूं, जो साम्यवादी पार्टी की तरफ से बराबर किसानों की आवाज उठाई जाती है, तो अन्ततोगत्वा जब उनका प्रश्न आता है, तो सारे किसान, चाहे जमीन के मालिक होकर विकास करते हैं, सहकारिता से विकास करते हैं, वे जाकर मजदूर बन जाते हैं। उससे क्या ज्यादा मिल जाता है ? उनमें असंतोष पैदा करके, अपनी परिस्थिति को दिखा कर गुमराह करके आखिर में जाकर उनको मजदूर बनाना चाहते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : गलत समझ रहे हैं आप।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : हम इस लक्ष्य को लेकर चलना चाहते हैं, यह मुश्किल काम है। मुश्किल है, क्योंकि वे डिमोरेलाइज करके सारी चीजें चला सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ हम जो करना चाहते हैं उसमें एक एक किसान को समझाने की बात आती है, उत्पादन के लिए समझाने की बात है, सहयोग की बात आती है। हम यह याद रख कर चलें कि जब किसान की आमदनी का विचार करके चलते हैं तो जमीन की बात पर विचार करके न चलें, तो ठीक नहीं होगा। हमें पशु-पालन और जमीन, दोनों चीजों को साथ जोड कर किसान की इकानामी को देखना होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हमें विचार करके आगे बढना होगा। मैं समझता हूं कि कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है, कम जमीन वाले किसान के पास पशु भी नहीं होंगे। तो उसके लिए

( श्री मोहनलाल सुखाडिया )

मुश्किल है और उसके सामने दिक्कतें आती हैं। मैं समझता हूं कि जब हमारे वित्त मंत्री इसके बारे में जवाब देंगे तो उन लोगों, जिनकी होल्डिंग बहुत छोटी है, को रिलीफ दिया जाय, यह बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है, जहां और लोगों को वजन न पडे, तो साथ ही साथ किसान पर वजन न पडे, इस सिद्धान्त को मान कर चलना, मैं समझता हूं, इसमें समाजवाद की बात आती है न कि और बात आती है। इतना जरूर मान कर चलना चाहिए कि सबको वजन उठाने की स्थिति आज देश के सामने है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लैण्ड रेवेन्यू के ऊपर सेस लगेगा, अगर एमर्जेन्सी हट जाय, तो उसके हटने के बाद, जो कन्शेसन्स वित्त मंत्री जी अनाउन्स करें, एमर्जेन्सी हटने के बाद जो कन्सेशन सरकार देगी उससे वजन कम हो जायगा, यह सोचने के लिए हम तैयार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार ऐसी स्थिति बना कर चलें जिसकी वजह से लोगों के दिमागों पर ऐसा असर हो, जिसके मायने बिल्कुल नहीं निकलें और मामूली रास्ता न निकल सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमको एक बात दिमाग में स्पष्ट करके चलना है।

इस सदन के अन्दर यह प्रश्न आया कि हम किराये पर टैक्स लगा दें, जो मकान बना कर दूसरों को किराये पर देते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगायें। मुझे एतराज नहीं है, और चीजों पर टैक्स लगायें। मैं सारे प्रश्न एक दृष्टि से देखना चाहता हूं कि जो हमारे यहां पर आर्थिक विकास के लिए, इन्वेस्टमेन्ट के लिए, जो एम्प्लॉयमेन्ट जेनरेट होती है वह बन्द न हो जाय। वह एम्प्लायमेन्ट जेनरेट होती रहे और उसके होते रहते हुए जो टैक्स किसी पर डालना चाहते हैं बडे आदमियों पर, तो ज्यादा से ज्यादा डाल दीजिये, मुझे एतराज नहीं है, और कहीं डाल दीजिये, लेकिन राजस्थान में इन्वेस्टमेन्ट के बजाय यहां कहीं डाइवर्शन हो जाय और राजस्थान के अन्दर इकॉनमिक एडवान्टेज हो सकते हैं, वह बन्द हो जायें। इस बात का हमें पूरे तौर पर विचार करके चलना होगा। भले ही उसको हम तात्कालिक स्लोगन बना सकते हैं लेकिन लोंग-रन में वह डिस्एडवान्टेजियस हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, हम इस सदन में जल्दी से जल्दी मनी-लैंडर्स बिल लाना चाहते हैं, उस मौके पर मनी-लैंडिंग के बारे में जो कुछ विचार किये जायं, उसको पूर्ण रूप देने के लिए इस सदन को अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ निवेदन कर दूं कि सीलिंग के बारे में इस सदन में कई बार प्रश्न उठाये जाते हैं कि इस सरकार ने सीलिंग के कानून को तो पास कर दिया लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं करना चाहती है। तो मैं आपकी आज्ञा से, उपाध्यक्षजी, सीलिंग के बारे में जो हम जांच-पडताल कर रहे थे और उसको इम्प्लीमेन्ट करने के लिए जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय किये हैं, उसकी पुस्तिका इस सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रति कृपया विधान सभा के टेबल-आफिस में देखें)

जिसको देख कर हम एक रोज इस सदन के अन्दर उस पर विचार करें। हम चाहते हैं कि सदन के सदस्यों के विचार इस पर मालूम हो सकें और यह फॉर रीचिंग तरीके का यह कार्यक्रम होने वाला है, उसके

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

बारे में जो आपकी राय है, उसकी जानकारी हो जाय, जिससे इम्प्लीमेन्ट करने के अन्दर आसानी हो। तो माननीय सदस्य जब जायं तो उसकी कापी ले सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। सीलिंग के कानून को इम्प्लीमेन्ट नहीं करना या और कुछ करना यह हमारे दिमाग के अन्दर कभी बात आई नहीं है। हमारे यहां पर जितनी जल्दी हो सके, उस पर अमल करने ....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : ( Give us a fixed date ) डेट फिक्स तो कर दीजिये।

लेटेस्ट कौनसी डेट तक आप इसको लागू करेंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : हमारे यहां हाउस में डिस्कशन हो जावे उसके बाद हम जल्दी लागू करेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : लेटेस्ट डेट तो आप बता दें।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : यहां पर सदन में डिस्कशन होने के बाद हम जल्दी ही उसको इम्पलीमेंट करेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : Every year we hear the same thing

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं यह निवेदन कर दूं कि पिछले साल यह कहा था कि सीलिंग के लिए आपने यह तय किया था कि १० मन पैदावार प्रति एकड में शुमार किया जावेगा इसलिए इसके डिटेल्स वर्क आउट कर रहे हैं। डिटेल्स प्रस्तुत होने पर क्या पोजिशन होती है, वह रख रहे हैं। आप लोगों ने एरिया पास नहीं किया था वरना कभी इम्पलीमेंट हो जाता। इस सदन में यह कहा गया कि १० मन पैदावार वाले को एकड माना जावे। उसकी वजह से समय लगेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या एक जून से पहले आप लागू कर देंगे ?

**श्री एक माननीय सदस्य** : घबराते क्यों है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस तरफ बैठने वालों को घबराने की कोई बात नहीं आती। आप घबराने की बात कह कर चिन्ता न करें। कानून भी इसी तरफ वाले लाये थे और उसे इम्पलीमेंट भी इसी तरफ बैठने वाले करेंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : यह कितने सालों से रेंग रहा है ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : Point of Order, Sir.

**एक माननीय सदस्य** : आप बीच में बोल रहे हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराना** : पोइण्ट ऑफ आर्डर तो बीच में ही रेज होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्री ने जो यह रेफरेंस दिया कि यह कानून इस तरफ वाले लाये हैं इसी तरफ वाले पास करेंगे...

**एक माननीय सदस्य** : पास नहीं करेंगे, इम्पलीमेंट करेंगे।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : मैं इन रिमार्क्स को आपत्तिजनक समझता हूं क्योंकि यहां

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
पर जितने कानून पास होते हैं वे सदन के द्वारा पास किये जाते हैं और दोनों तरफ से पास किये जाते है । यह सरकार कांग्रेस की सरकार हो सकती है, मगर कानून दोनों पक्ष की तरफ से पास होते हैं । इसलिए सदन में जो इस प्रकार के रिमार्क्स चीफ मिनिस्टर ने दिये हैं वे इस सदन के सदस्यों और सदन की डिग्निटी को कम करने वाले हैं और इससे सदन की डिग्निटी कम होती है ।

**श्री दलपतसिंह** (आबू) : आपने वकालत की है ।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसके फेल होने के लांच्छन हम पर लगाये जा सकते हैं तो इसे इम्पलीमेंट करने का श्रेय भी तो हम पर ही होना चाहिए । और इसलिए मैं यह कह रहा था ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि पर-केपिटा इन्कम इतनी बढ गई है, परन्तु इन्कम इन्डेक्स इतना बढ गया है । यह देखा जावे तो यह रिजल्ट २४६ नहीं बैठेगा । इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जब Constant prices पर वर्क आउट करते हैं तो ५४-५५ में जो इन्डेक्स नम्बर था वह चेन्ज नहीं होता है और जो इन्क्रीज है वह उसके साथ को-रिलेट हो जाती है, इसलिये बढी हुई आज की प्राइस को लेते तो ३५० आती और आज का कोई इन्डेक्स नम्बर लें और पर केपिटा पर लें, यह कन्सीडरेशन है । इस आधार पर ले सकते हैं । इसके कारण यह कान्ट्रेरी हुआ है

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि पर-केपिटा में ज्यादा इन्क्रीज हुआ है, इस पर ज्यादा वजन डालें । मैं समझताहू कि यह सबके ध्यान में है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में मध्यप्रदेश या उडीसा में जैसे स्टील का कारखाना लग गया, इस प्रकार की परिस्थिति यहां उत्पन्न नहीं हुई है । हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां भी कारखाने हों और हमारे यहां भी पर-केपिटा इन्कम बढे, मगर यहां पर ज्यादा इन्डस्ट्रीज में उन्नति नहीं हुई है इसलिये इन्डस्ट्रिज इनकम में बहुत ज्यादा तादाद में फर्क पड गया हो, ऐसा मानने में नहीं आता ।

साथ में यह भी कहा गया कि हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में बजट स्टडी में ४-५ कॉमोडिटीज के फिगर्स ही दिये गये हैं । सीमेन्ट के बारे में कहा गया है, उसके संबंध में मैं अर्ज करूं कि सीमेन्ट की पोर्जीशन ठीक है । एक महीना जयपुर उद्योग में स्ट्राइक रहने से उसके प्रॉडक्शन में कोई अन्तर आया हो ऐसी बात नहीं है ।

इसी प्रकार यार्न में पहले के मुताबिक १९६० में ३११ लाख था, वह बढ कर ३६६ लाख दर्ज हुआ ।

बॉल बियरिंग में पहले १९६० में १ लाख ३५ हजार था वहां २ लाख हुआ । इसी प्रकार बिजली के मीटरों में १ लाख ३.. हजार होते थे वे २ लाख ४८ हजार हो गये । नमक पहले २ लाख ८० हजार टन था वह आज ३ लाख ६० हजार टन हो गया । इसी प्रकार मिनरल्स में पहले के मुकाबले में पैदा बढी है । घटने की बात नहीं आती ।

( श्री मोहनलाल सुखाडिया )
लेकिन मेरा मतलब यह कहने का था कि किसी एक चीज में करोड़ों रुपयों की पैदावार होने से पर-केपिटा पर असर पड़ा . . .

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : Point of order, Sir. मैं आपसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सवाई माधोपुर के आंकडे यहां बताये गये हैं वे सही नहीं। जो सरकारी आंकड़ों के द्वारा बताया गया है वह वास्तव में कम है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मुझे पता नहीं अगर कोई एसी बात आ गई तो चैक अप कर सकते हैं।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात पर भी काफी वाद-विवाद हुआ कि राजस्थान केनाल में हमने पंजाब के पहले भी गवर्नर साहब का भाषण था उस मौके पर भी एक दो माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि राजस्थान नहर एरिया में पंजाव के जो फौजी हैं उन लोगों को हम अपने यहां पर जमीनें क्यों दें और हमारे यहां जमीन का इसी की वजह से नुकसान होगा और हमने उनको जमीनें देने का निर्णय उचित नहीं किया।

**श्री भैरोंसिंह व श्री रामानन्द अग्रवाल** : किसने कहा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आपके पीछे बैठे हुए माननीय सदस्य ने कहा।

**श्री भैरोंसिंह** :किसी ने नहीं कहा।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** :एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा था कि उस जमीन को बेचा जाय तो इतने करोड रुपये होंगे।

**श्री भैरोंसिह** : कौन थे ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : नाम तो इस समय याद नहीं।

तो देश में एक परिस्थिति पैदा हुई, उसके पैदा होने के बाद हमने यह फैसला किया कि पंजाब से लाखों व्यक्ति हमारे देश की सुरक्षा के लिये लड रहे हैं।

**राजा श्री मानसिंह** (डीग) : You mean to say, more than those from Rajasthan.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : Yes from Rajasthan

**श्री मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री) : Certainly.

**राजा श्री मानसिंह** : It is not a fact.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : That is quite true. यह तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान से अधिक हैं और यह भी है कि उनके यहां से हमारे यहां नहरें आयेंगी, पोंग डेम वहीं बनेगा, पर जमीन उनके पास नहीं। राष्ट्र पर इस तरह की परिस्थिति है तो राजस्थान और पंजाव दोनों पडौसी देश इकोनोमिक डेवलपमेन्ट में साथ साथ मिल कर काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में साथ मिल कर काम कर रहे हैं, तो जिनका इतना निकट का सम्बन्ध है वहां राजस्थान ने इस तरह का कदम उठाया है तो अधिकांश सदस्यों की तरफ से समर्थन हुआ है। जिनकी तरफ से नहीं

# Page No.84



(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

हुआ उनसे कहूंगा कि जो कुछ हमने किया है राष्ट्र के हित की दृष्टि से किया है । इस कदम के उठाने के लिये हमारे दिलों में किसी तरह की संकोच की भावना नहीं होनी चाहिये । इसके सिवा और मैं कुछ कहूं इसकी आवश्यकता नहीं ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में और चर्चाओं के साथ यह सवाल आया कि हमने कुछ जगह, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा में एक गांव में, नाम मैं इस समय भूल गया, जब वहां पंचायत नहीं रही तो कर्मचारियों का पट्टा अफसरों से, यू. आई. बी. के और दूसरे अफसरों से मिल कर किया और एक फैसले के एक्सट्रैक्ट्स सुनाये । मैं पूरी जानकारी में नहीं हूं, मैं जो जानकारी कर पाया हूं उससे पता चलता है कि जो कुछ हुआ है निश्चित रूप से ठीक नहीं हुआ है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी, किसी तरह की रियायत करने का सवाल नहीं ।

नीम-के-थाने के बारे में कहा गया । नीम-के थाने से मेरे पास आज ही कुछ देर पहले रिपोर्ट आई है । उससे पता चलता है कि माननीय सदस्य यहां जो प्रश्न उठाते हैं उसमें तथ्य है, छिपाने की बात नहीं जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और पांच-सात दिन में ही पहला कदम ले लिया जायगा ।

एक हाथियों के बारे में सवाल उठाया गया, आमेर में जाने के बारे में और कहा गया कि किसी एजेन्सी को यह सारा का सारा क्यों दे दिया ? मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे कारण है । जो टूरिस्ट्स बाहर से आते हैं, वहां कई लोग खड़े होकर छीना-झपटी करें, वह कहे इतने रुपयों में ले जाता हूं, दूसरा कहे इतने रुपयों में ले जाता हूं । तो यह न हाथी वालों के लिये ठीक रहेगा, न टूरिस्ट्स के लिये और न यहां के लिये ही इसलिये भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा नहीं ट्रेवल एजेन्ट्स हैं उनके द्वारा जिस एजेन्सी को एक्स्कर्शन के लिय रिकोग्नाइज किया है उस एजेन्सी को यह सौंपा गया है; इसके अलावा और नहीं है । और कोई एजेन्सी ट्रेवल एजन्ट द्वारा रिकाग्नाइज हो कर कार्य करना चाहे तो कर सकती है । आमेर से आने वाले प्रतिनिधि स्वयं हाथी पर बैठ कर जाना चाहें तो जा सकते हैं उन्हें कोई नहीं रोकेगा । जो रोक दिया तो रोकने वाले की गलती कि क्यों की टूरिस्ट्स के लिये यह है, कोई स्वयं शौक के लिये जाना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of clarification, Sir,) टूरिस्ट्स के लिये यह कौनसे कानून के तहत रोक लगाई है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : It is simply a regulation.

मैंने जैसा कि निवेदन किया देखने में अच्छा नहीं लगता । टूरिस्ट्स बाहर से आयें और एक दूसरे से हाथी वाले छीना झपटी करें । हाथी वालों को भी अच्छी कीमत मिले, टूरिस्ट्स आयें उनको भी ये सुविधा मिले इसलिये इसे इस प्रकार रेगुलेट किया गया है । दूसरों को इसके लिये उत्सुकता हो तो उनको भी मौका होना चाहिये

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
एक्स्कर्शन एजेन्ट होना चाहें तो वे बन सकते हैं ।

**श्री मानसिंह महार** :यह इतना आसानी से साइड ट्रैक करने का सवाल नहीं है, लाखों की आमदनी का सवाल है । तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसे इसलिये रेगूलेट किया है तो जो १०) रुपया वे लेते हैं फी हाथी वह दस रुपया सरकार अपनी जेब में रख ले तो हम मानलें कि सरकार को फायदा हुआ और किसी व्यक्ति विशेष को १०० रुपया रोज और इस हिसाब से ३ हजार रुपया महीने का पहुंचाना यह मोनोपोली है । यह कहा जायगा कि सब उनको नहीं मिलता, आधा हिस्सा एजेन्ट्स को जाता है । पर अगर इस मोनो-पोली से पर्टीक्यूलर आदमी को फायदा होता है तो यह कांस्टीट्यूशन के भी खिलाफ है ।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : मैं निवदन कर दूं, मैंने और भी जानकारी की है, तो साल भर में २५०० ट्रिप्स हुए तो तीन हजार रुपये माहवार आमदनी का कहा, यह नहीं, इन ट्रिप्स से पता चल सकता है कि कुल कितनी आमदनी होती है । फिर इन्तजाम करना, इस सारे खर्च को साल भर में इसी से मीट किया जाता है ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्वेश्चन यह नहीं है । क्वेश्चन यह है कि बिना कानून बनाये किसी भी फ्री ट्रेड को कन्ट्रोल कर सकते हैं कि नहीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : कानून से कितना कर सकते हैं या नहीं, यह सवाल नहीं है, इसको आमेर में रेगुलेट किया गया है ।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं । सरकार २ रुपये ही क्यों लेती है, १२ ही क्यों नहीं ले लेती ?

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : On a point of clarification, Sir, यह हाथी कोई सदस्य भी लगा सकत हैं कि नहीं? मोनोपोली तो तभी है जब कोई सदस्य खरीद कर लायेंगे और उन्हें नहीं लगाने दिया जाय ।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया है ।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने विचार नहीं किया और माननीय सदस्य हाथी खरीद रहे हैं ।

**श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** : मैं तो आप दोनों की चिन्ता देख रहा हूं कि हाथी खरीदने का विचार कर रहे हैं ।

**श्री मानसिंह महार** : हमारे तो चले गये, घबराइये मत ।

**श्री मथुरादास माथुर** (गृहमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन का समय १५ मिनट बढा दिया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट बढा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय १५ मिनट बढाया गया ।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक कम्पनी है उससे प्रोजेक्ट

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

रिपोर्ट तैयार करवाई, सोडा एश का काम सौंप दिया है। मैं यह निवदन करूं कि यह एक रिनाउन्ड कम्पनी है इन्होंने इन्डिया में कई जगह प्राजेक्ट रिपोर्टस तैयार की हैं। यदि एक्सपर्टस से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाते हैं तो किसी की रिश्तदारी किसी से जोड दी जाती है।

टोंक के पेमेन्ट के बारे में मैं पूरे डिटल्स मालूम नहीं कर पाया हूं, पर जो जानकारी मुझे मिली है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहले नवाब थे उनको कर्ज दिया गया, स्टेट ने गारन्टी दी थी। कुछ डिस्प्यूट चलता रहा और लिमिटेशन के पीरियड में कोर्ट में दावा नहीं किया, इसलिये यह राय दी जा सकती थी कि सामने वाले ने लिमिटेशन के पीरियड में दावा नहीं किया। इसलिये गवर्नमेन्ट ने सोचा कि यह प्ली लेना उचित नहीं, स्टट गवर्नमेन्ट का दावा है तो न देना उचित नहीं होगा और वह दिया जाना चाहिये। यह पोइन्ट इन्वोल्व्ड है और कोई दूसरा प्रश्न जैसा कि रखा गया वह नहीं है। और फरदर डिटेल्स की आवश्यकता होगी तो रेवन्यू की या दूसरी बहस होगी तब तक फाइल मंगा कर जवाब दे सकूंगा। कई बार इस बारे में चर्चा हुई है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार, जयपुर) : इस दृष्टि से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछूंगा कि क्या लिमिटेशन्स के सम्बन्ध में सरकार की यही पॉलिसी है? नहीं? सरकार की लिमिटेशन्स के सम्बन्ध में एक युनिफार्म पोलिसी होनी चाहिये। सरकार के खिलाफ बहुत से दावे चलते हैं गंगानगर में कुछ में लिमिटेशन की प्ली स्टेट ऑफ नहीं की। तो इस सम्बन्ध में सरकार निश्चित् नीति निर्धारित करे। मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से घोषणा करें सब में लिमिटेशन प्ली स्टेट ऑफ करें।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : इसके बारे में सारे इन्डिविजुअल केसेज में जाये बिना मैं कह नहीं सकता कि किस चीज में क्या चीज इन्वोल्व्ड है। यह मैं उनको देख कर ही कह सकता हूं। जनरली कह दूं कि लिमिटेशन के बारे में यही हो तो यह उचित नहीं होगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : Other things being equal. वह बाएबल हो तो आप इनकार नहीं करेंगे। At least that basis, you should commit.

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : सिमिलर केस सामने हो तो कह सकता हूं। केवल लिमिटेशन की plea लेकर अदरवाइज सब तरह से वह भी प्रूफ हो, मोरल ओब्लीगेशन हो क्योंकि लिमिटेशन का टाइम हो गया है इसलिये यह ले लें; Decision can be taken on individual cases.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इधर उधर ...

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : पॉलिसी के अलावा दो बातें आती हैं। एक तो सामने वाला गवर्नमेन्ट के ऊपर दावा करे और गवर्नमेन्ट के केस में ड्यू होता है और आपकी मंशा यह चल रही है कि कोई चीज पे नहीं करे और एडवान्टेज की बात हो तो वह प्रश्न नहीं आता है इसमें।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस चीज को भी उठाया गया कि प्राइमरी स्कूलस् न खोलें और कुछ चीजें न करें,

(श्री सोहनलाल सुखाडिया)

यह ज्यादा अच्छा होगा । २५० प्राईमरी स्कूल्स खोलने की भी बात कही गई है । ज्यादा प्राईमरी स्कूल्स, बोर्डर एरियाज हैं हमारे उनमें दूर दूर जगह पर प्राईमरी स्कूल्स नहीं हैं, हम वैसे तो एडीशनल टीचर्स का ही प्रोविजन रखना चाहते थे किन्तु जैसे कि हमारे बोर्डर्स की स्थिति है वहां दूर दूर तक बोर्डर एरिया के कोई प्राईमरी स्कूल न होने से उस दृष्टि कोण से इसके लिए व्यवस्था की गई है ।

एयर सर्विसेज के सम्बन्ध में, माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इसकी शुरुआत इसलिये की गई कि टूरिस्ट ट्राफिक ज्यादा बढे, राजस्थान का विशेष तौर से सम्बन्ध रहे उनका, उनको सुविधा मिले । हमने यह शुरू किया । जब दो वर्ष तक इससे हमको घाटा हुआ तो राजस्थान गवर्नमेन्ट ने और मैंने स्वयं ने दिल्ली के अन्दर जो इससे सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं उनसे बात करके हम इस बात का फैसला कर चुके थे कि हम इसके लिए सबसिडी नहीं देना चाहते, इसको भारत सरकार चलाना चाहे तो चलायें । पायोनियरिंग की दृष्टि से हमने यह कर दिया कि ट्रेड चले । मिनिस्टर तो एक-दो बार गये होंगे, आये होंगे, टूरिस्ट महत्व की चीज है और राजस्थान भारतवर्ष में महत्व रखता है । यह आगे बढे और भारत वर्ष और राजस्थान दोनों को ही अधिक इससे लाभ मिले । इसमें इन्वेस्टमेन्ट के बगैर यह ट्रेड डवलप होना मुश्किल हो जाता है । इसलिये इसके अन्दर इन्वेस्टमेन्ट करके गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया इसको चालू रखे इसकी व्यवस्था की गई है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बजट में क्यों प्रोवाइड किया ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : काफी समय हो गया, इसलिये ज्यादा वाद-विवाद में न पड़ कर अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ओवर ड्राफ्ट का प्रश्न आता है । मैंने जनरल भूमिका के रूप में निवेदन किया कि जो खर्चा हुआ है आउट साइड प्लान तो उसके अन्दर भी डेवलपमेन्ट की ही बातें हैं । वैसे ही खर्च किया हो यह नहीं है । हम खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होकर चलें । उसको रेस्ट्रिक्ट किया जावेगा, जितना ज्यादा हो सकता है । जो लोन या कर्जा हमारे ऊपर है उसको दूसरे पक्ष पर भी घटा कर देखना होगा । या तो यह होता कि पिछले पांच-सात वर्ष में जो ओवर ड्राफ्ट हुआ वह नहीं करते और डेवलपमेन्ट के कामों को रोक कर वह खर्चा नहीं करते । दूसरा यह होता कि पब्लिक लोन रेज करते या स्माल सेविंग्स से उन चीजों को पूरा करते । जहां तक खर्चे का सवाल है कुछ चीजों की आमदनी न होने से डेफिसिट हुआ है । आगे नहीं बढे हैं, ऐसी बात नहीं है । लोन नहीं आया इस कारण भी कुछ डेफिसिट बढ़ा है, सेल वगैरह नहीं हुआ । रोड्स के अन्दर, वाटर वर्क्स के अन्दर ज्यादा खर्चा हुआ । बिल्डिंग्ज के ऊपर खर्चा हुआ । प्लान में हो या गवर्नमेन्ट की बिल्डिंग्ज जो नॉन-प्लान में हों वे आती हैं, इस कारण बढा । आज जो लोन है इसके अन्दर जो इन्ट्रेस्ट पे करना पडता है, पब्लिक लोन फ्लोट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा इन्ट्रेस्ट पे करना पड़ता तो ज्यादा वजन हमने ले लिया है । पहले हम लेते तो लोन लेना पडता । इन्ट्रेस्ट

( श्री मोहनलाल सुखाडिया )

उतना ही देना पड़ता, अधिक हो ऐसी बात नहीं। या तो हम लेते ही नहीं। हम खुद चाहते हैं कि अब इस ओर आगे न बढ़ कर जितना री पे कर सकते हैं, करें।

यह कहा गया कि वित्त मंत्री ने ६ करोड़ का वायदा किया इसमें ३.४० करोड़ बताया और बाकी का टैक्स लगा कर पूरा करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि जो इसमें बताया गया है उसी माफिक पूर्ति करना चाहते हैं। उपाध्यक्षजी, हम तो भाखड़ा, चम्बल और जो बड़े बड़े बांध किये गए हैं उनको केपिटलाइज करके, जबकि भारत सरकार द्वारा, दूसरी बातें की जा रही हैं, आगे से चालू करना चाहते थे जिससे आगे जाकर रिटर्न अधिक हो और यह प्रश्न बराबर हमने भारत सरकार के सामने रखा। हमने बार बार जोर देकर कहा। किन्तु उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। इस कारण से भी यह वजन कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ वजन बढ़ रहा है और जो कुछ किया जा रहा है आगे जाकर राजस्थान की प्रोस्पेरिटी के लिहाज से किया जा रहा है। इन सारे प्रश्नों को सदन ध्यान में रखेगा। अपने साधनों को बढ़ाने के लिए राजस्थान के अन्दर वजन डालने की बात आयी। इस संबंध में कई बातें कही गई। माननीय उपाध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस चीज को न चाहते हों और इधर बैठने वाले माननीय सदस्य चाहते हों जब टैक्स का भार डालने की बात हो, ऐसा नहीं है; किन्तु यदि आम लोगों पर उसका असर पडता हो तो कोई भी पसन्द नहीं करेगा। हम भी पसन्द नहीं करेंगे। एक ही प्रश्न रहता है कि क्या इस दृष्टिकोण को लेकर आज राजस्थान के इकानामिक डेवलपमेन्ट को रोका जाय और उसका परिणाम यही हो सकता है कि हम आगे न बढ़ सकें। ३०-४० करोड़ जो पिछली अब तक रेवेन्यू इनकम और रिसीट्स हैं, उनको लेकर इस साल कुछ न करें, प्लान्स में भी कमी करें या कामों को रोक दें तो तीन-चार करोड़ के लगभग सरप्लस रह सकता है। लेकिन हमारा इकोनोमिक डेवलपमेन्ट रुक जायेगा, हमारा विकास रुक जायेगा, हमारे प्लान्स, यदि यह हो तो उनमें कोई खर्चा नहीं होगा; तो स्टेग्नेन्ट रह जावेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिये आवश्यकता यह रह जाती है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ायें, हमारे श्रोतों को आगे बढ़ायें, हमारे साधनों को बढ़ाते चले जायें और जो काम शुरू किया है उनको रोकने के बजाय हम उनको आगे बढाते चले जायें।

उपाध्यक्षजी, पंजाब जैसी जगह, जो आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न है, पंजाब आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है, सारे भारतवर्ष में, दिल्ली की छोटी स्टेट को छोड़ कर, पंजाब में पर-केपिटा इन्कम हाइयेस्ट है, उनको भी बहुत बडे टैक्सेशन में जाना पड़ा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश जो अधिक समृद्ध है हमसे, काफी विकासशील है उसको भी अधिक टैक्सेशन में जाना पडा है।

लैंड रेवेन्यू सेस की बात लें। हिन्दुस्तान के अन्दर यह न समझें कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ही इसके प्रोपोजल्स लेकर आयी है। किन्तु हिन्दुस्तान के अन्दर जो दूसरी स्टेटस हैं, केरल को लें, आन्ध्र को लें, मैसूर को लें, बंगाल को लें, उडीसा को लें, यू. पी. को लें, पंजाब को लें-करीब करीब सब जगह जहां तक

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

हमने जानकारी की है किसी न किसी प्रकार से किसानों से सेस के बारे में प्रावधान मौजूद है। राजस्थान में भी यही सोच कर कार्यवाही की गई तो उसको करने में जहां से रुपया प्राप्त हो सके थोड़ा थोडा करके प्राप्त किया जाय।

मैं साथ साथ आपसे यह भी निवेदन करूं हमको सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए, और इस दृष्टि को सामने रखते हुए कि पिछले दिनों बाजार में जिन्स के क्या भाव थे। १९६२ की फ़रवरी के अन्दर व्हीट के भाव ११७ थे, फ़रवरी ६३ में ९४ है, उसके बाद बार्ली १२१ था जो आज ८४ है, जवार १३६ था आज ११३ है, मेज़ ७७ था आज ६५ है व पल्सेज़ १०६ था आज ९६ है। हम किसी बात पर कोई एडीशनल इफ़ैक्ट दे रहे हों, इस प्रश्न पर विचार करने की बात है, जब कि हम इस साल के बजट पर विचार करने के लिये इकट्ठे हुए हैं। दर असल में जो वज़न डाला जा रहा है वह उस हालत में जब कि भावों का ट्रेन्ड नीचा होता हुआ जा रहा है फिर भी हम फ़ुड ग्रेन्स के मामले में नहीं गये। आज के भावों का ट्रेन्ड आदि जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इन सारे प्रश्नों को इस भूमिका में देखें, विकास की दृष्टि से आगे विचार करें। किन्हीं भावनाओं के वश किन्हीं प्रश्नों का हल नहीं हो सकता, हमें इन प्रश्नों के बारे में और इन समस्याओं के हल करने में तथ्यों को आगे देखकर बढ़ना है। इन चीजों पर इन हालतों पर विचार करते हुए चलें और झिझक कर रुक जायें तो यह निश्चित मान कर चलिये कि इसका असर आज नहीं पड़ेगा तो आगे आने वाले प्लान पर पड़ेगा और फिर उसका असर व्यापक होगा।

नॉन-टैक्स रेवेन्यू के लिये कहा गया कि अमुक अमुक काम हाथ में लें और उसके लिये यह सोच रखा है, जैसे हमने ट्रान्सपोर्ट के ज़रिये ज्यादा से ज्यादा इन्कम हो सकती है इस तरह से हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन सेट-अप किया और जो भी मीन्स उपलब्ध हो सकते हों लाइफ़ इन्शोरेन्स कोर्पोरेशन से हो सकते हैं या अन्य ज़रिये से हो सकते हैं, जितनी भी इन्कम कर सकते हैं–करने का प्रयास करेंगे।

मिनरल्स में जो गुंजाइश है उसमें भी बढ़ोत्तरी करने का विचार किया है। नॉन–रेवेन्यू में इन्क्रीज़ हमारी इनवेस्टमेन्ट की केपेसिटी आदि बातें हमारे ऑर्गेनाइज़रों पर और और चीजों पर निर्भर करता है। किस चीज पर कितना निर्भर करेंगे उन सब प्रश्नों को दोहराने के साथ साथ सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। हमारे वित्त मंत्री इस संबन्ध में फाइनल जवाब देंगे तो मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा, ताकि आगे के लिये हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सफल कर सकें, इसके लिये सभी सदस्यों का सहयोग पूर्ण रूप से हमें मिलेगा।

**श्री भैरोंसिंह** : दो प्रश्न इस तरह के रह गये हैं जिन पर मुख्य मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे; एक तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में और दूसरा आर.ए.सी के बारे में इनके लिये उन्होंने भारत सरकार से क्या कुछ निवेदन किया है ?

# Page No.90



**श्री मोहनलाल सुखाडिया** : आर. ए. सी. के बारे में हमने अपनी तरफ से भारत सरकार को अभी जो खास तौर से बटालियन्स रेज की हैं उनसे निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार की फाइनेन्शियल पोजीशन को देखते हुए इसमें भारत सरकार सहयोग दे ।

फर्टिलाइजर फैक्ट्री के बारे में मैं स्वयं मानता हूं कि यह अत्यंत आवश्यक प्रश्न है । मैं इस संबन्ध में भारत सरकार के मंत्री और दूसरों से मिला हूँ और इस बात पर जोर दिया है कि या तो इसका जल्दी से जल्दी फैसला हो, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो। हमने शुरू से कहा था कि हम राजस्थान में फर्टिलाइजर फैक्ट्री चाहते हैं भारत सरकार पब्लिक सैक्टर में लेकर इस जिम्मेदारी को पूरा करें ।

**राजा श्री मानसिंह** : Would the Chief Minister enlighten us what the Rajasthan Government is doing for defence efforts ?

**श्री मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री) : It has been done.

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही दिनांक १८ मार्च, १९६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५.१५ बजे दिनांक १८ मार्च, १९६३ को म.पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

**संक्षिप्त विवरण**

**(शनिवार, दिनांक १६ मार्च, १९६३)**

**१. शोक प्रगट**

स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास, भूत-पूर्व मुख्य मंत्री, राजस्थान एवं सदस्य, राज्य सभा के निधन पर सदन के नेता श्री मोहन लाल सुखाडिया, विरोधी दल के नेता महा-रावल श्री लक्ष्मणसिंह एवं श्री भैरोंसिंह, श्री मुकुट बिहारी लाल, श्री हरदत्तसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल, प्रो० केदारनाथ, श्री दुर्गालाल बाढदार ने शोक प्रकट करते हुए स्वर्गीय श्री व्यासजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उपाध्यक्ष राव श्री नारायण सिंह मसूदा ने भी सदन द्वारा प्रकट की गई भावनाओं में स्वयं की भावनाएं सम्मिलित करते हुए समवेदना प्रकट की। तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की गई तथा सदन की कार्यवाही ३० मिनिट के लिये स्थगित की गई।

(विधान सभा के उपाध्यक्ष राव श्री नारायण सिंह मसूदा की अध्यक्षता में सभा की कार्य-वाही पुनः १२.५ मध्यान्होत्तर से आरम्भ हुई)

**२. आय-व्ययक १९६३-६४**

**प्रथम अवस्था-सामान्य वाद-विवाद**

आय-व्ययक, १९६३-६४ पर आज वाद-विवाद का अन्तिम दिन था। बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री ज्वाला प्रसाद
(२) श्री हरदत्त सिंह
(३) श्री घासीराम यादव
(४) श्री उमराव सिंह
(५) श्री शीशराम ओला
(६) श्री मोहन राज
(७) श्री विजयसिंह झाला
(८) कुमारी उमा माथुर
(९) श्री मथुरेश बिहारी
(१०) श्री शंकर लाल
(११) श्री भगराज चौधरी
(१२) श्री बालूराम चौधरी
(१३) श्री हरिप्रसाद शर्मा
(१४) श्री मानिक चन्द सुराना

सरकार की ओर से श्री मोहन लाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री, ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ५ बजकर १५ मिनट पर सोमवार दिनांक १८ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**सोमवार, दिनांक १८ मार्च १९६३ की कार्य-सूची।**

१. विभिन्न समितियों के प्रदिवेदनों का उपस्थापन

२. आय-व्ययक, १९६३-६४ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

३. मांगों पर मत-दान:

(१) मांग संख्या १४, वैज्ञानिक विभाग।

(२) मांग संख्या २१, उद्योग।

(३) मांग संख्या ४२, औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत।

## शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक १६ मार्च, १९६३)

| स्कम्भ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| २६३३ | १ | ६१६३ | १९६३ |
| २६३६ | अन्तिम | सकेंग। | सकेंगे |
| २६३७ | अन्तिम से ४ | भागरा | भांगड़ा |
| २६३९ | ,, से ७ | दुखः | दुःख |
| २६४५ | १० | दिगू | दिग् |
| २६४९ से २८१२ तक | शीर्षक | अग्रेतर | अग्रेतर |
| २६६३ | २० | महारावल श्री लक्षमणसिंह | महारावल श्री लक्ष्मणसिंह |
| २६६४ | अन्तिम से ५ | रिजोलूशन | रिजोल्यूशन |
| २६६५ से २६६८ | शीर्षक | १६ माच | १६ मार्च |
| २६६५ | अन्तिम से ५ | Order | Order ! |
| २६६६ | शीर्षक | प – मार्च | पर–१६ मार्च, |
| ,, | ११ | लेता | लेते |
| २६७४ | ८ | सहानुभति | सहानुभूति |
| २६७९ | शीर्षक | माच | मार्च |
| २६९८ | ८ | श्री उमरासिह ढाबरिया | श्री उमरावसिंह ढाबरिया |
| २६९९ | १८ | कैपसीटी | कैपेसिटी |
| २७०० | १ | शैतानासह | शैतानसिंह |
| २७०४ | १० | सा | सोढ़े |
| ,, | ११ | ह | हैं |
| २७०८ | २० | हो | हो |
| २७३३ | अन्तिम से ६ | श्री किशन बठढ | श्री किशनसिंह बाटड़ |
| २७३७ | २२ | योगेन्दनाथ हांडा | श्री योगेन्द्रनाथ हांडा |
| ,, | २४ | भ गराज चौधरी | श्री भगराज चौधरी |
| ,, | २५ | ट | भ्रष्ट |
| ,, | २६ | क | एक |
| २७३८ | २२ | श्री ज्वाला साद शर्मा | श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २७३९ | ५ | मौजद | मौजूद हैं |
| ,, | ६ | श्री मगराज चोधरी | श्री भगराज चौधरी : |
| २७४० | अन्तिम से २ | ग्रॉर्डर | ग्रॉर्डर |
| ,, | ,, ,, ३ | मं | मेरा |
| २७४१ | १ | कबिनट | केबिनेट |
| ,, | ५ | ग्राचार्य | ग्राचार्य : |
| ,, | १२ | ग्राचर्य : | ग्राचार्य : |
| ,, | अन्तिम से ७ | महारावल श्री लवमर्णसिह् | महारावल श्री लक्ष्मर्णसिह् |
| २७४३ | ,, ,, ८ | ग्रजमर | ग्रजमेर |
| २७४५ | ६ | श्री भगराज : | श्री भगराज चौधरी : |
| ,, | अन्तिम से २ | Nadam | Madam |
| २७४७ | १ | श्री सभापती | श्री सभापति |
| ,, | ५ | श्री भगराज | श्री भगराज चौधरी |
| २७५१ | शीर्ष | (श्री बालूरास चौधरी) | (श्री बालूराम चौधरी) |
| २७५४ | १८ | डा० हरीप्रसाद शर्मा | डा० हरिप्रसाद शर्मा |
| २६५६ | १६ | डा० हरिप्रसाद | डा० हरिप्रसाद शर्मा |
| २७६३ | ६ | ,, | ,, |
| २७६५ से २७७७ तक | शीर्ष | (श्री मानिकचन्द सुराना) | (श्री मानिकचन्द सुराणा) |
| २७६५ | ६ | कहंगा | कहूंगा |
| २७७१ | अन्तिम से ३ | एक्सपेन्टीचर | एक्सपेन्डीचर |
| २७७५ | ६ | नशनल इनकम | नेशनल इन्कम |
| २७८२ | अन्तिम | स्टेट र | स्टेट पर |
| २७८३ | १६ | मालम | मालूम |
| ,, | २० | गय | गये |
| ,, | अन्तिम से ५ | डवलपमेंन्ट | डेवलपमेन्ट |
| २७८४ | ,, ,, ६ | डवलप | डेवलप |
| २७८६ | २ | म | में |
| २७८७ | अन्तिम से ७ | में | में |
| ,, | १ | इसके है। | है |
| २७८६ | अन्तिम से ६ | गवर्तमेन्ट | गवर्नमेन्ट |
| २७६१ | अन्तिम | ोती | होती |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २७९४ | ६ | श्री रामानन्द अ ्रवाल | श्री रामानन्द अग्रवाल |
| ,, | २३ | सुराना | सुराणा |
| २७९५ | १९ | इन्क्‌म | इन्कम |
| २७९६ | २० | रहन | रहने |
| २८१२ | १२ | तदन्तर | तदनन्तर |
| २८१४ | १३ | सुराना | सुराणा |
| २८१३ से २८१४ तक | शीर्षक | आय-व्ययक १९६३-६४ पर– १६ मार्च, १९६३–अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद | संक्षिप्त-विवरण-१६ मार्च १९६३–संक्षिप्त-विवरण |